असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

02 दिसम्बर, 2021

सप्तदश विधान सभा 02 दिसम्बर, 2021 ई0

चतुर्थ सत्र वृहस्पतिवार, तिथि 11 अग्रहायण, 1943(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : ये बैनर-पोस्टर सब हटवा दें ।

(व्यवधान)

अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । आपलोग अपने-अपने स्थान पर जाएं । श्री ललित कुमार यादव, पूरक पूछिए । माननीय सदस्यगण, अपने-अपने स्थान पर जाएं । शांति, अब सुनिए माननीय महबूब जी, आपकी चिंता है । माननीय सदस्य अजीतजी, सुनियेगा तब न।

(व्यवधान)

अभी खाद्य के मामले में ध्यानाकर्षण आया है ? कौन दिया है ।

(व्यवधान)

महबूब जी, आप अपने स्थान पर जाकर बोलेंगे तब आपकी बात प्रोसीडिंग में जायेगी ऐसे कोई बात जायेगी नहीं । आप अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान)

किन्हीं की आवाज ही नहीं आ रही है, अब अपने स्थान पर चले जाइये । आपकी बात ध्यान में आ गयी । महबूब जी, अपने स्थान पर चले जाइये ।

(व्यवधान)

आपके विषय को सरकार भी सुन रही है और अपने स्थान पर जाइयेगा तब सुनेंगे । वहां से प्रोसीडिंग में कोई बात नहीं जा रही है ।

(व्यवधान)

ठीक है । अब चलिये हो गया । आपकी आवाज तो पूरा सदन सुनता है, चलिए । जाइये अपने स्थान पर समय आप ही का बर्बाद हो रहा है । सुदामा जी, आप कहां सत्यदेव जी के पीछे आ गये ।

(व्यवधान)

बिहार में बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था खत्म हो गयी है । अब वह व्यवस्था नहीं रही । चलिये अपने-अपने स्थान पर आप । आपकी बात सुनेंगे अपने स्थान पर जाइयेगा तब न। अपने स्थान पर जाइये न, अपने स्थान पर जाकर बोलिये । स्थान पर जाकर बोलियेगा तब न सुनेंगे ऐसे कोई सुनेगा । जाइये सुदामा जी, अपने स्थान पर जाइये । समय बर्बाद हो रहा है देखिए पांच मिनट चला गया दो क्वेश्चन निकल जाता ।

(व्यवधान)

सत्यदेव जी, अपने स्थान पर जाइये न । ये दोनों आदमी खड़े हैं दोनों का प्रश्न है । महबूब जी, अब हो गया, अपने स्थान पर जाइये, समय पर सब विषय का संज्ञान लेंगे । अपने स्थान पर जाइये समय पर नियम के हिसाब से सबका संज्ञान हम लेते हैं ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, कम से कम कार्यस्थगन पढ़ने का.....

अध्यक्ष : अभी आपका प्रश्न है नहीं पढ़ियेगा । ललित कुमार यादव जी, यह दूसरी बार बोल रहे हैं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के मा0 सदस्यगण अपनी सीट पर चले गये)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हाऊस आर्डर में था नहीं ।

अध्यक्ष : अब तो सदन आर्डर में है ।

श्री ललित कुमार यादव : हम तो खड़े हैं महोदय ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-12(श्री ललित कुमार यादव) क्षेत्र सं0-82 दरभंगा ग्रामीण

श्री मुकेश सहनी,मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है । बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के तहत राज्य के सभी 534 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समति का निबंधन सहकारिता विभाग को कराना है । वर्तमान में प्राप्त सूचना के अनुसार 471 प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियां निबंधित है । समितियों में नये सदस्य बनाने हेतु उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है । विभाग के द्वारा सघन अभियान चलाकर सभी निबंधित प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों में सदस्यों की संख्या बढ़ाये जाने का अनुरोध निबंधन, सहयोग समितियां, बिहार से किया गया है । सहकारिता विभाग के द्वारा एन0आइ0सी0 के माध्यम से ऑनलाइन सदस्यता की कार्रवाई किये जाने की सूचना है । पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा इस अभियान को सफलतापूर्वक लागू कराया जाएगा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब है कि सहकारिता विभाग एन0आइ0सी0 के माध्यम से ऑनलाइन की कार्रवाई की जाने की सूचना । हम कह रहे हैं

कि मत्स्य विभाग मूल विभाग है । मेरा मात्र दो पूरक प्रश्न है । एक- जो मछुआरे हैं उनको सदस्य नहीं बनाया जा रहा है । जो मछुआरा सोसाइटी के सचिव हैं उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है जिनको मन होता है बनाते हैं जिनको मन नहीं होता है नहीं बनाते हैं तो सभी मछुआरा को सदस्य बनाया जाय । एक मेरा यह अनुरोध है और दूसरा है....

अध्यक्ष : सलाह है, पूरक क्या है ?

श्री ललित कुमार यादव : सभी मछुआरा को सदस्य नहीं बनाया जाता है जिनको सचिव चाहते हैं बनाते हैं जिनको नहीं चाहते हैं, नहीं बनाते हैं । ये व्यापक रूप से जो भी मछुआरा सदस्य बनना चाहते हैं तो मछुआरा विभाग मूल विभाग है तो वे दायित्व लें कि उन सभी लोगों को सदस्य बनायें । दूसरा महोदय, एक सदर प्रखंड में जो 500 से उपर तालाब है कम से कम 20 आदमी मात्र उस 500 पोखर के तालाब से अर्जन करते हैं, कमाई करते हैं जो सदस्य हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सदर प्रखंड के जो सचिव हैं उनके द्वारा जो अनियमितता की जा रही है उसकी कोई उच्च स्तरीय जॉच कराना चाहते हैं या नहीं ?

अध्यक्ष : यह सहकारिता विभाग को ट्रांस्फर हुआ है ।

श्री मुकेश सहनी,मंत्री : महोदय, यह मेरे विभाग में आ गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मत्स्यपालन विभाग से जवाब आ गया है ।

श्री मुकेश सहनी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मत्स्यजीवी सहयोग समिति की जो प्रक्रिया है वह मंत्री सदस्य के बीच में सदस्य बनाने का प्रावधान है, लेकिन हमलोग आनेवाले समय में एन0आइ0सी0 को बोल दिया गया है कि ऑनलाइन प्रक्रिया लाया जाय ताकि राज्य में जितने भी मछुआरा हैं ऑनलाइन सदस्य बन जाएं । इसके लिए हमलोग प्रक्रिया में हैं और शीघ्र ही उसपर कार्रवाई कर रहे हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : दूसरा पूरक भी है ।

श्री मुकेश सहनी,मंत्री : दूसरा सवाल आपका हटकर है, लेकिन तो भी जवाब हम दे रहे हैं । आपने जिस दरभंगा मत्स्यजीवी सहयोग समिति का जिक्र किया है उसमें औलरेडी कार्रवाई हो चुकी है । छः महीने के लिए मंत्री को सस्पेंड कर दिया गया है और आनेवाले समय में जो भी वहां की प्रक्रिया सहकारिता विभाग के द्वारा आम सभा करके सारे तालाब की बंदोबस्ती आम जनता के बीच में किया जायेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम कहे कि दरभंगा सदर तो इन्होंने भी माना कि वहां गड़बड़ी हुई है उसको छः महीना के लिए निलंबित कर दिया गया है । हम कह रहे हैं माननीय

मंत्री जी वहां सदर प्रखंड में व्यापक गड़बड़ी हुई है । आप उसकी एक उच्च स्तरीय जॉच कराना चाहते हैं या नहीं ?

श्री मुकेश सहनी,मंत्री : जॉच करायी गयी है और सहाकारिता विभाग का जो नियम है कि जो भी सोसाइटी चलाना है राज्य सरकार के देखरेख में ही चलाना है और उनको ही डिसिजन लेना है । उधर हमें पता चला कि गड़बड़ी हुई है उसके लिए जॉच हुआ और कार्रवाई भी हो चुकी है और अगले साल 2022 में फिर से चुनाव होना है तो जब तक चुनाव होगा तब तक वह मनोनीत ही रहनेवाला है । फिर नये सिरे से प्रक्रिया होगी चुनाव होगा फिर नये सदस्य जीतकर आयेंगे और नये सिरे से जितने भी तालाब हैं उनकी बंदोबस्ती करेंगे ।

अध्यक्ष : आपका तीन पूरक हो गया ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, उसी पूरक का जवाब चाहिए । हम कह रहे हैं कि तब तक बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई ये किससे जॉच कराना चाहते हैं । ये कह रहे हैं कि हम पूर्व में जॉच कराये हैं हम कह रहे हैं कि आज सदन के माध्यम से जो प्रश्न आया है आप किससे उच्च स्तरीय जॉच कराना चाहते हैं चूंकि व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी है ।

अध्यक्ष : इन्होंने तो कहा कि हम जॉच करा लिये हैं, लेकिन आप जानना क्या चाहते हैं ?

श्री ललित कुमार यादव : हम तो कह रहे हैं कि व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है किससे जॉच कराना चाहते हैं ?

श्री मुकेश सहनी,मंत्री : कहीं ऐसी गड़बड़ी नहीं है एक तालाब की शिकायत मिली थी एक महीना पूर्व ही शिकायत मिला था उसमें जॉच हुआ और उसको निलंबित कर दिया गया है। एक महीना पहले ही जॉच हुआ और उनको छः महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है ।

श्री ललित कुमार यादव : मैं कह रहा हूँ और माननीय मंत्री जी भी स्वीकार कर रहे हैं, गड़बड़ी हुई है, 500 से उपर तालाब.....

अध्यक्ष : आप नाम बताइये न, नाम दे दीजिए ।

श्री मुकेश सहनी,मंत्री : कहीं गड़बड़ी नहीं है, सिर्फ एक तालाब का है ।

श्री ललित कुमार यादव : आप जॉच करा लीजिए ।

श्री मुकेश सहनी,मंत्री : जॉच कराये हैं तब न कार्रवाई हुई है । सन ऑफ मल्लाह इस विभाग में बैठा है पूरे बिहार में एक-एक मछुआरा की शिकायत सुनी जा रही है, आप टेंशन मत लीजिए।

श्री ललित कुमार यादव : जॉच करा दें जिससे भी इसमें जॉच कराना है ।

अध्यक्ष : आप लिखकर दे देंगे मंत्री जी देखवा लेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : क्यों लिखकर देंगे । ये मेरे मूल प्रश्न में है हम कह रहे हैं कि किससे ये जॉच करा देंगे ? जॉच करा दें बस हो गया ।

श्री मुकेश सहनी,मंत्री : जॉच हो गया न ।

अध्यक्ष : ये कह रहे हैं जॉच हो गया, आप कह रहे हैं जॉच करा दीजिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हमलोग प्रश्न के आलोक में कह रहे हैं जॉच के लिए और ये कह रहे हैं कि पूर्व में ही जॉच कराये हैं ।

श्री मुकेश सहनी,मंत्री : एक महीना पहले ही जॉच हुआ है ।

श्री ललित कुमार यादव : हम कह रहे हैं कि 500 से उपर तालाब को एक ही व्यक्ति ने संचालित करके अवैध कमाई की है और आम मछुआरे को इसका लाभ नहीं मिला है आप 500 पोखर का जॉच सदर प्रखंड में कराना चाहते हैं कि नहीं ?

टर्न-2/पुलकित/02.12.2021

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : आप लिखकर दें, कहां-कहां जांच करानी है, सब जगह जांच करा देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संज्ञान में ले लीजियेगा ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उसको निलम्बित कर दिया गया । एक महीना पहले निलम्बित कर दिया गया और वहां प्रशासक बहाल कर दिया गया प्रखण्ड, मत्स्य पदाधिकारी को । लेकिन अभी तक जिसको प्रशासक बहाल किया गया उसको हैंड ओवर नहीं हुआ तो क्या माननीय मंत्री जी 24 घंटे के अंदर वहां के सचिव को जिसको निलम्बित कर दिया गया, निलम्बित करके प्रशासक बहाल कर दिया गया, उसको सारी कार्रवाई करने का अधिकार देंगे। जिसको प्रशासक बहाल किया गया उसको अभी तक कुछ हैंड ओवर नहीं हुआ है प्रशासक के रूप में ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : ये ऑलरेडी अधिकार उनको प्राप्त हो चुका है और किसी कारण अगर विलम्ब हुआ है तो आप 24 घंटे बोले हैं, शीघ्र ही अभी हम यहां से निकलेंगे और अभी बात कर लेंगे ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था पर एक प्रश्न है । इस हाउस के आप कस्टोडियन हैं । इसलिए मैं आपके समक्ष इसको लाना चाहता हूं । आज मैं हाउस में पांच मिनट विलम्ब से इसलिए पहुंचा कि विधान सभा परिसर के अंदर हमारी गाड़ी को रोक दिया गया । एस0पी0 और डी0एम0 की गाड़ी आ रही थी और वह गाड़ी भी उसी गेट से आती है जिस गेट से सी0एम0 इस परिसर में आते हैं । उस गेट से एस0पी0, डी0एम0 की गाड़ी आ रही थी । ये चूंकि परिसर के अंदर की बात है इसलिए मैं इसको यहां रख रहा हूं बाहर तो मैं खुद सक्षम था ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये । पहले हमको कहने दीजिये । पहले हमको कह लेने दीजिये फिर आप बताइयेगा और हमारी गाड़ी को रोका गया और एस0पी0, डी0एम0 के लिए रोका गया । मुझे लगा कि शायद सी0एम0 साहब आ रहे हैं या सभापति या अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं लेकिन एस0पी0, डी0एम0 के लिए हमारी गाड़ी को रोका गया । आप आश्वासन दीजिये आसन से कि दोषी अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करके उन पर कार्रवाई की जायेगी । अदरवाइज, इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को अगर अपमानित किया जायेगा तो यह कहीं न कहीं उचित नहीं है । इस पर मुझे आसन का आश्वासन चाहिए । मुझे आश्वासन चाहिए आसन का, आप कस्टोडियन हैं...

(व्यवधान)

मुझे क्यों रोका गया है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बैठ जाइये ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : ये आसन तय करे कि डी0एम0 बड़ा, एस0पी0 बड़ा या सरकार बड़ी । ये आसन तय करे आज ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बैठ जाइये ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : मैं तब तक नहीं बैठूंगा । ये आसन तय करे आज एस0पी0 बड़ा, डी0एम0 बड़ा कि मंत्री बड़ा या सरकार बड़ी । तय करें, मैं नहीं बैठूंगा....

(व्यवधान)

तय करके इसको आज, उसके लिए मेरी गाड़ी रोकी गयी है और मैं हाउस में लेट आया हूं । मैं हाउस में इसलिए लेट आया हूं कि मेरी गाड़ी रोकी गयी है ।

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

मैं इसलिए.....

(व्यवधान)

मैं जनता का प्रतिनिधि हूं और मुझे रोका गया है । मैं हाउस में इस वजह से लेट आया हूं ।

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(एम0एल0), कांग्रेस, राजद व विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य वेल में आ गये।)

अध्यक्ष : ये क्या तमाशा है ?

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आप बैठिये । आसन की बात को सुनिये । बैठिये, एक चीज, महबूब जी सुनिये । अब सुनियेगा तब न, अब सुनिये विधायकों की प्रतिष्ठा, सदन गंभीर है । बैठ जाइये पहले, अपनी-अपनी जगह पर बैठिये ।

(व्यवधान)

आप बैठिये । बैठियेगा तब न । अब अपने-अपने स्थान पर बैठिये । संसदीय कार्य मंत्री बोलेंगे । बैठिये । चलिये अब संसदीय कार्य मंत्री, आप लोगों से आग्रह है, देखिये सदन को, अब सुनिये । माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी की भावना से हम सब गंभीर हैं । एक मिनट पहले बैठ जाइये । देखिये, सदन में आप सभी के भाव प्रकट हो रहे हैं और सबकी भावना को मैं समझ रहा हूं बैठिये, अच्छी बात और अच्छा नियमन जायेगा, जाइये सब अपनी जगह पर ।

(व्यवधान)

आप अपने स्थान पर जायेंगे तभी न बोलेंगे । तो खड़े रहिये हमलोग ऐसे ही बैठते हैं । अपने स्थान पर बैठ जाइये, पहले स्थान पर जाइये ।

संसदीय कार्य मंत्री जी । आपलोग अपने स्थान पर जाइये, सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री जी बोलते हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ये लोग पहले बैठ जायं ।

अध्यक्ष : अपने-अपने स्थान पर जायं तभी तो सरकार बोलेगी ।

(व्यवधान)

आप स्थान पर जाइये । स्थान पर जाइयेगा तभी न बोलें । आर्डर में जब सदन रहेगा तभी सरकार बोलेगी । बैठ जाइये, बैठ जाइये, आप नहीं चाहते हैं, आप सभी नहीं चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसपर गंभीरता से सरकार जवाब दें। आपलोग नहीं चाहते हैं कि जवाब सरकार दे । अगर चाहते हैं कि सदन की गरिमा बढ़े, सदस्यों का मान-सम्मान बढ़े तो अपने स्थान को ग्रहण करिये ।

(व्यवधान)

नहीं । आप अपने स्थान को ग्रहण करियेगा तभी सरकार जवाब देगी ।

श्री विजय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : ऐसे में क्या बोलेंगे । आपलोग अपने स्थान पर जाइये, सरकार जवाब देगी ।

श्री विजय कुमार चौधरी : महोदय, लगता है कि...

अध्यक्ष : अपने-अपने स्थान पर जाइये । सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है....

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी : महोदय, लगता है....

अध्यक्ष : सभी अपने स्थान पर जाइये । आप पुराने सदस्य हैं, संसदीय कार्य मंत्री को सुनिये तो पहले, अपने स्थान पर जाइये । सब लोग बैठिये, आप जाइये, सब लोग बैठिये । सुदय जी, मंडल जी जाइये । आप लोगों की बात को तो हम सबसे पहले प्राथमिकता में लेते हैं। चलिये बैठिये, विधायकों की प्रतिष्ठा को उनकी मर्यादा को तो हम सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं । आप जाइये अपने स्थान पर ।

(व्यवधान)

बेलगाम किसी को नहीं होने दिया जायेगा ये ध्यान में रखिये ।

(इस अवसर पर सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये)

महबूब जी बैठ जाइये-बैठ जाइये, शांति से । अब संसदीय कार्य मंत्री जी.....

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : आप विपक्ष के मुख्य सचेतक हैं, आपकी बात को सुनेंगे, जब आपकी बात से संतुष्ट नहीं होंगे तब न आपके विपक्ष के नेता बोलेंगे । बैठ जाइये ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये । आप क्या चाहते हैं कि सदन में सदस्यों के सम्मान की बात को गंभीरता से लेंगे या हंगामा करके हम अवसर देंगे । चलिये सभी शांति से सुनें, संसदीय कार्य मंत्री जी ।

टर्न-3/अभिनीत/02.12.2021

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में माननीय मंत्री श्री जिवेश कुमार जी ने बड़ी ही आहत भावना से आज उनके साथ सदन परिसर में जो बातें हुई हैं उसका जिक्र किया है जिसे आसन ने भी सुना है और सदन के सारे माननीय सदस्यों ने भी सुना है । जो बातें उन्होंने बताई हैं वास्तव में एक गंभीर मसला है । सदन में आते समय किसी मंत्री क्या, सरकार तो चाहती है या सरकार की मंशा है, सरकार का स्पष्ट निदेश है और महोदय, आसन इसका सबसे बड़ा साक्षी है । जितनी बार, चाहे दलीय नेताओं की बैठकें हुई हैं या वरीय पदाधिकारियों की बैठक जो सत्र से पहले महोदय आप बुलाते हैं उसमें सरकार की तरफ से मैं भी होता हूं आप ही की अध्यक्षता में जो बैठकें होती हैं जिसमें राज्य के शीर्षस्थ अधिकारी रहते हैं, मुख्य सचिव रहते हैं, पुलिस महानिदेशक रहते हैं, उनलोगों की मौजूदगी में हमलोगों ने आपके समक्ष सरकार की मंशा बार-बार दोहराई है कि मंत्री तो खुद सरकार के अंग होते हैं । वैसे सभी माननीय विधायक भी सत्ता पक्ष के

हों, विपक्ष के हों सभी सरकार के ही अंग हैं इसी सदन में लिखा है । हम लोग सरकार की तरफ से किसी माननीय सदस्य की भी भावना आहत हो ऐसी स्थिति नहीं होने देना चाहते हैं । आपको स्मरण होगा महोदय कि जांच-पड़ताल के क्रम में भी आपके समक्ष हमलोगों ने बार-बार सरकार की तरफ से ये बातें उठाई हैं कि गेट पर जो जांच होती है उसमें भी माननीय सदस्यों के साथ बा-अदब-अदब के साथ ही कोई बात भी पूछी जाय । उनको जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से उनके बारे में जांच या कोई जानकारी लेनी है वह ली जाय । महोदय, जब सरकार की मंशा किसी विधायक की भावना को भी आहत करने की नहीं होती है तो मंत्री तो सरकार के ही अंग होते हैं...

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, ये क्या कह रहे....

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अभी बात...

अध्यक्ष : बात को रखने दीजिए । माननीय सदस्यगण, देखिए अब ये बात रख रहे हैं, इसके बाद आपकी बात को भी सुनेंगे । एक बार बैठ जाइये, सुन लीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : एक मिनट, सुदय जी, महबूब जी इनकी बात सुनिए तब न आपकी बात सुनेंगे । ये बोलेंगे आप हल्ला करेंगे, आप बोलेंगे ये हल्ला करेंगे कैसे चलेगा ? ऐसे चलेगा ? सुन लीजिए एक मिनट । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कम शब्दों में बतावें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माननीय मंत्री ने भी कहा है कि यह आपके परिसीमा की बात है और उन्होंने आपका संरक्षण मांगा है । हम सरकार की तरफ से आसन को और सदन को आश्वस्त करते हैं कि आप अपने स्तर से भी दिखवा लीजिए, सरकार भी दिखवायेगी और जिस पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार या व्यवहार माननीय मंत्री के साथ किया गया होगा उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए, अब बैठिए । एक-एक करके जिनको अनुमति देंगे वही बोलेंगे । सभी लोग बैठिए, एक आदमी को अनुमति देंगे । महबूब जी बैठिए ।

ललित जी, एक चीज बता देते हैं सुन लीजिए, सभी सदस्यों को हमने पहले दिन बोला था, फर्स्ट डे कि किसी भी माननीय सदस्य का अपमान सदन का अपमान माना जायेगा ।

(व्यवधान)

अब बैठे-बैठे बोलिएगा तो फिर खड़ा करना पड़ेगा आपको । किसी भी सदस्य का अपमान सदन का अपमान है और सदन का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है ।

प्रहलाद जी, बैठे-बैठे, आप इतने वरिष्ठ विधायक हैं । शालीनता सदन की रहनी चाहिये । इसी कारण से नहीं सुनता है, आप जैसे लोगों के कारण ही सदन की गरिमा गिर रही है । आप ही जैसे लोगों के कारण, जो सदन का सम्मान नहीं रखते हैं तो दारोगा से सम्मान पाने की कैसे उम्मीद करते हैं । सदन का सम्मान यदि आप रखेंगे तो आप सब के सहयोग से सदन की इतनी गरिमा है कि किसी की बिसात नहीं है कि सदन के सामने वह खड़ा हो सके ।

(व्यवधान)

बैठिए, क्या तमाशा है साहब ! ललित जी, आप बोलिए कुछ कहना चाह रहे हैं और शालीनता के साथ नियमानुसार बोलिए कि क्या करना है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सरकार के मंत्री जब इस तरह का वक्तव्य सदन में दिए हैं तो इसके बाद और क्या बचता है । अविलंब आसन से निदेश हो कि जो पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई मंत्री के साथ किए हैं उनको निलंबन करने का, उन पर कार्रवाई करने की आप आसन से घोषणा कीजिए हमलोग यही सुनना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी से हमने पूछा कि कौन हैं, तो इन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस । सदन की एक कमेटी, आज हम बैठ रहे हैं, दलीय नेताओं को हमने कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में बुलाया है और बैठ कर, वह समिति जांच करके जिसको अनुशंसित करेगी उस पर कार्रवाई करेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नाम आप बता सकते हैं कि कौन सी पुलिस है, कौन सा पदाधिकारी है ? ठीक है, सुन लीजिए जो ड्यूटी में होगा उस पर कार्रवाई होगी । ललित जी, जो ड्यूटी में होगा, जिसने ऐसा व्यवहार किया है जानकारी प्राप्त कर के कार्रवाई की जायेगी । मंत्री जी, एक मिनट बैठ जाइये । हां बोलिए ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, यह जो व्यवस्था, कुव्यवस्था है इसके लिए सिर्फ कोई एक सिपाही जिम्मेदार नहीं हो सकता है । एस0पी0 के यहां से जो निर्देश आता है उसी निर्देश के

आधार पर ही ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं । डी0एम0, एस0पी0 का खौफ इस तरह से है कि बलि चढ़ा दीजिए एक सिपाही को लेकिन जो व्यवस्था बनी हुई है वह बिल्कुल ही इस ओर ले जाती है जो घटना आज घटी है । इसलिए महोदय, विधायिका की डिग्निटी को, विधायिका के महत्व को मजबूती से बरकरार रखने के लिए हम माननीय अध्यक्ष जी से इस सदन की तरफ से एक मजबूत और एक कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को रखते हैं ।

अध्यक्ष : क्या कार्रवाई ? कार्रवाई बताइये, क्या कार्रवाई ?

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, प्रोटोकॉल के अंदर...

अध्यक्ष : जांच करके या बिना जांचे ही ?

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, यह पहली घटना नहीं है । आये दिन जिलों में, थानों पर आस-पास जो घटना होती है उसको आप देख सकते हैं, पता भी होगा कि किस तरह अपमान करने का मौका खोजा जाता है । महोदय, जब यहां कड़ी कार्रवाई होगी तो इसका मैसेज पूरे बिहार के पदाधिकारियों को और स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं कि कार्रवाई सीधे-सीधे बड़े पदाधिकारियों सहित जो भी जिम्मेवार हैं उन पर होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा अपमान बिहार के लिए और क्या हो सकता है कि आपने खुद कहा कि यह सदन का अपमान है । एक मंत्री जो बिहार सरकार में हैं उन्होंने अभी खुद कहा है कि यहां आश्वासन चाहिए । डी0एम0, एस0पी0 को आने के लिए और इनको रोक दिया गया इससे बड़ा अपमान इस सदन का, इस बिहार का क्या हो सकता है ? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए जांच क्या होगी ? मंत्री महोदय ने साफ कहा है कि उनको आश्वासन आज चाहिए तो आपको देना चाहिए नहीं तो पूरा बिहार इसको माफ नहीं करेगा ।

अध्यक्ष : मैं पूरी तरह से देने को तैयार हूं लेकिन सदन शांति से सुने । हमने कहा कि आप माननीय सदस्य हैं, नियम के अनुसार ही व्यवस्था आप करेंगे तो लोग स्वीकार करेंगे ।

टर्न-4/हेमन्त/02.12.2021

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बयां किया उस बयान के बाद बचता क्या है ? वो सरकार हैं और सरकार स्वयं आसन से निवेदन कर रही है । यहां आसन सर्वोपरि है, सार्वभौम्य है सर । ऐसे भी अवसर आये हैं जब आसन से सरकार को निदेश

दिया गया है । महोदय, पूर्व में ऐसे अनेक अवसर आये हैं । जब हरि जी अध्यक्ष थे तब भी और उसके बाद भी आसन से निदेश हुआ है सरकार को कड़ी कार्रवाई करने के लिए। महोदय, ये मामला चूंकि सदन का है और आसन सर्वोपरि है, आसन निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और निदेश देने के लिए स्वतंत्र है । महोदय, इसकी जांच, किसी भी राज्य के किसी भी बड़े अधिकारी से एवन चीफ सेक्रेटरी से भी मंत्री का दर्जा और विधायक का दर्जा ऊपर है, महोदय । वारंट ऑफ प्रेसीडेंस में डिफाइन है कि विधायिका से और माननीय सदस्य से, मंत्री तो बड़ी चीज हैं, सरकार है, विधायक के ऊपर कोई अधिकारी नहीं होता है । अधिकारियों को रास्ता देने के लिए विधायकों को रोका जाना, मंत्री को रोका जाना गंभीर मामला है ।

अध्यक्ष : महबूब जी, एक मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री महबूब आलम : महोदय, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य एक विद्वान व्यक्ति हैं और मैं मानता हूं कि शब्द जाल से नीरस को सरस बनाने में उनको महारथ हासिल है । महोदय, बार-बार हमें ये नसीहत दी जाती है, बार-बार हमें हमारे अधिकार क्षेत्र, हमारे मान-सम्मान का ज्ञान दिया जाता है और सरकार की मंशा का बार-बार इजहार हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री करते हैं और आप भी करते हैं महोदय । मैं जो देखता हूं ऐसा माहौल बन गया है कि बिहार के विधायकों की तो पिटाई हो ही गयी, अब मुझे लगता है कि माननीय मंत्रियों की पिटाई बाकी है ।

अध्यक्ष : महबूब साहब, महबूब साहब..

श्री महबूब आलम : अभी हमारे..

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये, हो गया । आपकी भावना से सभी अवगत हो गये, अब सुन लीजिए ।

श्री महबूब आलम : सदन अगर सर्वोपरि है तो सदन से तात्कालिक कार्रवाई हो, सदन में घोषणा की जाय..

अध्यक्ष : सुनिये अब बैठ जाइये ।

श्री महबूब आलम : उसकी जांच-पड़ताल की जाय, महोदय । मंत्री लोग खुद बोल रहे हैं, उन्होंने खुद देखा है, वह खुद गवाह हैं । अगर मंत्री के बयान को सत्य नहीं माना जाय, तो मंत्री पर झूठा इल्जाम लगाने का तब इल्जाम लगता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री महबूब आलम : मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और सदन को यह आश्वस्त करना होगा कि सदन सर्वोपरि है कि नहीं । आज वह दिन आ गया है, महोदय...

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये, बैठ जाइये । बैठियेगा तब न सुनेंगे ।

अजय जी, अब तो पूरा समय चला गया, यह बात तो आ गयी ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि सदन के परिसर के अंदर जो माननीय मंत्री जी के साथ व्यवहार हुआ आप उससे आकलन कर सकते हैं कि बिहार के अंदर सदस्यों के साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा । इसीलिए जब आप यहां कार्रवाई करेंगे, आप सक्षम हैं, जब आप यहां सीधे कार्रवाई करेंगे...

अध्यक्ष : अब, सुन लीजिए माननीय सदस्य । 1 बजे दिन में...

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : हुजूर मुझे कुछ कहना है..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी...

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : मेरी बात सुन ली जाय...

अध्यक्ष : अभी आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

आप स्थिर रहिये । उप मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी..

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, मुझे बात पूरी कर लेने दी जाय ।

अध्यक्ष : हम देते हैं मौका ।

(व्यवधान)

सुनिये । सदन स्थगित किया जाता है । 11.45 बजे पूर्वा0 में फिर सदन की कार्यवाही शुरू होगी । सभी माननीय दलीय नेता एवं मंत्री हमारे कक्ष में बैठेंगे ।

टर्न-5/धिरेन्द्र/02.12.2021

स्थगन के बाद

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, हमलोग बैठे हैं अभी, सवा एक बजे पुनः हम सभी बैठेंगे और सरकार ने भी कहा है कि ऐसे लोगों पर तलब करके कार्रवाई होगी। हमलोग सभी बैठेंगे अभी । प्रश्नकाल, श्री ललित कुमार जी का हो गया, श्री भाई वीरेन्द्र जी ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र जी ।

(व्यवधान)

अब चलिये । इस तरह से सदन नहीं चलता है, सदन व्यवस्था से चलता है । श्री भाई वीरेन्द्र जी ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा आहत हुई है ।

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न तो समाप्त हुआ । तारांकित प्रश्न अब शुरू होगा । तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-338 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र सं0-221, नवीनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बारूण प्रखंड अन्तर्गत पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं उसका हस्तांतरण भी हो गया है ।

2- उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मिर्जापुर पशु चिकित्सालय, बारूण के अतिरिक्त प्रभार में हैं । इनका बारूण पशु चिकित्सालय में कार्यदिवस सप्ताह में बुधवार एवं वृहस्पतिवार है तथा क्षेत्र की जनता को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है ।

3- उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है । साथ ही उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक-3360, दिनांक-18.12.2020 द्वारा बिहार पशु चिकित्सा सेवा (मूल कोटि) के 624 रिक्त कोटिवार पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

(व्यवधान)

सवा एक बजे हम सब लोग बैठेंगे । देखिये, एक चीज बता देते हैं....

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण....

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, सुनियेगा तब न....

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आप लोगों से आग्रह है कि अपने-अपने स्थान पर जायें, आज सी0ए0जी0 का प्रतिवेदन भी सदन पटल पर रखा जाना है । कृपया सब लोग सहयोग करें....

(व्यवधान)

और यह अच्छी बात है....

(व्यवधान)

अब, सी0ए0जी0 का प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा जायेगा । माननीय सदस्यगण, अपने स्थान को ग्रहण करें...

(व्यवधान)

न्याय मिलेगा, नियम के अनुसार कार्रवाई भी होगी । आप अजय जी....

(व्यवधान)

आप अपने स्थान पर जाइये । देखिये, सदन और आसन के प्रति आपकी गंभीरता को देखते हुए, अब सुनिये....

(व्यवधान)

सुनियेगा नहीं तो कैसे....

(व्यवधान)

श्री अरूण बाबू....

(व्यवधान)

मंत्री जी के प्रति आपलोगों की सहानुभूति और सदन की गंभीरता को, हमलोग भी गंभीरता से लिये हैं ।

(व्यवधान)

लाठी, गोली कहां चल रही है वीरेन्द्र बाबू, वह युग तो चला गया ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदनों यथा ''वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2)'', ''विनियोग लेखे'' तथा ''राज्य का वित्त'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदनों यथा ''वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2)'', ''विनियोग लेखे'' तथा ''राज्य का वित्त'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदनों यथा ''वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2)'', ''विनियोग लेखे'' तथा ''राज्य का वित्त'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243-I के अनुसरण में षष्ठम राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन, खण्ड-I एवं II की एक-एक प्रति को सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 की धारा-54(2) के तहत् बिहार लोकायुक्त का वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-70(2) के तहत् बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, विधि विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-18(6) के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का वार्षिक लेखा की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपने स्थान को ग्रहण करें ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए)(2) के तहत् बिहार राज्य भंडार निगम के वित्तीय वर्ष 2011-2012 का 55वाँ वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-95(3) के तहत् बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-95(3) के तहत बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री दामोदर रावत, सभापति, राजकीय आश्वासन समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित 306वाँ प्रतिवेदन, पथ निर्माण विभाग से संबंधित

307वाँ प्रतिवेदन एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित 309वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

टर्न-6/संगीता/02.12.2021

अध्यक्ष : बोलिए, महूबब जी अपने स्थान पर जाकर बोलिए क्या कहना चाहते हैं...

(व्यवधान)

सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर जाइए और आपके दल के नेता बैठे हैं, सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर पहले जाइये दल के नेता से हमलोग एक-एक मिनट सुनेंगे । चलिए, जाइये ।

(व्यवधान)

चलिए न, जाइये न । आपके दल के नेता बैठे हैं, जाइये अपने स्थान पर । दल के नेता बोलेंगे, फिर बीच में नहीं । माननीय सदस्य नहीं...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्य वेल से अपने-अपने स्थान पर चले गए)

अध्यक्ष : एक चीज तो हमने आग्रह किया है कि दलीय नेता अपने दल के माननीय विधायकों को एक बार प्रशिक्षण की जरूरत सबको है और विषय को दलीय नेता जिस ढंग से शालीनता से रखेंगे...

(व्यवधान)

अब आप कहां इसमें खड़ा हो गए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपके नेता हैं, नेता बोलेंगे, कोई सलाह देना है तो नेता को सलाह दीजिएगा । बैठ जाइये, बैठ जाइये । पुराने विधायक हैं आप...

(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, एम0एल0ए0 और मंत्रियों का अपमान हो...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उनके सम्मान बढ़ाने के लिए आप भी अपना नैतिक आचरण और व्यवस्था को कम्प्लीट करेंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि गड़बड़ करे ...

(व्यवधान)

बैठ जाइये...

(व्यवधान)

महबूब जी, आप जो वेल में आकर बोल रहे थे, कुछ बोलना है तो एक मिनट का, देखिए आप ही लोगों की सलाह पर अभी हम 1 बजकर 15 मिनट में बैठने जा रहे हैं । उसमें हमने कार्य मंत्रणा समिति के सभी सदस्यों के साथ दलीय नेताओं को भी आमंत्रित कर लिया है और सदन में हमने पहला ही शब्द कहा था सुरेन्द्र बाबू, पहला ही शब्द कहा था कि किसी भी विधायक का अपमान सदन का अपमान होगा ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, सभी माननीय सदस्यों को घेर रहे हैं, आगे ही बोलवा दीजिएगा तो मीटिंग क्या होगा...

अध्यक्ष : तो इसीलिए...

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, पहले मीटिंग हो जाए उसके बाद सभी से बोलवाइएगा...

अध्यक्ष : ठीक है अच्छी बात है, आपके इस सुझाव को हम स्वीकार करते हैं । अब शून्यकाल लिये जायेंगे । यह अच्छी बात है । पुराने वरिष्ठ लोगों को, देखिए इसीलिए न कहा जाता है कि वरीय लोगों से सीखना चाहिए । सुरेन्द्र बाबू ने ठीक कहा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री महानन्द सिंह, शून्यकाल पढ़ें ।

(व्यवधान)

अब देखिए, मतलब किसी की बड़ाई भी नहीं सुन सकते हैं आप, बड़ा विचित्र हाल है ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : शून्यकाल को पढ़ा हुआ मान लिया जाय महोदय ।

अध्यक्ष : पढ़ने दीजिए । क्यों आप उनको...

(व्यवधान)

पढ़ने दीजिए, पढ़िए, पढ़िए ।

(व्यवधान)

पढ़िए महानुभाव, आप पढ़िए तो...

श्री महानंद सिंह : अरवल जिला के सोन तटीय बसावट वाले 3 किलोमीटर...

श्री ललित यादव : माननीय मंत्री जी स्वयं आसन से आग्रह किये हैं और महोदय उसके बाद आप सदन चला रहे हैं...

अध्यक्ष : मंत्री जी भी सहमत हैं कि 1 बजकर 15 मिनट में बैठक का जो हमने निर्णय दिया है और जब आसन की बात को आप नहीं स्वीकार करेंगे, आसन की बात को आप स्वीकार नहीं करते हैं तो यही तो हमारी कमी को कोई न कोई गलत रूप से लेता है । आप बैठ जायं...

श्री ललित यादव : नहीं महोदय, सदन की गरिमा के...

अध्यक्ष : आप पढ़िए...

श्री ललित यादव : आप संरक्षक हैं । माननीय मंत्री जी जिस तरह से रो-रोकर...

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये, बैठ जाइये । अब पढ़ने दीजिए, बैठ जाइये । आप तो रहेंगे, आप भी रहेंगे उस बैठक में...बैठ जाइये ।

शून्यकाल

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, अरवल जिला के सोन तटीय बसावट वाले तीन कि0मी0 के दायरे में आनेवाले को मकान बनाने के लिए बालू की रॉयल्टी माफ किये जाने की मांग करता हूं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखण्डान्तर्गत रघुनाथपुर पंचायत के रघुनाथपुर चवर, सुवैया लइला, हरियारा चवर की हजारों एकड़ जमीन जल जमाव के कारण कृषि योग्य नहीं रह गई है ।

अतः उपर्युक्त रघुनाथपुर पंचायत के रघुनाथपुर चवर, सुवैया लइला, हरियारा चवर से जल निकासी की मांग करती हूं ।

श्री मो0 कामरान : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर (पी0जी0) की पढ़ाई शुरू कराने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : धन्यवाद, 12 शब्दों में ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, पटना, मधुबनी सहित राज्य के 12 जिलों में घोरपरास किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं । किसानों में हाहाकार है ।

अतः घोरपरास के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग करता हूं ।

श्रीमती संगीता कुमारी : महोदय, कैमूर जिला के खरवार जाति का 1910 का खतियान मांगे बिना अनु0जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग करती हूं ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के किसानों को बाढ़ एवं सुखाड़ का सरकार द्वारा किये जाने वाले राशि का भुगतान सरकार रबी बुआई से पूर्व करें ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, बक्सर शहर के बड़ी मस्जिद से सेन्ट्रल जेल तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाय एवं उसके दोनों तरफ नाला निर्माण कराया जाय मैं सदन से मांग करता हूं ।

श्री राम सिंह : महोदय, बिहार राज्य के गन्ना उत्पादक के किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किये जा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य अंके/-350/रूपये प्रति क्विंटल को बिहार में लागू करने की मांग करता हूं ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत मंझौल अनुमंडल के मंझौल-हसनपुर मार्ग पर स्थित जयमंगला गढ़ द्वार से जयमंगला माता मंदिर तथा काबर टाल पक्षी विहार तक जाने वाली लगभग 3 कि0मी0 सड़क काफी जर्जर एवं दयनीय स्थिति में है जिसका निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती विभा देवी : महोदय, नवादा जिला के सरकारी बुधौल बस स्टैण्ड का निर्माण 7-8 करोड़ रूपये में बना है । उक्त बस स्टैण्ड को चालू नहीं किए जाने से लाखों रूपये का राजस्व नुकसान एवं नगर को जाम का सामना करना पड़ता है । राजस्वहित में अविलम्ब उक्त बस स्टैण्ड को चालू कराया जाय ।

श्रीकान्त यादव : अध्यक्ष महोदय, सारण जिलान्तर्गत एकमा प्रखंड के रसूलपुर से चैनपुर सीवान जानेवाले रास्ते में संवेदक के द्वारा सड़क पर लोहे का बैरियर लगा दिया गया है कई बार दुर्घटना हुई है और हमेशा खतरा का डर बना रहता है ।

अतः उक्त बैरियर को हटाने की मांग करता हूं ।

श्री ललन कुमार : महोदय, मैं सरकार से भागलपुर जिला अन्तर्गत कहलगांव के गांगुली पार्क चौक से पीरपैंती के प्यालापुर चौक तक उच्च क्षमता के सड़क निर्माण करवाने की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मिथिला विश्वविद्यालय अन्तर्गत इंटरमीडिएट एवं ग्रेजुएशन में नामांकन हेतु ऑन लाइन आवेदन के बाद छात्रों को अन्य जिलों या दूसरे प्रखंडों में कॉलेज आवंटित किया जाता है, जिससे छात्रों को कठिनाई होती है ।

मैं सरकार से नामांकन की परम्परागत प्रक्रिया बहाल करने की मांग करता हूं ।

श्री भीम कुमार सिंह : महोदय, STET-2019 के चयन प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम घोषित होने बाद बदलाव किया गया ।

सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि STET–2019 का विज्ञापन संख्या PR-373/2019 का पालन किया जाय ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत मोदनगंज प्रखण्ड में पछेती और तीलक बिगहॉ तक बन रहा सम्पर्क पथ जमीन विवाद के कारण बाधित है । सरकार से मांग है कि जमीन अधिग्रहित कर दोनों गांव के लिए संपर्क पथ शीघ्र पूरा करायें ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जाँचोपरान्त गलत बिजली विपत्रों में सुधार की जाए ।

अध्यक्ष : चलिए, धन्यवाद ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, रोजगार के अभाव में देश के कोने–कोने में गए प्रवासी बिहारी मजदूरों की सुरक्षा, मजदूरी भुगतान, आपदा या दुर्घटना संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए देश के सभी जिलों में प्रवासी मजदूर सहायता कार्यालय स्थापित कराने की बिहार सरकार द्वारा पहल हो ।

टर्न–7/सुरज/02.12.2021

श्री ऋषि कुमार : अध्यक्ष महोदय, दाउद नगर (औरंगाबाद) प्रखंड के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के अनियमितता की जांच की जाए । ये मृत अनुज्ञप्तिधारी (36D85) के नाम पर भी अनाज का उठाव कर बेच दिया गया । MO द्वारा अवैध पैसे की उगाही की जांच की जाए एवं इनके आय से अधिक की संपत्ति की भी जांच की जाए ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज–टेढ़ागाछ सड़क का टेंडर 2015 में हुआ था परन्तु आज तक सड़क का काम पूर्ण नहीं हो सका है ।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त सड़क को शीघ्र पूर्ण किया जाए एवं संवेदक और विभाग के दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए एवं सड़क का चौड़ीकरण किया जाए ।

श्री शाहनवाज : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड में अक्टूबर 2021 में बेमौसम आयी बाढ़ से धान, आलू, सब्जी, सहित अन्य फसलें बर्बाद हो गयी हैं जिसके कारण किसानों को आर्थिक क्षति हुई है ।

अतः उक्त प्रखंड में आयी बाढ़ से किसानों की बर्बाद फसलों की क्षति की भुगतान की सूचना देता हूं ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र कोचाधामन में इस वर्ष असमय बाढ़ आने के कारण धान एवं सब्जी की खेती को भारी नुकसान हुआ है ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि क्षतिपूर्ति हेतु किसान भाइयों को उचित मुआवजा अविलंब उपलब्ध कराया जाए ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, बढ़ती महंगाई को देखते हुए राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगों के पेंशन को बढ़ा कर कम से कम 5 हजार रुपया प्रति माह करने की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, युवाओं, छात्र एवं छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं खेलकूल को बढ़ावा देने के लिए शेखपुरा जिला मुख्यालय में स्टेडियम का निर्माण जनहित में शीघ्र कराने की मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लगभग 5.1 लाख से ज्यादा दिव्यांगजन हैं परन्तु उनके सर्वांगीण विकास हेतु अभी राज्य में दिव्यांगजन. ..

अध्यक्ष : मुकेश जी, आप लिखकर दिये हैं 11 शब्दों में ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : दूसरा है महोदय ।

अध्यक्ष : मुकेश कुमार रौशन, महुआ नगर परिषद् क्षेत्र में सिवरेज सिस्टम का निर्माण कराने के संबंध में...

श्री मुकेश कुमार रौशन : वह कल था महोदय, उसका कल हुआ है महोदय । आज उसको कोई प्रस्तुत किया होगा । कल वह था । कल वह हो चुका है महोदय ।

अध्यक्ष : तो यह आज कैसे आया है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, 2011 की जनगणना...

अध्यक्ष : एक मिनट । इसको चेक करवा लेते हैं । पढ़ दीजिये, पढ़िये ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लगभग 5.1 लाख से ज्यादा दिव्यांगजन हैं । परन्तु उनके सर्वांगीण विकास हेतु अभी राज्य में दिव्यांगजन आयोग गठित नहीं है तथा उन्हें अन्य राज्यों से बहुत कम विकलांग भत्ता का भुगतान होता है । अतः विकलांग आयोग के गठन की मांग करता हूं ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला में रबी की बुआई में डी0ए0पी0 खाद की बहुत कमी है । पर्याप्त मात्रा में डी0ए0पी0 खाद उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिलान्तर्गत हिलसा अनुमंडल के एक मात्र अंगीभूत महाविद्यालय एस0यू0 कॉलेज, हिलसा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई जल्द शुरू करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, चेनारी विधान सभा अंतर्गत छितराताड़ में कुदरा नदी पर बने पुल के पास कटावरोधी दीवार गिरने के कारण सबराबाद–तेलारी पथ पर आवागमन बाधित है ।

अत: कटावरोधी दीवार निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के बरौनी प्रखंड अंतर्गत डॉक्टर राजेन्द्र भारती संस्कृत उच्च विद्यालय भवन की स्थिति जर्जर है । सरकार से जर्जर भवन की मरम्मति एवं नए भवन निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, देशी चिकित्सालय खगड़िया जिला कई वर्षों से किराये के मकान में चलता है को स्थायी भवन 10 बेड सहित सम्पूर्ण व्यवस्था सरकार से करने की मांग करता हूं ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड गडहनी और अगिआंव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काफी जर्जर हैं और बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, माननीय मंत्री द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य बनाने की अनुमति दिये जाने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका, अविलम्ब निर्माण कार्य शूरू करने की मांग करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, सिवान के बेलोड़ी, गोपालगंज के महमदपुर तथा राज्य के मोतिहारी, मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों में हुई जहरीली शराब से मौत की उच्चस्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों पर कठोरतम कार्रवाई एवं मृतक के आश्रितों को मुआवजा की मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, बिहार के सभी तरह के प्राथमिक, मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय नहीं होने के चलते बच्चियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ।

अत: बिहार के सभी तरह के विद्यालयों की जांच कराकर गुणवत्तापूर्ण शौचालय का निर्माण कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी । ध्यानाकर्षण के बाद समय शेष रहेगा तो शून्यकाल फिर लिये जायंगे ।

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार, अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल कोई मंत्री सुन नहीं रहे हैं सब मंत्री...

अध्यक्ष : ट्रेजरी बेंच शून्यकाल में भी गंभीरता से इसको लें और सुनें । ठीक है । बैठ जाइये अब, बैठ जाइये ।

<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य</u>

सर्वश्री अजय कुमार, अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं अन्य सात सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली सहित सभी जिलों में मांग के मुकाबले सिर्फ 25 फीसदी ही डी0ए0पी, पोटाश एवं यूरिया खाद उपलब्ध होने के कारण खाद की भारी किल्लत है । राज्य के कई जिलों में किसान कालाबाजारी के कारण 400 से 500 रुपये तक प्रति बोरी ज्यादा देकर खाद खरीदने को मजबूर हैं ।

अत: जनहित में राज्य के सभी जिलों में पर्याप्त खाद की व्यवस्था करने एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, राज्य में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली सहित पूरे राज्य में रबी मौसम में यूरिया, डी0ए0पी एवं पोटाश की आवश्यकता निम्नवत है:

यूरिया-12 लाख मीट्रिक टन, डी0ए0पी-4 लाख मीट्रिक टन, पोटाश-1.5 लाख मीट्रिक टन, कम्पलेक्स जो मिक्सर खाद होता है 2.0 लाख मीट्रिक टन ।

अक्टूबर एवं नवम्बर माह तक उक्त उर्वरकों की आवश्यकता एवं प्राप्ति भी निम्नवत है:

यूरिया 4.35 लाख मीट्रिक टन, प्राप्ति-3.43 लाख 59 प्रतिशत । महोदय, डी0ए0पी 2.3 लाख मीट्रिक टन यह नवम्बर तक है, प्राप्ति 0.81 यानी 35 प्रतिशत उपलब्ध है ।

(क्रमश:)

टर्न-8/राहुल/02.12.2021

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री :(क्रमश:) कंपलेक्स जो मिक्सर खाद है वह 1.05 लाख मीट्रिक टन है इसकी आवश्यकता, उसके विरूद्ध प्राप्ति एक लाख मीट्रिक टन है यह 96 प्रतिशत उपलब्ध है । महोदय, पोटाश 0.95 मीट्रिक टन और प्राप्ति 0.16 मीट्रिक टन है यह 17 प्रतिशत उपलब्ध है । उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि आवश्यकता के आलोक में अब तक उर्वरकों की आपूर्ति कम हुई है । उर्वरकों की आपूर्ति हेतु सभी स्तरों से कृषि निदेशक, सचिव, मुख्य सचिव एवं स्वयं मेरे स्तर से भारत सरकार से आवश्यकता के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति हेतु लिखित एवं मौखिक अनुरोध किया गया है । भारत सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है तथा कई जिलों में शीघ्र उर्वरकों के रेक आगमन होने की सूचना भी मिली है । कई उर्वरक कंपनियों द्वारा 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक विभिन्न उर्वरकों की रेक लहेरिया सराय, कटिहार, छपरा ग्रामीण, खगड़िया, भोजपुर,

फतुहा, रानीपत्रा, मोतिहारी, तिलरथ, पूर्णियां एवं गया आदि रेक प्वाइंट पर आने की सूचना है जिससे उन रेक प्वाइंट से संलग्न जिलों को उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी ।

महोदय, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है तथा...

(व्यवधान)

सुनिये पहले, सुन लीजिये...

अध्यक्ष : शांति, टोका-टोकी नहीं कीजिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है तथा खरीफ मौसम में निर्धारित मूल्य पर उर्वरकों की आपूर्ति कृषकों के बीच करने में सफल रही है । जिन उर्वरक विक्रेताओं अथवा कंपनियों ने जीरो टॉलरेंस नीति के खिलाफ कार्य किया है उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 194 प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा 246 अनुज्ञप्तियों को निलंबित किया गया । जीरो टॉलरेंस नीति के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर भी सरकार कठोरता से कार्रवाई के लिए कृत संकल्पित है ।

रबी मौसम में अब तक प्राप्त 11 शिकायतों में 04 उर्वरक विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है । राज्य सरकार किसानों के हित में उर्वरकों की आपूर्ति आवश्यकता के अनुरूप करने तथा निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित करने हेतु हर संभव आवश्यक कार्रवाई करेगी ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : महोदय, महोदय...

अध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य अभी उनका पूरक नहीं हुआ, थोड़ा धैर्य रखिये ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, दिनांक-22.11.2021 को सचिव, कृषि द्वारा कृषि निदेशालय संबंधी सभी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में कार्य प्रगति से संबंधित साप्ताहिक समीक्षा बैठक की संक्षिप्त कार्यवाही में निर्णय लिया, उसमें उर्वरक के संबंध में उन्होंने दिया है कि भारत सरकार द्वारा 65 प्रतिशत यूरिया डिस्पैच कर दिया है जो एक-दो दिन में प्राप्त होगा । इसी प्रकार उसमें डी0ए0पी0 के संबंध में बताया है कि इसमें निर्धारित लक्ष्य 1 लाख 32 हजार के विरूद्ध मात्र 27 हजार 540 मीट्रिक टन ही प्राप्त हुआ तो मैं यह जानना चाहता हूं, यह बैठक हुई है दिनांक-22.11.2021 को, उसमें पूरे बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट जिला कृषि पदाधिकारी और पूरे बिहार का कृषि का महकमा वहां मौजूद था और जब यह तय हुआ 1 लाख 32 हजार मीट्रिक टन की जरूरत है और सिर्फ 27 हजार 540 मीट्रिक टन उपलब्ध कराया गया तो इसका मतलब बिहार के जो किसान हैं उनकी खेती कैसे होगी यह सवाल मूल सवाल है । बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है अगर

उर्वरक नहीं उपलब्ध होगा तथा डी0ए0पी0, पोटाश और यूरिया नहीं उपलब्ध होगा तो बिहार का किसान खेती कैसे करेगा...

अध्यक्ष : पूरक क्या है, पूरक ?

श्री अजय कुमार : मेरा सवाल है कि जब मात्र 27 हजार 540 मीट्रिक टन डी0ए0पी0 उपलब्ध हुआ है उसके बाद जो जरूरत है वह कैसे होगा, एक और इसी के साथ दूसरा जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि कालाबाजारी जीरो टॉलरेंस पर चल रही है यह बिलकुल सत्य से परे है । बिहार के सभी जिलों में और समस्तीपुर में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि किसान को 500 से 600 रुपया प्रति बैग ज्यादा दर पर बेचा जा रहा है और कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है । इसलिए ठोस रूप से सरकार आज इस सदन के माध्यम से ऐलान करे कि किसी किसान को भी एक पैसा ज्यादा दर पर खरीदना नहीं पड़े, हमको यह जवाब चाहिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, पहले तो मैं यह बता दूं कि 30 नवंबर तक, मैंने जो बताया है पहले यूरिया की कोई कमी नहीं है । इसलिए यूरिया के कालाबाजारी की बात तो नहीं की जाय, एक बात...

(व्यवधान)

सुन लीजिये मेरी बात । यूरिया जितना चाहें आप लें हम तैयार हैं और सब जगह उसकी उपलब्धता है और वह हो रही है । कमी सिर्फ डी0ए0पी0 की है और वह कमी सिर्फ बिहार में नहीं है ये ध्यान देने योग्य बाते हैं पूरे देश में इसकी कमी है और इसके कारण हम लोगों को भी कमी है लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले सप्ताह भारत सरकार के माननीय मंत्री मांडविया जी, जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं उनके साथ मैंने बैठक की है, बैठक में हमारे सेक्रेटरी, डायरेक्टर सब थे और उन्होंने एक सप्ताह के अंदर एक लाख मीट्रिक टन देने का वादा किया है । हम लोगों ने डिमांड किया तो उन्होंने कहा कि हम देंगे और वह आना शुरू हो गया है और आप चाहें तो हर जिले के हिसाब से कब, कहां, कौन रेक पहुंच रहा है वह भी मैं आपको बता सकता हूं, मेरे पास है आपका आदेश हो तो कहिये हम बता देते हैं...

अध्यक्ष : सदन पटल पर रख दीजिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : ठीक है सर । अब सुन लीजिये, जहां तक आपने कहा कालाबाजारी, कालाबाजारी करने वाले अपना धंधा करते हैं लेकिन बिहार राज्य में पिछले खरीफ के मौसम में हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की...

(व्यवधान)

सुन लीजिये बात पहले...

अध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : आपके समय में क्या होता था कुछ पता नहीं है, सुन लीजिये अब वह सब बात मत कीजिये...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सत्यदेव जी, सुन लीजिये, मंत्री जी अभी खड़े हैं बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

नहीं ये गलत है, बैठ जाइये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : गजब बात है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मंत्री जी आप इधर बोलिये, आप उधर देखिये मत, इधर बोलिये...

(व्यवधान)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यूरिया की मांग खरीफ में ज्यादा थी, होती है ज्यादा । डी0ए0पी0 की मांग अभी रबी मौसम में बहुत अधिक है तो खरीफ के मौसम में 266 रुपया यूरिया, कोई भी किसान ऐसा नहीं कह सकता है कि हमें नहीं मिला है और यह सुनिश्चित किया हमने कि 266 रुपये में यूरिया दो नहीं तो आपकी नौकरी जायेगी, कंपनी के कई अधिकारियों पर मैंने मुकदमा कर दिया वे जेल के दरवाजे पर खड़े हैं और इसको सुनिश्चित किया । पहली बार मालूम हुआ किसानों को कि 266 रुपये में यूरिया, इसके पहले नहीं पता था क्लेक्टर पंचायती करते थे मैं यह बात बता रहा हूं और 300, 400 में बिकवाओ यह तय होता था, मैंने इसको सुनिश्चित किया, हमारी सरकार ने इसे सुनिश्चित किया और 266 रुपये में यूरिया बिकवाया जिसमें 11 सौ रुपया भारत सरकार की सब्सिडी है । एक 45 किलोग्राम का जो बोरा होता है, जो बैग होता है यूरिया का, उसमें भारत सरकार की सब्सिडी 11 सौ रुपया है । आप समझ लीजिये कि कितनी सब्सिडी है भारत सरकार की और...

अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : 266 रुपया में किसान लिया और इसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया था । डी0ए0पी0 खाद की कमी है और उस कमी की पूर्ति करने के लिए सचेष्ठ हैं, भारत सरकार भी सचेष्ठ है । वह हमसे जो वादा किये हैं उस वादे के अनुसार रेक भी आना शुरू हो गया है, थोड़ा धैर्य रखना ही पड़ेगा । हम जानते हैं किसानों की क्या दिकक्त है, हम भी किसान परिवार से हैं और बढ़िया किसान परिवार से हैं, हम उनका

दुख, उनकी तकलीफ जानते हैं । ऐसी बात नहीं है, हम किसान के बेटे हैं इसलिए हम जानते हैं और अच्छे किसान हैं घर के । हम नहीं जानते हैं आलू पेड़ पर पैदा होता है...

(व्यवधान)

लेकिन हमने खेती की है, अपने हाथों से खेती की है । सुधाकर जी, भलीभांति आप जानते हैं इस बात को...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी...

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : सुधाकर जी, आप कम से कम मत बोलिये इस बात को । आपके यहां मैंने जैसे-जैसे आपने, आपके पिताजी ने जिस प्रकार से कहा उस प्रकार से आपके यहां खाद बटवा दिया ।

क्रमशः

टर्न-9/मुकुल/02.12.2021

क्रमशः

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः हमने उसको सुनिश्चित किया और दाम में बंटवाया है । कैमूर जिले में कहीं दिक्कत नहीं है और बिल्कुल 266 रुपये में, आप उसके गवाह हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्रः केवल अपने में बंटवाइयेगा कि हम लोगों में भी बंटवाइयेगा । ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः नहीं, आपको भी बंटवाये हैं, आप बताइये, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप विपक्ष के माननीय सदस्य हैं, हमें सहयोग कीजिए, सुन लीजिए । अवध विहारी बाबू जी ।

श्री अवध विहारी चौधरीः अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में फॉसफेटिक खाद की कमी है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः हां, आपकी बात ठीक है ।

श्री अवध विहारी चौधरीः बोआई का समय आ गया है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः अवध विहारी बाबू जी, हम आपकी बात मानते हैं, आपकी बात मान लिये न ।

श्री अवध विहारी चौधरीः व्यवस्था करने की आपकी जिम्मेवारी है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः हां, व्यवस्था करने की जिम्मेवारी है ।

श्री अवध विहारी चौधरीः तो कब तक व्यवस्था करवाइयेगा ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः हम कहां कह रहे हैं कि हम व्यवस्था नहीं कर रहे हैं ।

श्री अवध विहारी चौधरीः व्यवस्था करवाइये ताकि किसानों को मुहैया हो सके और गेहूं की बुआई समय सीमा के अंदर हो ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः देखिये, हम आपको बता देते हैं :-

क्र0 सं0	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	रैक बिन्दु	रेक आगमन संभ वत ति	रैक बिन्द से आपूर्ति कि जाने वा जिला
1	आई0पी0एल0	डी0ए0पी0	लहेरियासराय	01.12.2021	दरभंगा, मधुबनी, समस्ती
2	पी0पी0एल0	डी0ए0पी0	कटिहार	29.11.2021	दरभंगा, मधुबन समस्तीपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णियां
3	पी0पी0एल0	डी0ए0पी0	छपरा ग्रामीण	05.12.2021	सारण, सिवान, गोपालगंज
4	आई0पी0एल0	डी0ए0पी0	खगड़िया	01.12.2021	खगड़िया, बेगुसराय
5	आर0सी0एफ0	डी0ए0पी0	भोजपुर	03.12.2021	भोजपुर, बक्सर, अरवल
6	पी0पी0एल0	डी0ए0पी0	फतुहा	01.12.2021	पटना, आरा, नालं जहानाबाद
7	कोरोमण्डल	डी0ए0पी0	रानीपत्रा	01.12.2021	पूर्णियां, अररि किशनगंज, कटिहार

अध्यक्षः मंत्री जी, डेट बताते जा रहे हैं उसे नोट कर लीजिए ।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अरवल के बारे में बता दें ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः हम रख भी देंगे, आप सुन लीजिए, सुनिये तो । सुरेन्द्र बाबू जी सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः धैर्य से सुनिये । आपका हस्ताक्षर इसमें नहीं है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः अच्छा, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं ।

8	चम्बल फर्टि0	डी0ए0पी0	मोतिहारी	03.12.2021	मोतिहारी, बेतिया
9	चम्बल फर्टि0	डी0ए0पी0	खगड़िया	04.12.2021	खगड़िया, बेगुसरा लखीसराय, मुंगेर
10	जी0एस0एफ0सी0	डी0ए0पी0	तिलरथ	04.12.2021	बेगुसराय, खगड़िया
11	इफको	डी0ए0पी0	पूर्णियां	04.12.2021	कटिहार, किशनगंज, पूर्णि

12	इफको	डी0ए0पी0	गया	05.12.2021	गया, जहानाबाद

अध्यक्ष महोदय, हम बिल्कुल सजग हैं, हम लगे हुए हैं, हमारा संपर्क भारत सरकार से है और एक बात मैं आप सबसे कह दूं, माननीय सदस्य अजय कुमार जी को । आप बैठ जाइये, मैं बताऊं आपको कहीं भी यदि ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अरुण जी, बैठ जाइये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनी जाय । यदि कहीं भी माननीय सदस्यों से आग्रह है, निवेदन है कि कहीं भी यदि उनको सुनाई पड़े तो स्पेसिफिक शिकायत कर दें, सरकार उसके खिलाफ बेहिचक कठोर कार्रवाई करेगी और यह हम आपको वचन देते हैं, वादा करते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: जिनका हस्ताक्षर है उन्हीं की बात को हमलोग प्रोसिडिंग्स में लेंगे ।

हां, बोलिये जिनका प्रश्न है ।

श्री अजय कुमार: अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से सीधा सवाल है कि मैं आसन के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि समस्तीपुर जिला में नवम्बर महीने में 10 हजार 746 मीट्रिक टन डी0ए0पी0 की जरूरत थी, दिसम्बर महीने में 9 हजार मीट्रिक टन डी0ए0पी0 की जरूरत थी और इसके अगेंस्ट में सिर्फ 11 सौ 55 मीट्रिक टन उपलब्ध हुआ । क्या सरकार पूरे खाद जिसकी जरूरत है डी0ए0पी0 का खासकर के और पोटास का, वह उपलब्ध करायेगी और किस तिथि तक उपलब्ध करायेगी यह सरकार बताये ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया है ।

अध्यक्ष: आप धैर्य से सुनिये और विमर्श कीजिए बढ़िया से ।

(व्यवधान)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: तमाम जिलों...

अध्यक्ष: आप हस्ताक्षर नहीं किये हैं, अलग से मिलकर पूछ लीजिएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बगैर पूछे हुए नहीं बता रहे हैं । ये जवाब दे रहे हैं आप धैर्य रखिये न, बैठिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है, अवध विहारी बाबू जी की बात सही है । हमने कहा है कि डी0ए0पी0 और बाकी जो खाद फॉसफेट है, इसकी अधिक

आवश्यकता है, इसमें मक्का में भी और गेहूं में भी दोनों में समान रूप से इसकी आवश्यकता होती है इसलिए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब शांति बनाये रखिए, यह उचित नहीं है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया है कि इन जिलों में 5 तारीख तक, अभी तक की आवश्यकता के अनुसार खाद हम पहुंचा देंगे ।

अध्यक्ष: चलिए, अब सकारात्मक जवाब है ।

श्री अजय कुमार: अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल बस इतना ही है कि किल्लत इतनी है खाद का, डी0ए0पी0 का क्या इसके अनुश्रवण में सभी विधान सभा के जो विधायक हैं उनके क्षेत्र में अनुश्रवण कमेटी बनाकर के उनके देखभाल में वितरण किया जायेगा । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार यह चाहती है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: महोदय, प्रत्येक जिले में अनुश्रवण समिति बनी हुई है और समय के साथ उसकी बैठकें होती रहती हैं और हम, सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

आज आपने कहा है तो इस खाद पर विशेषकर के और सभी जिलों के डी0एम0 को हम आज ही निर्देश दे देंगे कि आप अनुश्रवण समिति की बैठक करके और उस क्षेत्र के विधान सभा के माननीय सदस्यों को बुलाकर के और खाद का वितरण कैसा हो रहा है उनको जानकारी दीजिए और उनको विश्वास में लेकर के खाद के वितरण का अनुश्रवण करें ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए आपके विभाग में कोई दस्ते की टीम, फ्लाइंग स्क्वाड है, कोई जिला में बना हुआ है ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: हमने 18 स्क्वाड टीम बनाया है और वे छापेमारी के लिए समय-समय पर निकलती हैं ।

अध्यक्ष: उसकी उपलब्धि क्या रही है, किसी जिले का हो तो बता दें ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उसकी उपलब्धि तो मैंने बताया है ।

अध्यक्ष: अब अनुश्रवण की बात जो माननीय विधायक कर रहे हैं तो वह तो आपलोगों के माध्यम से, जिला के जिलाधिकारी के माध्यम से बैठक होती है क्या ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, बैठक होती है ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः बैठक हो रही है तो माननीय सदस्य, जहां बैठक नहीं हो रही है तो आप लिखकर के देंगे तो मंत्री जी उसको दिखवा लेंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः इस विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय, हम खाद के लिए करवा देंगे ।

अध्यक्षः ठीक है ।

श्री विजय शंकर दूबेः अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्षः क्या आपका इसमें साइन है ?

श्री विजय शंकर दूबेः जी, महोदय । इसमें मेरा नाम है ।

अध्यक्षः आपका नाम इसमें है, बोलिये ।

श्री विजय शंकर दूबेः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, कृषि ने जो राज्य में विभिन्न केन्द्रों पर गाड़ी के आगमन का, रेक के आगमन की सूचना दी उसमें छपरा शामिल है, सिवान और गोपालगंज के किसानों के लिए खाद छपरा उतरेगा और छपरा से दूसरे रूट होकर के मीरगंज पहुंच जायेगा उसको रोकने का मंत्री जी के पास कोई इंतजाम नहीं है । सिवान में रेक क्यों नहीं उतरा, गोपालगंज और सिवान का रेक सिवान में उतारता तो सिवान के और गोपालगंज के किसानों को खाद उपलब्ध हो जाता, छपरा उतारने का क्या औचित्य है ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, रेक प्वाइंट कहां होगा, खाद का वितरण कैसे होगा यह निर्धारित कम्पनी और कम्पनी के वहां जो भारत सरकार का जो मंत्रालय है उसके बीच तय होता है । हमलोग सुविधा के अनुसार उसको निश्चित रूप से और निकट करने की जो मांग होती है उसके मुताबिक इधर-उधर करवाते हैं, अगर विशेष रूप से कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कहेंगे तो उसको हम उनलोगों से आग्रह करके करवायेंगे, उसमें हमारा कुछ नहीं है ।

अध्यक्षः ठीक है ।

श्री विजय शंकर दूबेः अध्यक्ष महोदय, सिवान पहुंचाने का आज के पहले जितने भी वितरण हुए हैं, सिवान में रेक उतरता था, गोपालगंज और सिवान के कृषकों के लिए सिवान केन्द्र था । आप सिवान, छपरा और गोपालगंज को छपरा के साथ टैग कर दिये । दूसरी बात हुजूर, कालाबाजारी रोकने का विभाग के पास कोई उपाय, प्रबंध नहीं है ।

टर्न-10/यानपति/02.12.2021

अध्यक्षः कोई सुझाव है क्या ?

श्री विजय शंकर दूबेः जी, क्या ?

अध्यक्षः कोई सुझाव है ?

श्री विजय शंकर दूबेः अध्यक्ष महोदय । सुझाव है । ये एक तो माननीय मंत्री जी जितना कह रहे थे कि माननीय सदस्यों को हम शामिल करेंगे भविष्य में । किसान का रोपाई शुरू है.....

अध्यक्षः भविष्य के लिए ऑलरेडी बैठक हो रही है हर जिले में । अनुश्रवण की जो इनकी बनी हुई है, उसकी बैठक हो रही है ।

श्री विजय शंकर दूबेः आजतक तो कोई सूचना माननीय सदस्यों को नहीं दी गयी कृषि विभाग की ओर से ।

अध्यक्षः क्या बताइये ।

(व्यवधान)

बैठक होती है ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्रीः बैठक होती है और खुद बैठक में जाते हैं ।

श्री विजय शंकर दूबेः खुद, कागज में-कागज में और उसमें केवल माननीय मंत्री प्रमोद बाबू बुलाये जाते हैं । अध्यक्ष महोदय वो.....

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, माननीय विधायकों को सूचना मिले और बैठक में बुलायें यह एक बार सुनिश्चित फिर से करवा लेंगे ।

श्री विजय शंकर दूबेः अध्यक्ष महोदय, सीवान में रेक उतरे और रेक सीवान में आए इसकी व्यवस्था माननीय मंत्री जी सुनिश्चित करें ।

अध्यक्षः संज्ञान में ले लिए हैं ।

श्री विजय शंकर दूबेः भारत सरकार से अनुरोध करें कि सीवान के किसानों को सीवान में खाद उपलब्ध कराया जाय, रेक उपलब्ध करायी जाय ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य अखतरूल ईमान अपनी सूचना को पढ़ें ।

(व्यवधान)

अच्छा एक मिनट बोलिये आप ।

श्री आलोक कुमार मेहताः एक सूचना है महोदय ।

अध्यक्षः आप बैठ जाइये, सूचना है लेकिन समय नहीं है ।

श्री अखतरूल ईमानः अध्यक्ष महोदय, सीमांचल के जिला किशनगंज, पूर्णिया, अररिया.....

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप बस एक लाईन में बताईये ।

श्री आलोक कुमार मेहताः अध्यक्ष महोदय, प्रतिवर्ष खरीफ में और रबी में.....

(व्यवधान)

महोदय, जरा सा ।

अध्यक्षः अखतरूल ईमान जी, एक मिनट ।

श्री आलोक कुमार मेहताः प्रतिवर्ष खरीफ और रबी में किस खाद की कितनी आवश्यकता है उसका एक ट्रेन्ड बना हुआ है । निश्चित रूप से खरीफ में कहीं यूरिया की आवश्यकता ज्यादा है रबी में.....

अध्यक्षः बहुत देर हो चुकी है । पूरक पूछिये ।

श्री आलोक कुमार मेहताः महोदय, ये ट्रेन्ड बना हुआ है । उसके बावजूद अभी एक सप्ताह पहले माननीय मंत्री जी की मीटिंग केंद्रीय मंत्री जी से हुई थी ।

अध्यक्षः पूरक क्या है ?

श्री आलोक कुमार मेहताः केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि खाद की कमी नहीं है और उसके बावजूद खाद समय पर यहां नहीं पहुंच रहा है ।

अध्यक्षः चलिये, यह सब विषय आ चुका है ।

श्री आलोक कुमार मेहताः ये आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रियेट करके कालाबाजारी.....

अध्यक्षः अखतरूल ईमान जी, आप पढ़िये ।

श्री आलोक कुमार मेहताः पहले इसको तय किया जाय, हर साल का कोटा.....

श्री अखतरूल ईमान, श्री शाहनवाज एवं श्री मोहम्मद अनजार नईमी, स॰वि॰स॰ से प्राप्त ध्यानार्षण सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अखतरूल ईमानः ''सीमांचल के जिला पूर्णिया, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार में बहने वाली नदियां महानन्दा, कनकई, बकरा, परमान एवं डोंक इत्यादि नदियों के लगातार कटाव से आसजा, अर्जुन भिट्टा, डमराहा, हजरिया शादीपुर, सिमलबाड़ी नगरा टोला, महेश बथना, मिशन्दा चनकई एवं ताराबाड़ी सहित हजारों गावों में भीषण कटाव हुआ है और अब भी कटाव जारी है । लगातार कटाव के कारण कई सरकारी भवन, विद्यालय एवं पक्की सड़क नदी में कटकर विलीन हो गए हैं ।

अतः उपरोक्त स्थानों पर ग्राम सुरक्षात्मक कार्य कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्षः माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए, कल इसका जवाब हो जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री अमरजीत कुशवाहाः अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लिया जाय ।

अध्यक्षः अब क्या सुनाइयेगा ।

श्री अमरजीत कुशवाहा: सूचना यह है कि कल जो दिया गया था कल डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद का जन्मदिन भी है और मैं चाहूंगा कि उस पर बातचीत ध्यानाकर्षण पर हो जाय । कल के लिए कहा गया था और उसपर जो है चर्चा.....

अध्यक्ष: नहीं-नहीं 03.12.2021 को आएगा और आपकी भावना का सम्मान होगा । बैठ जाइये ।

श्री अमरजीत कुशवाहा: दूसरी एक सूचना.....

अध्यक्ष: अब हो गया, एक सूचना के लिए बोले अब दूसरी सूचना मत पढ़िये । नहीं, बैठिये ।

(व्यवधान)

शून्यकाल ले लें या शून्यकाल समिति को भेज दें ?

(माननीय सदस्यों ने सभी शून्यकाल सूचनाओं को शून्यकाल समिति को भेजने का आग्रह किया)

अध्यक्ष: सभी शून्यकाल सूचनाएं समिति को भेज दी जाती हैं ।

श्री अजीत कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, श्री ददन सिंह पिता स्व0 रघुनाथ सिंह, ग्राम सुकसेना डेरा, थाना-मेरार, जिला-बक्सर के पुत्र-रामभजन कुमार की कोरानसराय में दिनांक 10.07.2021 को दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो गयी । परन्तु अभी तक मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया । दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई तथा अविलंब मुआवजा की मांग करता हूं ।

श्री मो0 इसराइल मंसुरी: अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मड़वन प्रखंड के बड़कागांव में 1857 ई0 में शहीद हुए 28 शहीदों के स्मारक स्थल को विकसित कर संग्रहालय का निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अखतरूल ईमान: अध्यक्ष महोदय, प्रखण्ड अमोरे एवं बैसा सहित पूरे सीमांचल में खाद की किल्लत होने के कारण किसानों को रबी की फसल बुआई करने देरी हो रही है ।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाय ताकि रबी फसल की बुआई ससमय हो ।

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, जनवितरण विक्रेता द्वारा राशन कार्डधारी को समय पर राशन देने में टाल-मटोल, मनमाना विलंब की शिकायतें मिलती रहती है जिससे असहाय जनता को कई दिन मजदूरी छोड़नी पड़ती है ।

जनहित में मांग करता हूं कि राशन कार्डधारियों के सुविधानुसार किसी भी जनवितरण दुकान से राशन आपूर्ति की सुविधा व्यवस्था की जाय ।

श्री संदीप सौरभ: अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग द्वारा 2016-17 में 1.14691 वार्ड सचिवों की बहाली हुई थी । इनसे सरकार ने बिना किसी मानदेय के 4 साल तक विभिन्न योजनाओं में काम लिया । अब इन्हें हटाने की तैयारी चल रही है ।

सभी वार्ड सचिवों को मानदेय के साथ स्थायी करने की मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी प्रखण्ड बाजपट्टी के ग्राम- सोनमनी टोल पुल वर्ष 2018 के बाढ़ में ध्वस्त हो गया वहां हमेशा गंभीर घटनाएं घटती रहती हैं, उक्त पुल से तीन प्रखंड सहित 20 गांव प्रभावित होते हैं । जनहित में पुल शीघ्र निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के अंतर्गत सनोखर एकचारी मुख्य सड़क स्थित मुररघट्टी (चांदनी चौक) से पकड़िया बजरंगबली मंदिर (बेलबड्डा रोड) तक के सड़क निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री अरूण शंकर प्रसादः अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर ग्रीड से नरार पावरस्टेशन तक के 33 हजार के0वी0ए0 के जर्जर लाईन का नवीनीकरण करने की मांग करता हूं ।

श्री विनय कुमारः अध्यक्ष महोदय, गया जिला के गुरूआ प्रखण्ड अंतर्गत मण्डा एवं रघुनाथखाप, दो पंचायतों को जोड़ने वाली भुरहा नदी पर मध्य विद्यालय, गड़ेरी विगहा के पास पुल का निर्माण शीघ्र कराने की मांग करता हूं ।

श्री चेतन आनंदः अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिला के पिपराही प्रखण्ड में बिन्धी पुल का निर्माण अभी तक सरकार द्वारा नहीं कराया गया है । जिससे आम जनता को आने जाने में काफी कठिनाई हो रही है । उक्त पुल का निर्माण यथाशीघ्र कराने हेतु मैं शून्यकाल की सूचना देता हूं ।

श्री संजय कुमार गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिलान्तर्गत प्रखण्ड तरियानी में एक अतिरिक्त सब स्टेशन पावर ग्रीड, वृन्दावन बाजार में स्थापित कराने की मांग करता हूं ।

श्री पंकज कुमार मिश्रः अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रुन्नीसैदपुर प्रखण्ड के मोड़संड पंचायत के भीड़ा टोला से भवानीपुर होते हुए माणिक चौक तक की कच्ची का पक्कीकरण कराने मांग करता हूं ।

श्री रामचन्द्र प्रसादः अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत बहेडी प्रखंड का निबंधन कार्यालय पूर्व मे लहेरियासराय या जिसे वर्तमान में निबंधन कार्यालय बहेड़ा कर दिया गया है जो भौगोलिक एवं यातायात के दृष्टिकोण से बिल्कुल उचित नहीं है ।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि निबंधन कार्यालय को पुनः लहेरियासराय दरभंगा किया जाय ।

श्री विद्या सागर केशरीः अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नगर परिषद जोगबनी के बीच शहर में लगनेवाली द्वार के जमीन पर नगर परिषद के साठगांठ से दबंगों द्वारा अवैध वसूली के नीयत से लगातार पक्के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है जिससे गरीब जीविकोपार्जन

करनेवाले फुटकर विक्रेता बेबस हैं । अतिक्रमणमुक्त करने एवं दोषी पर कार्रवाई की मांग सदन से करता हूं ।

श्री इजहारूल हुसैनः अध्यक्ष महोदय, बिहार एस0 टी0ई0टी0 परीक्षा 2019 में सम्मिलित अभ्यर्थियों का परीक्षाफल अब तक लंबित है जिस कारण अर्हता प्राप्त एवं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अब तक नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं होने के कारण इनकी स्थिति दयनीय है ।

अतः समस्त बिहार के एस0 टी0ई0टी0 परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रमाणपत्र निर्गत कर अति शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झाः अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी विधानसभा-क्षेत्र के सिंघवारा प्रखंड के हरिहरपुर पूर्वी पंचायत के हरिहरपुर निवासी श्री सत्यनारायण झा के घर से वाटर वेज कतरी पोखर तक पक्की सड़क बनाना जनहित में अति आवश्यक है । जनमानस के हितों को देखते हुए यथाशीघ्र बनाने की कृपा करें ।

श्री गोपाल रविदासः अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के ग्राम-परसा, पोठही, बसुहार, नदवा, भलूआॅ को रेलवे ने रास्ता बंद कर रखती है । आने-जाने के लिए अन्डर पास बनाने के लिए राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग करता हूं ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीनः अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिले के सिमरी बख्तियापुर अनुमंडल अंतर्गत सिमरी बख्तियापुर, सलखुआ एवं महिषी प्रखंड में युवाओं एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है जिस कारण इन स्थानों के युवाओं की प्रतिभा निखर नहीं पा रही है ।

अतः सरकार से जनहित में उक्त प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं ।

डॉ0 अनिल कुमार साहनीः अध्यक्ष महोदय, कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के सभी मेनटेंस एवं चल रहे कार्य अभियंता एवं ठेकेदारों द्वारा अनियमितता एवं लूट की जांच कराने की मांग करता हूं ।

श्री भूदेव चौधरीः अध्यक्ष महोदय, बांका जिला अंतर्गत धोरैया प्रखंड के भगौंधा गांव एवं बिशनपुर गांव के कब्रिस्तान का अतिक्रमण हो रहा है । अतः उक्त गांव में अवस्थित कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए उसकी घेराबंदी जनहित में अविलम्ब कराने की मांग करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्रः अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के बिहपुर दक्षिण पंचायत (सोनवर्षा) में 11 नवंबर 2021 को गंगा नदी धार में आशीष मंडल पिता-राजेश मंडल के डूबने से मौत हो गई ।

अतः सरकार से पीड़ित परिवार को पांच लाख सहायता राशि देने की मांग करता हूं ।

श्री सतीश कुमारः अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला अंतर्गत मखदूमपुर में महिला महाविद्यालय स्थापना करने की मांग करता हूं ।

श्री संजय सरावगीः अध्यक्ष महोदय, बिहार में गुटखा, शिखर, रजनीगन्धा सहित कई पान मसालों की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी के बावजूद यह कैंसरकारक तत्व हर चौक-चौराहे पर खुलेआम बिक रहा है । सरकार इसकी बिक्री बन्द करावे ।

श्री जयप्रकाश यादवः अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलांतर्गत नरपतगंज प्रखंड के मधुरा दक्षिण पंचायत में खररा धार के दोनों ओर बसे दलित बस्ती के लोगों के आवागमन हेतु खररा धार में सुमित पासवान के घर से पूरब पुल निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

डॉ0 रामानुज प्रसादः अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के माध्यम से विभिन्न विभागों में नियोजित कार्यपालक सहायकों को विभागीय पत्रांक-488, दिनांक-07.03.2019 द्वारा सभी लाभ दिया जा रहा है, की भांति लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में नियोजित कार्यपालक सहायकों को सभी लाभ दिये जाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, जहानाबाद वार्ड नं.-31 से गुजरने वाली सड़क के किनारे कुड़ा भण्डारण होता है । उसमें आग लगने के कारण ग्राम-बैरागीबाग भरथुआ सहित सड़क से गुजरने वाले लोगों का जीना हराम हो गया है । आग बुझाकर कुड़ा भंडारण को वहां से हटाने की मांग करता हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के पीरो सब्जी मार्केट में आग लगने से 28.04.2021 को 125 दुकानें जलने से दुकानदारों को एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ लेकिन आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला । भुखमरी के शिकार दुकानदारों को पर्याप्त मुआवजे की मांग करता हूँ ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के नया बाजार रेफरल अस्पताल नुतननगर में विगत 3 वर्षों से अधूरा पड़ा पी0सी0सी0 रोड एवं ढक्कन युक्त नाला बनवाने की मांग करती हूं ।

श्री महबूब आलमः कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखण्ड में बिहार-बंगाल की सीमा से बहती हुई नागर नदी की बाढ़ ने नजराबाड़ी, कचना, खिजनडारी, डेगरापारा, बिघौर गांव की हजारों एकड़ जमीन को बंजर बना दिया है ।

उक्त गांवों के पूर्वी तथा नदी के पश्चिमी किनारे रिंग बांध निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री सउद आलम नदवी: अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत विद्युत अंचल ठाकुरगंज में प्रस्तावित पावर ग्रिड का कार्य प्रारंभ कराने की मांग करता हूं ।

श्री राजवंशी महतो: अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत प्रखण्ड चेरिया बरियारपुर में अतिवृष्टि से जलजमाव होता है, किन्तु अंचलाधिकारी के गलत रिपोर्टिंग की वजह से भू-धारी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है । अतएव उक्त प्रखण्ड के जलजमाव पीड़ित किसानों को अविलंब मुआवजा दिलाया जाय ।

श्री मिश्री लाल यादव: दरभंगा जिला के अलीनगर विधान सभा क्षेत्र में तीन प्रखण्ड, अलीनगर, घनश्यामपुर एवं तारडीह क्रमश: तीन अनुमंडल बेनीपुर, विरौल एवं सदर दरभंगा में पड़ता है । परेशानी की दृष्टि से एक अनुमंडल बेनीपुर में तीनों प्रखण्ड को शामिल करने की मांग सरकार से करता हूं ।

डॉ0 शमीम अहमद: अध्यक्ष महोदय, नरकटिया विधान को छौड़ादानो Project Girls High School जर्जर अवस्था में हो गया है । अनहोनी होने से पहले हेमराज दास हाई स्कूल में शिफ्ट कर पठन पाठन कार्य कराया जाय ।

श्रीमती बीना सिंह: वैशाली जिला अंतर्गत महनार प्रखंड के सरमस्तपुर पंचायत के रूपनारायणपुर सिमान स बाजिदपुर तक एक बांध है, जिसके ऊपर ग्रामीण सड़क और पुराना पुल था, जो बाढ़ में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, सरकार क्षतिग्रस्त स्थल पर एक नये पुल का निर्माण कराये ।

श्रीमती नीतु कुमारी: अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के हिसुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 100 एकड़ में पान की खेती होती है । इस वर्ष खेतों में पानी भर जाने के कारण सारा पान का फसल बर्बाद हो गया है ।

अत: सरकार इन गरीब किसानों को मुआवजा प्रदान कराने की कृपा की जाय ।

श्री भरत बिन्द: अध्यक्ष महोदय, जिला कैमूर, प्रखंड-भभुआ के ग्राम सैयदरा खुर्द एवं ममहान गॉ के बीच सुअरा(स्वर्ण नदी) पर पुल नहीं रहने के कारण आम जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ।

अत: उक्त स्थान पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण करावें ।

श्री अनिल कुमार: अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधान सभा के बथनाहा ब्लॉक पर 21 पंचायतों का भार है एवं आमजनों को ब्लॉक आने-जाने में काफी दूरी तय करनी पड़ती है । सहीयारा पंचायत जो विधान सभा के बीचों-बीच पड़ता है, को प्रखंड बनाने की मांग करता हूं ।

श्री अवध विहारी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, सीवान शहर के सीवान रेल जंक्शन से पूरब सिसवन रेल गेट बंद रहने के कारण सीवान से सिसवन एवं सिसवन से सीवान शहर आने जाने में भारी जाम का सामना करना पड़ता है । इस रोड पर फ्लाई ओवर ब्रीज का निर्माण शीघ्र कराने की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार देश-प्रदेश की अनेकों विश्वविद्यालय का नामकरण महापुरुषों के नाम पर रखा गया है उसी प्रकार पूर्णिया के पावन धरती पर अवतरित सद्गुरु महर्षि मेंहि के नाम पर पूर्णिया विश्वविद्यालय का नामकरण जनभावना अनुरूप आवश्यकता है ।

अत: मैं सरकार से पूर्णिया विश्वविद्यालय का नाम महर्षि मेंहि विश्वविद्यालय पूर्णिया करने की मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहू: अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखण्ड अंतर्गत ताजपुर-हलई पथ पर हमेशा लूट-पाट की घटना घटित होते रहती है ।

सरकार से मांग करता हूं कि ताजपुर-हलई पथ, नून नदी पर अवस्थित डिहिया पुल के पास पुलिस नाका स्थापित हो ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिलांतर्गत राजापाकर प्रखंड के गौसपुर पंचायत में बरियारपुर चौर में विद्युतीकरण किये जाने हेतु पोल तो लगा दिया गया है लेकिन तार आदि नहीं लगाये जाने के कारण विद्युतीकरण कार्य पूरा नहीं हुआ है ।

बरियारपुर चौर के अधूरे विद्युतीकरण के कार्य को पूरा किये जाने हेतु मांग करती हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र नरकटियागंज प्रखंड में बिलवलिया पंचायत के ग्राम विसुनपुरा से मनवा परसी होते हुए बलोर नदी पर पुल निर्माण की अतिआवश्यकता है । पुल नहीं रहने के कारण क्षेत्र के लोगों को आवश्यक कार्य के लिए नरकटियागंज अनुमंडल आने में 12 कि0मी0 उलटा फेरा होकर आना पड़ता है ।

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-11/अंजली/02.12.2021

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जाएंगे ।

<u>वित्तीय कार्य</u>

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष–2021–22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों की कुल संख्या 35 है । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है ।

अतः किसी एक विभाग की अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान हो सकता है । मैं मांग संख्या–21 शिक्षा विभाग को लेता हूं, जिस पर वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटीन मुखबंध द्वारा किया जायेगा । इसके लिए 03 घंटे का समय उपलब्ध है ।

विभिन्न दलों को उसकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार के उत्तर के लिए समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	– 56 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	– 55 मिनट
जनता दल युनाइटेड	– 33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 14 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	– 09 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन	–04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 03 मिनट
विकासशील इंसान पार्टी	– 02 मिनट
सी0पी0आई0एम0	– 02 मिनट
सी0पी0आई0	– 02 मिनट
	कुल 180 मिनट ।

श्री गोपाल रवि दासः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी वाला क्या हुआ ?

अध्यक्षः दलीय नेताओं के साथ बैठे, दल से आप ऊपर हैं क्या ? पहले हम जो पूछे, बैठिये । दल के नेता से ऊपर हैं आप क्या ? दल के नेता से बात हो चुकी है ।

(व्यवधान)

आप बैठिये, बैठिये । अपने दल के नेता से संपर्क कर लीजियेगा ।

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''शिक्षा विभाग के संबंध में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूचि में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च,

2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या-2 अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग संख्या-3 अधिनियम, 2021 के उपबंध के अतिरिक्त 7744,01,72,000/- (सात हजार सात सौ चौवालीस करोड़ एक लाख बहत्तर हजार रुपये) से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

महोदय, यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्षः इस मांग पर माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय शंकर दूबे, श्री सुधाकर सिंह, श्री अजय कुमार सिंह, श्री अजीत शर्मा, श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरूल ईमान से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं । जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव का प्रस्ताव प्रथम है ।

अतएव, माननीय सदस्यगण, श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

''इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटाई जाय ।''

महोदय, कटौती प्रस्ताव हमलोग दिए हैं, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलेंगे मेरे पार्टी की ओर से । मैं पांच मिनट का समय लेना चाहता हूं । महोदय, आज शिक्षा जो मानव संसाधन विकास विभाग भी कहलाया जाता है । महोदय, मानव संसाधन विकास विभाग के रख लेने से ही उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, मानव का विकास कैसे हो, शिक्षा विभाग का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है और आज शिक्षा विभाग की जो गिरावट है जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था अभी है, हम शिक्षा व्यवस्था को कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें महोदय, यानी बिहार में जो दिन-प्रतिदिन शिक्षा व्यवस्था में गिरावट आई है । हम आपको छोटा सा एक उदाहरण देना चाहते हैं कि आज गांव में प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में कौन बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अतिपिछड़े के बच्चे पढ़ते हैं, दलित बच्चे पढ़ते हैं, महादलित के बच्चे पढ़ते हैं और बड़े लोगों के बच्चे तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं । महोदय, पांच साल में, हम सरकार को पिछली बार विधान सभा में हम प्रश्न के माध्यम से दो दिन पहले पूछे थे कि आप यह माननीय मंत्रीजी बताइए कि पांच साल में जो बुनियादी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अतिपिछड़े के बच्चे पढ़ते हैं, दलित बच्चे पढ़ते हैं, आप कितने विद्यालय बनाये हैं । जर्जर भवन है महोदय, कब छत गिर जाएगा, बच्चे पढ़ रहे हैं संशय में, डर

से, बाहर में लोग पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, एक विद्यालय नहीं महोदय, हम अपने प्रश्न काल में उठाये थे और अपने क्षेत्र के हम सैकड़ों विद्यालय का नाम गिनाए थे । पूरे राज्य में बहुत माननीय सदस्य आपको इसी छोटा सत्र में एक दिन के शिक्षा विभाग मात्र प्राथमिक विद्यालय का महोदय, बागी कुमार वर्मा जी का था, सुदय जी का था, बहुत माननीय सदस्यों का था कि प्राथमिक विद्यालय का निर्माण नहीं हो रहा है, हम इसलिए कहें कि माननीय मंत्री जी इतना ही मात्र बता दीजिए कि विगत पांच साल में आप कितने प्राथमिक विद्यालय बनाये हैं जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं । आप दुहाई देते हैं हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं, आप कौन सा गरीब के लिए उत्थान और विकास के लिए काम कर रहे हैं जहां शिक्षा व्यवस्था नहीं आपका सुदृढ़ है, आप कहां बिहार को ले जाना चाहते हैं, आपके बिहार के बच्चे राज्य से बाहर कितने जा रहे हैं, आपके दिल्ली, राजस्थान एवं कोटा में कितने बच्चे जा रहे हैं, अन्य प्रदेशों में कितने बच्चे जा रहे हैं, यह तो हाइयर एजुकेशन की बात है महोदय, टेक्निकल शिक्षा की बात है । आप प्राथमिक विद्यालय की सुधार नहीं कर पा रहे हैं जहां से बच्चे ए,बी,सी,डी, क,ख,ग,घ, सीखते हैं वहां आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो हाइयर एजुकेशन और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बात छोड़ दीजिए । आपका मध्य विद्यालय की वही स्थिति है, एक भी मध्य विद्यालय आप पांच साल में खोले हैं तो बताइए, आप क्या ग्रामीण विकास, क्या गांव का विकास करना चाहते हैं, क्या गरीब का विकास करना चाहते हैं आपका कहां बिहार को पहुंचाना चाहते हैं, आप कह दीजिए कि हम यू0के0 से और यू0एस0ए0 से आगे हैं, ठीक है आप आगे हैं, अपनी पीठ अपने ही थपथपाइए, कहने के लिए कोई भी हम जितनी बात अपनी बोल दें बाहर में, हम अपनी बात जितनी बार बोलेंगे कि हम इतने बड़े हम बिहार में चमत्कार कर दिए, चमत्कार दिखना भी चाहिए । यदि आप बोल रहे हैं कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं सरकार में महोदय, कथनी और करनी में दोनों अलग है । कथनी कुछ है और करनी कुछ है । हमलोग इससे सहमत नहीं हैं । सरकार न्याय के साथ कह रही है हम विकास कर रहे हैं, सुशासन बाबू है, लेकिन हमलोग इससे सहमत नहीं हैं । बिहार के यदि किसी, आप बिहार का, हम कह रहे हैं कि पांच विद्यालय के नाम बता दें जो इसी एक साल में बनवाए हों, दो साल में बनवाए हों जर्जर विद्यालय है महोदय, गरीब के गांव में, टोला में कहां विद्यालय खुले हैं । आप सब को एक जगह से दूसरे जगह टैग कर रहे हैं । कहां खुले हैं गरीब के, दलित के बस्ती में वहां आप विद्यालय नहीं बनवा रहे हैं उसको आप चार किलोमीटर, पांच किलोमीटर के एन.एच. पार करके, फोर लेन पार करके, एस.एच.

पार करके बच्चे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं आप आंकड़ा मंगा लीजिए । आप टैग कर रहे हैं ...

टर्न-12/सत्येन्द्र/02-12-2021

श्री ललित कुमार यादव(क्रमशः): आप टैग कर रहे हैं एक विद्यालय को दूसरे विद्यालय में, आपको विद्यालय खोलने की शक्ति नहीं थी और खोलें भी तो उसका भवन बनाने की शक्ति नहीं है। आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्या आमूल परिवर्त्तन करना चाहते हैं, लाख कहें विजय बाबू कि काम हुआ है, हां बहुत काबिल शिक्षा मंत्री हैं, ये काबिल हैं, विद्वान हैं, इनमें विद्ववता है तो दिखनी भी चाहिए ।

श्री विनोद नारायण झाः अध्यक्ष महोदय.....

श्री ललित कुमार यादवः विनोद जी, बैठिये..

(व्यवधान)

अध्यक्षः शांति, आपस में बातचीत न करें ।

श्री ललित कुमार यादवः विनोद जी, आप..

अध्यक्षः आप उधर कहां देखने लगें, इधर न देखिये ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, मैं आपको कह रहा हूँ । हमलोग मधुबनी गये थे तो रावण झा राम सुने थे, ये भाई वीरेन्द्र जी बोलते थे तो हमलोग कहते थे कि भाई विनोद झा को आप रावण झा क्यों कहते हैं । महोदय, वहां बेनीपट्टी में हमारे नेता प्रतिपक्ष गये थे और वहां..

अध्यक्षः व्यक्तिगत नाम नहीं, आप विषय पर आईए न, कहां भटक गये आप ?

श्री ललित कुमार यादवः वे व्यक्तिगत बोले हैं इसलिए मैंने कहा, यह हम नहीं कह रहे हैं आप पूरे प्रेस और मीडिया से पूछिये, पूरे लोग कहें हैं कि हत्याकांड में रावण झा का नाम है..

अध्यक्षः आप यह कहां पहुंच गये । (व्यवधान) शिक्षा पर आईए ।

श्री ललित कुमार यादवः आज सभी विभाग है महोदय लेकिन शिक्षा विभाग का..

अध्यक्षः ठीक है, आपका 5 मिनट समय पूरा हो चुका है, आगे समय बढ़ा देते हैं ।

श्री ललित कुमार यादवः हमारा 25 मिनट है महोदय ।

अध्यक्षः आप 5 मिनट अपने निर्धारित किये हैं ।

श्री ललित कुमार यादवः हम 25 मिनट बोलेंगे महोदय ।

अध्यक्षः ठीक है 25 मिनट, चलिये ।

श्री ललित कुमार यादवः हमको बोलना होगा या बंद करना होगा तो बंद कर देंगे महोदय, आसन मेरा आग्रह स्वीकार करे । महोदय हम कह रहे हैं शिक्षा विभाग में गिरावट का, हम कह रहे

हैं ये विद्वान मंत्री हैं विजय चौधरी जी, हमलोग पिछली बार सदन में मामला उठाया था, ये जीरो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपका जितना भी माध्यमिक विद्यालय है और वहां जो लेबोरेट्री का सामान है..

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: महोदय, अगर मेरे बारे में इनको कोई गलतफहमी है तो इसमें विभाग का क्या दोष है ?

श्री ललित कुमार यादव: इनके बारे में न कोई गलतफहमी है, चूंकि ये प्रभार में हैं शिक्षा विभाग का और शिक्षा विभाग का अनुदान मांग इन्होंने ही प्रस्तुत किया है तो इनका नाम कोट करना जरूरी है, चूंकि इस विभाग को यही संभाल रहे हैं। महोदय, शिक्षा विभाग का बिहार के विकास में एक बहुत अहम भूमिका है और उस भूमिका को सही से न विभाग निर्वहन कर रही है न उसके जो ये प्रभारी मंत्री हैं वे कर रहे है। महोदय, हमने सदन में पिछली बार मदरसा का एक क्वेश्चन उठाया था, स्पष्ट प्रश्न था महोदय, ध्यानाकर्षण के माध्यम से और कई हमारे माननीय सदस्य भी इस बात को रखे थे, वहां इतना भ्रष्टाचार है, आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस, हम तो कहते हैं कि कम से कम जांच तो करवा दीजिये लेकिन आप जांच नहीं कराते हैं किसी से और कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है । आप जांच भी नहीं करायेंगे यानी आप जो कहेंगे सब सही, हमलोगों को यहां जनता मूर्त्ति बनाकर घंटी बजाने के लिए नहीं भेजी है कि आप जो कहेंगे हमलोग सुनते रहेंगे। जनता आपको माफ नहीं करेगी, जनता सब देख रही है, आप में हिम्मत है तो जांच तो करवाईए, महोदय मदरसा में इतनी गड़बड़ी हुई है, वहां इतना शोषण और दोहन हो रहा है कि मैं क्या कहूं। आप में हिम्मत है तो इसकी जांच कराईए और जांच में कोई गड़बड़ी नहीं आयेगी तो हम इस्तीफा कर देंगे, नहीं तो आप इस्तीफा कीजिये लेकिन हिम्मत नहीं है इनको इसके लिए । क्या ये विजय चौधरी जी अपने को काबिल मंत्री, विद्वान मंत्री कहेंगे ? महोदय हमने चुनौती दिया था लेकिन ये चुनौती इन्होंने स्वीकार नहीं किया । महोदय यह शिक्षा विभाग में जो गिरावट है, ये सरकार का द्योतक है कि यह सरकार कहां है देश के नीति आयोग का जो रिपोर्ट है महोदय, इनके नीति आयोग का रिपोर्ट है, यह हम नहीं कर रहे हैं इनका नीति आयोग कह रहा है कि शिक्षा में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है । महोदय, हमलोग तो यह नहीं कह रहे हैं, यह इनके नीति आयोग का रिपोर्ट है, नीति आयोग के रिपोर्ट में है महोदय, बिहार में बच्चों की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं होती है, 26.27 प्रतिशत बच्चे की शिक्षा पूरा नहीं होता है महोदय । महोदय, बिहार में 8वीं तक के स्कूल में नहीं जाने वाले छात्रों की संख्या 12.52 प्रतिशत है। महोदय, नेशनल फेमली हेल्थ सर्वे में जो आंकड़ा प्रकाशित किया गया है उसमें कहा गया है कि कक्षा 8 तक की शिक्षा नहीं प्राप्त

करने वाले छात्रों की सख्या 9.80 प्रतिशत है जो 10 प्रतिशत के लगभग है और यह राष्ट्रीय पैमाने पर सबसे खराब है । महोदय, अब ये अपना पीठ अपने आप जितना थप थपा लें, जितना बिहार को यू0के0,यू0एस0 से आगे ले जाने की बात कह लें लेकिन जो वास्तविकता है उसको पूरा देश और दुनिया देख रही है । पूरे बिहार के बच्चे यहां से देश और दुनिया में जा रहे हैं लेकिन आपके यहां तो कहीं से बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं आप सोचिये ? चूंकि आपकी नीति, आपका नियत साफ नहीं है, न आपकी दूरदृष्टि सही है इसलिए आप कहीं नहीं हैं। महोदय, इतना ही नहीं हम कहते हैं विकास के सबसे खराब आयामों में ये बिहार सबसे फिसड्डी राज्य घोषित हो चुका है, यानी बिहार के राजधानी में महोदय 20 प्रतिशत स्कूल या तो दो शिक्षक के भरोसे चलायी जा रही है या कहीं कहीं एक भी है महोदय, गांव के सुदूर देहात में तो कहीं कहीं से दूसरे जगह से प्रतिनियुक्त कर के विद्यालय चलाया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालय का आपने निर्माण कराया है कुछ लेकिन आजतक उसमें कक्षा नहीं चल रही है, टीचर नहीं बैठ रहे हैं, विद्यार्थी नहीं बैठ रहे हैं और यह स्थिति पूरे बिहार की है। सदन के जो भी माननीय सदस्य हैं, बहुत सारे माननीय सदस्य के क्षेत्र में विद्यालय खुला होगा लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। अब आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईए, आपने अस्पताल तो बना दिया लेकिन आप देख लीजिये अभी जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बना है, 80 प्रतिशत अस्पताल जो आप बनाये हैं उसमें आजतक पांच साल हो गया है लेकिन ताला ही लगा हुआ है, उसका गेट लोग खोलकर ले गये, खिड़की खोलकर ले गये और आपके स्कूल का भी यही हाल है। आप कह रहे हैं मेरे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास शिक्षक नहीं है तो आप भवन क्यों बनाये? आपका नीति क्यों इस तरह का बनाया जाता है, केवल भवन बनाकर ऐसे ही रखना यहां के गरीब जनता के पैसा का दुरूपयोग है महोदय, पांच साल से, सात साल से अतिरिक्त प्रा0स्वा0केन्द्र बने हुए हैं लेकिन वहां अभी तक ताला लटका हुआ है और स्थानीय ग्रामीणों ने सब गेट बगैरह खोल लिया, खिड़की का शीशा बगैरह फोड़ दिया और अब ग्रामीण लोग उसमें गाय-भैंस ले जाकर बैठाते हैं, यहीं आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था है । आप जो माध्यमिक विद्यालय बनाये हैं, उसमें देख लीजिये कि कहां पढ़ाई होता है, विद्यालय में वैसे ही ताला बंद है लोग कहीं कहीं ताला खोलकर गेट बगैरह ले जा रहे हैं, यही आपकी शिक्षा व्यवस्था है, इसका जो हाल है बेहाल है।(व्यवधान) चरवाहा विद्यालय, आपके समझ से बाहर की चीज है। यू0एस0 और यू0के0 के लोग, देश और दुनिया के लोगों ने इसका प्रशंसा किया था, आपलोगों जैसे उच्च मानसिकता के लोग हीं उसके विरोधी हैं । गरीब के बच्च जब उस चरवाहा

विद्यालय में जायेंगे पढ़ने के लिए तो आपको पेट में दर्द होगा कि गरीब के बच्चे पढ़ लिखकर के हो सकता है, हमारे विजय बाबू भी चाहते होंगे कि गरीब के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो आगे बढ जायेगा, उनको राजनीतिक ज्ञान हो जायेगा, हो सकता है उनकी भी यह मंशा हो कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ें तो आपको पेट में दर्द इसलिए ही होता है । चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट आप नहीं जानियेगा, आप जान लीजियेगा तो आपको समझ में आ जायेगा। देश और दुनिया के लोगों ने इसको सराहा है। अनाथ बच्चे जो सुअर चराने वाले हैं, भैंस चराने वाले हैं, गाय चराने वाले हैं, वैसे बच्चे गरीब जिसको कोई देखने वाला नहीं है, उनको हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि ये सुअर चराने वाले, गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले तुम्हारे लिए भी विद्यालय होगा लेकिन विजय बाबू का यह सोच नहीं हो सकता है। वह लालू यादव का सोच था विजय बाबू तो चाहते हैं जितना नया प्राथमिक विद्यालय बना, माध्यमिक विद्यालय, बुनियादी विद्यालय बना उसमें ये विद्यालय भवन नहीं बना रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं उसी प्रकार से आपके अस्पताल में एक डॉक्टर नहीं है, आप पता कर लीजिये, पशुपालन अस्पताल जो हैं वहां कहीं भी एक भी डॉक्टर नहीं है सब जगह आपका खाली है, सारा पद खाली है । जितना हेल्थ सब सेंटर बना, आप कहते हैं हम तरक्की किये हैं, तो विकास का यही आयाम है, यहां जो भी अस्पताल बना वह बंद है और जो स्कूल बना उसको दूसरे जगह पर टैग कर दियें । जो भी अस्पताल बना, वहां ताला बंद है, पशुपालन का तो कहीं अस्पताल हीं नहीं है और महोदय, यही स्थिति सारे विभाग का है । जिस विभाग के हमारे श्री मुकेश सहनी जी जो दरभंगा जिला से आते हैं मत्स्य मंत्री है, बिहार में आंध्र प्रदेश और बंगाल से मछली आता है, महोदय, इनके गांव में, मंत्री जी के गांव में पांच ट्रक डेली मछली उतरता है और ये कहते हैं कि बिहार विकास कर रहा है, यही विकास कर रहा है । हमारा मिथिला का मछली पहले हर जगह जाता था, मखाना हर जगह जाता था, पान जाता था लेकिन आज सारे चीज का कारोबार दम तोड़ रहा है सरकार के नीति के कारण, चूंकि आपके तरफ से, सरकार के तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। आप इसकी जांच कर लीजिये कि मंत्री के गांव में पांच ट्रक मछली डेली उतरता है या नहीं, आज दरभंगा में कम से कम 500 ट्रक मछली आता है, जहां से पहले 500 ट्रक दूसरे राज्य में जाता था, आप इसकी जांच करवा लीजिये। अगर हमारी बात पर आपको लगे कि असत्य हम बोल रहे हैं तो आप इसकी जांच करवा लीजिये कि आप कहां है विकास के पैमाने पर. (क्रमशः)

...क्रमश...

टर्न-13/मधुप/02.12.2021

..क्रमशः...

श्री ललित कुमार यादव : आज आपने शिक्षा विभाग का रखा, आप गृह विभाग का रखते । आज सारे हमारे बच्चे-बच्चियां कौन काम में लगे हुये हैं छात्र-छात्राएँ । लोग किस काम में लगे हुये हैं, लोग गलत काम में लगे हुये हैं । लॉ एण्ड ऑर्डर बिगड़ रहा है । आपके पूरे राज्य में लॉ एण्ड ऑर्डर बिगड़ रहा है । सभी पढ़ने वाले बच्चे, 8-10-11 क्लास के बच्चे कौन काम में लग गये हैं । आपको सारे बिन्दु पर ध्यान देना होगा, आप सरकार हैं। सरकार का दायित्व है । तीन सत्र से हमलोग देख रहे हैं, सप्तदश विधान सभा का यह चतुर्थ सत्र है, गृह विभाग का आप न प्रश्न लाते हैं, न आप गृह विभाग पर चर्चा कराते हैं । आज हमलोगों को प्रसन्नता होती अगर गृह विभाग पर, कानून-व्यवस्था की इस राज्य में क्या स्थिति है, इसपर चर्चा होती । यदि कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरती तो आप जरूर निश्चित रूप से गृह विभाग पर आज बहस करवाते । लेकिन आप गृह विभाग के बहस से, प्रश्न से आप भाग रहे हैं । क्यों भाग रहे हैं ? माननीय मुख्यमंत्री जी हैं सदन में बैठे हुये और माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के गृह मंत्री भी हैं, हमलोग उम्मीद करते थे कि मुख्यमंत्री जी अपना विभाग गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा कराते । लेकिन यह सारा गिलोटिन में है । आप गृह विभाग पर भी आज चर्चा करा सकते थे । आप सरकार हैं । अध्यक्ष महोदय, आप थोड़े ही अस्वीकृत कर देते । ये गृह विभाग पर चर्चा कराते । यह तो सरकार ने आपको कहा कि हम शिक्षा विभाग को ही अनुदान माँग के माध्यम से लाना चाहते हैं और शेष को गिलोटिन में ले आइये मुखबंद में । आपने मान लिया सरकार की सिफारिश को लेकिन महोदय, आपको भी गृह विभाग का राज्य का कानून-व्यवस्था क्या है, आप भी कहीं से जन-प्रतिनिधि हैं, देख रहे हैं और राज्य की सारी स्थिति को आप देखते हैं । राज्य की कानून-व्यवस्था....

(व्यवधान)

15 साल पहले आप नहीं आये थे इस सदन में । आप 15 साल पहले नहीं थे, इस सदन के सदस्य नहीं थे, सीखिये । हमलोग 15 साल पहले भी थे, लालू जी के भी राज में और नीतीश बाबू के भी राज में हमलोग हैं । आपका उस समय में राजनीतिक जन्म नहीं हुआ था । चुप रहिये ज्ञानू जी ।

अध्यक्ष : आप उधर देखकर नहीं, इधर देखकर बोलिये ललित जी ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : नाम ज्ञानू हो जाने से थोड़े ही हो जायेगा, ये सबसे अज्ञानी व्यक्ति हैं । बैठे-बैठे बोलते रहते हैं । इनका नाम है ज्ञानू और सबसे इस विधान सभा में अज्ञानी हैं । बैठे-बैठे बोलते रहते हैं । यदि ये 15 साल का याद दिलाते हैं तो इनको उठकर अध्यक्ष महोदय, आपसे परमीशन इजाजत लेनी चाहिये । बैठे-बैठे बोलते रहते हैं ।

अध्यक्ष : वे आपको भटकाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : 15 साल पहले विधान सभा में इनका जन्म हुआ था क्या ? 15 साल पहले यहाँ नहीं जन्मे थे, महोदय । ये बच्चा भी नहीं थे 15 साल पहले । इसलिये 15 साल की चर्चा ये नहीं करें सदन में, बाहर जाकर जो बोलना है, बोलें ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : आपसे उम्र में कम नहीं हैं, 62-63 साल हमारी उम्र है ।

(व्यवधान)

आपका 15 साल पहले जन्म नहीं हुआ था, बच्चे भी नहीं थे, चुप रहिये । विधान सभा के सदस्य आप नहीं थे । चुप रहिये, आपको अध्यक्ष ने इजाजत नहीं दी है। बैठाइये महोदय, ये क्या बोल रहे हैं ?

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री ललित कुमार यादव : दूसरे का समय खराब कर रहे हैं । बैठाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । टोका-टोकी मत करिये । माननीय सदस्य, बोलिये ।

श्री ललित कुमार यादव : इनको बोलना है तो परमीशन लेकर बोलें । ये बोले हैं 15 साल, 15 साल पहले इनका राजनीतिक जन्म भी नहीं हुआ था । ये विधान सभा के सदस्य नहीं थे, महोदय ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : आपसे पहले से राजनीति में हैं ।

अध्यक्ष : आप टोका-टोकी मत करिये । माननीय सदस्य, बोलिये । आप वीरेन्द्र जी, क्या-क्या सलाह देते हैं बगल में ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम अस्पताल की बात नहीं करें, हम स्कूल की बात नहीं करें, आखिर हम किसकी बात करें ? हम किनको कहें ? माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री और आप आसन सर्वोपरि हैं । आप हमारी पीड़ा नहीं समझेंगे, मुख्यमंत्री जी नहीं समझेंगे, हमलोग भी अपने लिये नहीं जनता के लिये कहते हैं और मुख्यमंत्री जी

कहते हैं कि जनता के किसी भी मामले में चाहे भ्रष्टाचार के मामले में हो या विकास के मामले में हो, हम कोई समझौता नहीं करेंगे । लेकिन हमलोग देखते हैं, प्रश्न भी हमलोग करते हैं, सरकार को इतनी हिम्मत नहीं होती है कि जॉच कराने का भी आदेश दें । जॉच में क्या है ? आप ही का पदाधिकारी जॉच करेगा । जॉच भी आश्वासन नहीं देते हैं । पोल खुल जायेगा, महोदय । ये जॉच नहीं करा सकते हैं । हम कहे थे, मदरसा बोर्ड के बारे में आपके समक्ष ध्यानाकर्षण लगाया । 100 करोड़ का घोटाला कर लिया, इनके लिए पाक-साफ है चूंकि इनकी पार्टी के सदस्य हैं इसीलिए पाक-साफ हैं और क्या-क्या काम करते हैं, आप पता लगा लीजियेगा । यानी जितनी बार जॉच होती है, उसका दोहन और शोषण होता है जॉच के नाम पर । हमलोग प्रश्न और ध्यानाकर्षण लाते हैं, उसपर दोहन और शोषण होता है । कौन करते हैं दोहन और शोषण, आप पता लगाइये । आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, हम न्याय के साथ विकास करते हैं, हम सुशासन बाबू हैं । महोदय, बहुत बात बोलेंगे सरकार को नाराजगी हो जायेगी, हम बहुत कड़वी बात नहीं बोलेंगे, बहुत कड़वी बात को हम छिपा देते हैं । महोदय, बहुत बात को रखना हमको नहीं लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी नाराज हो जायेंगे और कल हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी की नाराजगी हमको महँगा भी पड़ सकता है । इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं । लेकिन जनता ने हमको प्रतिनिधि बनाकर भेजा है और बिहार की जनता की जिम्मेवारी जितनी बिहार के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का है उतना ही विपक्ष का है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रतिपक्ष को हमेशा सजग रहना चाहिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम कह रहे हैं कि हमारे यहॉ मनिगाछी रेफरल अस्पताल है । उसका मकान 10 साल से जर्जर है, डॉक्टर नहीं बैठ रहा है । आप जॉच करा लीजिये, एक भी बात गलत बोल रहे हैं तो जॉच करा लीजिये और इसी सदन में एक रिपोर्ट मॅगाकर माननीय अध्यक्ष महोदय को दे दीजिये । एक डॉक्टर अन्दर नहीं बैठता है । महोदय, डी0एम0सी0एच0 उत्तर बिहार का यानी पी0एम0सी0एच0 के बाद डी0एम0सी0एच0 था, आज डी0एम0सी0एच0 में कुत्ता जाकर बैठा रहता है बेड पर, पेसेंट को बैठने लायक नहीं है । कब बिल्डिंग गिर जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हम कह रहे हैं आप सदन की कमिटी बना दीजिये, हम एक भी बात यदि गलत बोल रहे हों, हम ऑन द रेकर्ड बोल रहे हैं, सरकार को हिम्मत है तो

सभी बात की जॉच करा लें, कोई बात असत्य निकल जाय तो हम सदन में माफी मॉगने के लिये तैयार हैं । लेकिन अगर सरकार जॉच से भाग रही है तो सरकार को भी कटघरे में खड़ा होना चाहिये चाहे विधान सभा में चाहे जनता के बीच में जाना होगा । हम मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं रेफरल अस्पताल मनिगाछी है, दरभंगा जिला में डी0एम0सी0एच0 के बाद हमारा यह अस्पताल था, पहले 500 पेसेंट रोज आते थे और सभी विभाग के डॉक्टर थे । हम बहुत दिन पहले की बात नहीं कह रहे हैं, फिर कहियेगा कि 15 साल में चले गये, हम उसमें नहीं उलझना चाहते हैं । हम कहते हैं कि पता कर लीजिये, 2003, 2004, 2005 में विभागवार डॉक्टर थे । जिवेश मिश्रा जी मंत्री हैं, उनके यहॉ रेफरल अस्पताल है जाले में, विभागवार डॉक्टर थे, मंत्री हैं बोल दें, अभी हम बैठ जाते हैं, नहीं था तो बतावें और आज डॉक्टर नहीं है ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : पहले नहीं था, आज है । आज अल्ट्रासाउंड भी है और एक्स-रे भी होता है ।

श्री ललित कुमार यादव : मंत्री जी कह रहे हैं....

अध्यक्ष : आप न्यौता देकर क्यों बुलाते हैं ?

श्री ललित कुमार यादव : आप दोनों समय का रेकर्ड मॅगा लीजिये, कितना पेसेंट पहले आते थे और आज कितने पेसेंट आ रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप नाम लेकर न्यौता देकर क्यों बुलाते हैं ? बैठ जाइये ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : आज एक्स-रे मशीन भी लेटेस्ट लगा हुआ है, अल्ट्रासाउंड मशीन भी है । सभी विभाग में आज वहॉ डॉक्टर हैं, सभी प्रकार से साफ-सफाई जाकर देख लें । इनके समय में क्या हाल था ? यह तुलना ये मत करें ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : अब वे जवाब दे दिये । उनका नाम लिये थे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम सभी अस्पताल का कह रहे हैं, वहॉ के विधायक हैं इसलिये कह रहे थे । हम जाले अस्पताल का कह रहे थे, वहॉ के विधायक थे इसीलिये कहे । विभागवार डॉक्टर था । मेरे यहॉ रेफरल अस्पताल मनिगाछी है, एक विभाग में डॉक्टर नहीं है, आप पता कर लीजिये, जॉच कर लीजिये, मेरा मनिगाछी रेफरल अस्पताल दरभंगा में सेकंड अस्पताल था । यदि 5 पेसेंट भी रोज आते हों तो आप रेकर्ड मॅगवा लीजिये, वहॉ का रेकर्ड होगा कि कौन-कौन लोग अस्पताल में भर्ती हुये, उसका कौन-सा इलाज

हुआ । महोदय, 10 साल से ऐसे ही डॉक्टर का बिहटा रेफरल अस्पताल में हाल है । महोदय, स्वास्थ्य की यह बदहाल हालत है ।

शिक्षा के बारे में हमलोग कहॉ से शुरू करें और कहॉ अंत करें, शिक्षा विभाग में बदहाली में सुधार नहीं हो सकता है, वर्तमान सरकार के रहते हुए शिक्षा विभाग में सुधार नहीं हो सकता है । दिन-प्रतिदिन शिक्षा व्यवस्था में गिरावट हो रहा है, लूट हो रहा है । सब शिक्षक लोग की जो योग्यता पहले थी, बी0पी0एस0सी0 से शिक्षक आते थे, आज ए-बी-सी-डी लिखना नहीं आता है तो जो शिक्षक हैं, क्या पढ़ायेंगे विद्यार्थी को । तो यह शिक्षा व्यवस्था का हाल है ।

महोदय, मेरी ओर से तो शेष समय बचा है, पार्टी की ओर से नाम गया हुआ है, माननीय सदस्य बोलेंगे ।

टर्न-14/आजाद/02.12.2021

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि विहपुर विधान सभा की जनता की ओर से आपने मुझे बोलने का मौका दिया है । वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शिक्षा विभाग से संबंधित द्वितीय अनुपूरक में अनुदान की मांग के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, सबसे पहले मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और विद्वान मृदुभाषी शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने जब पूरे विश्व में कोविड का महामारी था, पूरा विश्व त्रस्त था, हमारा भारत भी त्रस्त था और उसमें बिहार भी त्रस्त था। उस समय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री सफल रूप से जो आज देश में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, उसके माध्यम से हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम किया है । चूँकि उस समय कोई बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कोई परिवार घर से बाहर नहीं निकल पाता था । बच्चे सोच कर, चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर पाते थे । हमारी सरकार ने उन बच्चों को, उन नौनिहालों को पढ़ाई लगातार सम्पर्क में रखा और आज तो हम कोविड से निकल चुके हैं । आदरणीय ललित बाबू चले गये महोदय, पहले घोटालों की सरकार हुआ करती थी, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, कौन-कौन घोटाला था महोदय और उस घोटाले वाले हमें आज शिक्षा दे रहे हैं । आज हमारे ललित बाबू कह रहे थे ज्ञानू जी को कि आप बच्चे हैं । हमारे तरफ के बच्चे ही आपके महारथी को भी हराने का काम किया है महोदय । आपके महारथी ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा राजद के थे बुलो मंडल जी, उसको मैं

हराकर आया हूँ । आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और आप हमलोगों को बच्चा कहते हैं । हमारे यहां पहले शिक्षा की क्या स्थिति थी, ललित यादव जी कह रहे थे कि पहले जो है शिक्षा में जब लालू यादव, राबड़ी देवी जी थी तब का और अब का । हमको महोदय ....

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ ।

अध्यक्ष : बोलिए, क्या है व्यवस्था ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, ये चूँकि नाम लेकर बोले हैं, हम इनको चुनौती देते हैं, लालू जी के समय में जो बी0पी0एस0सी0 से जो शिक्षकों की बहाली हुई और इस राज में जो शिक्षकों की बहाली हुई, दोनों में गुणवत्ता की जॉच करा लें, यदि जॉच में बी0पी0एस0सी0 अगर फर्स्ट नहीं करेगा तो आप कहियेगा ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, आज शिक्षा विभाग पर बोलना है । आज शिक्षा का स्तर कहां से कहां चला गया । पहले जब बिहार में कोई घुसता था तो गड्ढ़ा से भरा रोड को देखता था और आज लाल ब्लिडिंग को देखकर कह देता है कि हम बिहार में प्रवेश कर गये हैं । ये लालू जमाने के रोड की बात करते हैं । उस वक्त गड्ढ़ा में रोड हुआ करता था, उनके नाम से जाना जाता था और आज चमकती हुई सड़क, लहलहाती हुई हमारी बेटी जब साईकिल से पढ़ने के लिए जाती है तो कहा जाता है कि यह नीतीश कुमार की बिहार है ।

महोदय, ये कहते हैं कि अस्पताल में कोई नहीं, आज क्या स्थिति है, 3 हजार से 4 हजार, प्रत्येक प्रखंड के अस्पतालों में 200 से अधिक दवाईयां मिलती है । ये कहते हैं कि हमारे यहां कुछ व्यवस्था नहीं है । मित्रों, इनको कहने के लिए कोई जगह नहीं है। इनको बोलना नहीं चाहिए, आज हमारी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है । ये आज सदन में आंकड़ा दे रहे थे । शिक्षा विभाग का आंकड़ा दे रहे थे, हम तो इनको चुनौती देते हैं महोदय, ये चुनौती क्या देंगे ? हमारे पास आकंड़ा है, हमारे पास मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में 64 करोड़ रू0 दिया गया है । ये अपने समय का देखें, ये जब अपना बजट बनाते थे, उस वक्त क्या बजट था शिक्षा विभाग का, आप तो चरवाहा विद्यालय खोलना चाहते थे, हमारी सरकार .....

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : हमारी सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी शिक्षा मंत्री के बारे में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है महोदय । हमारे मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में 20 करोड़ रू0 प्रोत्साहन राशि दिया है । हमारे मुख्यमंत्री जी ने बालिकाओं के लिए जिस बालिका को आप देखकर के तिरस्कृत करते थे, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री बालिकाओं

को पढ़ने के लिए, आप बोलिए मत, बैठिए आपलोग, आपके कार्यों को सब जनता ने देखा है । आपने पिछले 15 वर्षों में क्या किया था, कम से कम जनता को मत बुड़बक बनाईए । ये लोग दादागिरी करके, बाहुबली बनकर के विधायक बनकर आते हैं । आपलोग वोट से थोड़े विधायक बनकर आते हैं और यहां पर आकर बोलते हैं । मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में, इसमें बालिकाओं के लिए 363 करोड़ रू0 प्रोत्साहन राशि दिया गया है । इस तरह से सारी योजनाओं में 8 करोड़, 47 करोड़, 30 करोड़, 93 करोड़ महोदय, ये लोग केवल और केवल महोदय, अपनी बात को बिना आंकड़े के यहां पर रखते हैं । इसलिए मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ । पहले महोदय, हमारी बहनें, हमारी बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी । आज क्या है, आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां साईकिल से फराफराती हुई स्कूल जाती है । इनको अच्छा नहीं लगता है । पूरे देश में इस योजना की सराहना की जा रही है । आज हमारी बेटियों की शिक्षकों में बहाली हो रही है, हम धन्यवाद अपने शिक्षा मंत्री को भी देना चाहते हैं । हमारे यहां विद्यालयों में अपना भवन नहीं रहता था । आज क्या है, सभी जगहों पर अपना भवन है, सभी विद्यालयों में शिक्षक हैं, सभी जगहों पर आज पढ़ाई हो रही है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ, हमारे यहां .....

अध्यक्ष : ध्यान से सुनिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां अपने विहपुर विधान सभा में 37 पंचायत है और पहले कहीं भी शिक्षक नहीं रहते थे । इनके शासन काल में जब दोनों सरकारें इनकी थी, विद्यालय नहीं था, आज 37 पंचायतों में विद्यालय लहलहा रहा है महोदय । कोविड काल में भी उस वक्त हमारे शिक्षा मंत्री ने अपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है और उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके दूरदर्शन से और मोबाईल ऐप के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया है । आज जो स्थिति है, उसकी तो कम से कम सराहना करते महोदय ।

अन्त में मैं अपनी बात विहपुर विधान सभा में कुछ समस्यायें हैं, उसको मैं बता देना चाहता हूँ । मेरे यहां 4 हाईस्कूल में चार-चार कमरा और बरामदा दिया गया है लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय हैं, जैसे हमारे यहां तुलसीपुर हाईस्कूल है, हम अपने शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । बहुत ही गौरवशाली स्कूल है, उस विद्यालय में थोड़ा आपकी महती कृपा हो जाय और लोकमानपुर विद्यालय का जो कोड मिलता है, सरकार के माध्यम से वह कोड प्राप्त नहीं हुआ है । उस कोड को भी आप वहां पर

जल्द से जल्द देने का काम करने की कृपा करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

टर्न-15/शंभु/02.12.21

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा की चर्चा पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । निश्चित रूप से हमारे बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत गौरवशाली इतिहास था । यहां नालन्दा, विक्रमशीला जैसा विश्वविद्यालय हुआ करता था । यहां न केवल बिहार बल्कि पूरी दुनिया से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे और मध्यकाल में भी शिक्षा की स्थिति अच्छी ही रही और उस परंपरा को लोग लेकर चले । आजादी के बाद लगातार देखने को मिला है कि गिरावट आयी और शिक्षा के स्तर में यह कहा जा सकता है कि जो गौरवशाली इतिहास था कहीं-न-कहीं क्षीण हुआ । 1990 में लालू प्रसाद जी का शासन आया आजादी के 43 साल के बाद लोग बताते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया । आजादी से पहले भी कुछ युनिवर्सिटी बिहार में था और आजादी के बाद 43 साल में मुश्किल से तीन-चार युनिवर्सिटी की स्थापना की गयी, लेकिन लालू प्रसाद जी 43 साल आजादी के बाद जब आये तो उन्होंने बिहार में कम युनिवर्सिटी की संख्या को बढ़ाने की दिशा में बेहतर करने का काम किया । उन्होंने छपरा में जे0पी0 युनिवर्सिटी की स्थापना की, उन्होंने बी0पी0 मंडल युनिवर्सिटी की स्थापना की, उन्होंने वीर कुंवर सिंह युनिवर्सिटी की स्थापना की, उन्होंने विनोबा भावे युनिवर्सिटी की स्थापना की, उन्होंने मजहरूल हक अरबी फारसी युनिवर्सिटी की स्थापना की, उन्होंने नालन्दा विश्वविद्यालय को प्रोपर वे में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । यह काम जो पिछले 40-50 साल में हुआ था वह पांच सात वर्षों के शासनकाल में एक व्यापक बदलाव देने का काम किया । जो लोग आज बात कर रहे हैं क्या अपने 15 साल, 17 साल के शासन में मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी बहुत नजदीकी हैं, हमलोगों के आदरणीय हैं हम यह जानना चाहेंगे कि 17 साल के शासनकाल में, 16 साल के शासनकाल में कितनी युनिवर्सिटी को जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने दुगुना किया इन्होंने जितना युनिवर्सिटी मिला था उसको दुगुना करने का काम किया कि नहीं । दूसरी तरफ जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था थी उस समय 1991 से 2001 जब पूरे देश में साक्षरता की जो वृद्धि दर थी वह 23 प्रतिशत थी लेकिन उस दस साल के कार्यकाल में 27 प्रतिशत- राष्ट्रीय औसत 23 प्रतिशत था और बिहार का 27 प्रतिशत अप्रत्याशित वृद्धि प्रमाणित किया है कि बिहार में किस तरह से बदलाव हुआ है । आपने देखा सही बताया कि बी0पी0एस0सी0 के माध्यम

से शिक्षकों की बहाली की गयी, दलितों के लिए आवासीय विद्यालय खोले गये, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास पूरे बिहार में खोले गये, तमाम एक रूपये की व्यवस्था की गयी ताकि गरीब के बच्चे एक रूपये की लालच में स्कूल में आएं । चरवाहा विद्यालय जिसके बारे में लोग मजाक उड़ाते हैं उसका युनिसेफ ने प्रशंसा किया जो पूरे विश्व का प्रतिष्ठित संस्थान है । उन्होंने प्रशंसा किया कि गरीबों को किस तरह से आकर्षित किया जाता है । ये लोग तो कल खिचड़ी की जो व्यवस्था है उसका भी मजाक उड़ायेंगे कि खिचड़ी खिलाकर बुलाया जा रहा है । ये नहीं जानते हैं कि गरीब गुरूबा शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं उन्हें तरह-तरह से स्कूल की ओर आकर्षित किया जाता है । अब आते हैं वर्तमान सरकार है अभी 16 साल हो गये सरकार को लगातार नये मंत्री तो अभी आये हैं इसलिए इनपर विशेष रूप से नहीं । 16 साल से यह सरकार है इस बार भी बजट में इन्होंने 38 हजार करोड़ रूपये का बजट इस वित्तीय वर्ष में लिया है, पिछले बार भी 35 हजार करोड़ का बजट लिया । पूरे बजट का 17-18 प्रतिशत एक बड़ा हिस्सा यह मांगते हैं और कहते हैं कि बिहार में हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, बेहतर शिक्षा देंगे, बिहार को देश के सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में लायेंगे । यह सब मीठी-मीठी बातें करके हर बार लाखों करोड़ लगभग डेढ़ से दो लाख करोड़ रूपया पिछले 15 साल में सदन से स्वीकृत कराया । आज स्थिति क्या है बिहार की शिक्षा का किसी से छिपा नहीं है । बिहार पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, दसवें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है सबसे अंतिम पायदान पर है । नीति आयोग की ही रिपोर्ट नहीं पूरे देश का जितना भी आंकड़ा है तमाम आंकड़ों में बिहार सबसे फिसड्डी साबित हुआ है । असर का रिपोर्ट है एक, असर का रिपोर्ट जो पूरे देश में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट करता है । उसने यह बताया, हर साल बताता है उसने भी बताया कि यहां पाचवां में पढ़नेवाले 50 प्रतिशत बच्चे दूसरे क्लास की किताब को नहीं पढ़ पाते हैं । असर के रिपोर्ट में यह भी बताया कि यहां आठवां क्लास में पढ़नेवाले 50 प्रतिशत बच्चे गुणा और भाग करना नहीं जानते । यह अपने आप में शर्मनाक है । यह हम नहीं कह रहे हैं कहीं नीति आयोग कह रहा है, देश की असर संस्था कह रही है, तमाम तरह की संस्थाएं हैं जो कह रही है । यह हम नहीं कह रहे हैं यह पब्लिक अफेयर इन्डेक्स, पब्लिक का अफेयर इन्डेक्स भी बताता है कि बिहार आखिरी पायदान पर है और संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है सेनेटेबल डेवलपमेंट गोल वह भी कहता है कि बिहार पूरे देश में अंतिम पायदान पर है । एक नहीं दर्जनों गिना सकते हैं कि तमाम पारामीटर या इन्डेक्स जो जारी होता है वह बताता है । अब ये लोग कहते हैं कि वह पारामीटर ही गलत है, नीति

आयोग ही गलत है, तमाम तरह की चीज है । अब एक आंकड़ा हम बताना चाहते हैं हम जानते हैं कि ज्यादा समय बातों में नहीं जाए । 18 से 23 वर्ष आयु के लगभग 1 करोड़ 15 लाख आबादी बिहार की है जो 18 साल से 23 साल के हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में कितने हैं मात्र 15 लाख - मतलब 1 करोड़ बच्चे बिहार के जो 18 साल से 23 साल के हैं वह स्कूल से बाहर हैं आखिर 15 साल, 16 साल के शासन में यह कैसी व्यवस्था हुई जो 1 करोड़ नौजवान जो 18 साल से 23 साल के हैं वे स्कूलों से बाहर हैं । दूसरा एक आंकड़ा हम देना चाहते हैं कि 2009 में 27 लाख बच्चे नामांकन लेते हैं और दस साल के बाद जब बोर्ड की परीक्षा होती है तो मात्र 17 लाख बच्चे एपीयर होते हैं तो दस लाख बच्चे कहां गये ? नामांकन लिये 27 लाख और जब बोर्ड की परीक्षा होती है तो उसमें मात्र दस लाख बच्चे आते हैं । ऐसे बहुत सारे हैं । आर0टी0इ0 जो कहता है कि आखिर क्या वजह है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी बदतर है । महोदय, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था उसके तहत यह बताया जाता है कि यहां पर जो शिक्षकों का अनुपात होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर का रेशियो होना चाहिए- प्राथमिक स्तर पर 26, माध्यमिक स्तर पर 21 होना चाहिए, इसी तरह से उच्च माध्यमिक है, लेकिन बिहार में क्या स्थिति है । 60-70 बच्चे पर एक शिक्षक हैं अब एक शिक्षक 70 बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं । ये कैसे दावा कर सकते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का काम करेंगे । इसी तरह से शिक्षक की कमी- शिक्षक के स्वीकृत पद अभी बिहार में 3 लाख 15 हजार है जिसको ये कई वर्षों से कह रहे हैं कि भरेंगे-भरेंगे । हमलोग दस साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उस दिशा में कारगर कार्रवाई नहीं हुई । 3276 प्रारंभिक स्कूल हैं जहां मात्र एक शिक्षक काम कर रहे हैं और 12507 ऐसे स्कूल हैं जहां मात्र दो शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रहा है । कहीं-कहीं 300 बच्चे हैं और एक या दो शिक्षक के भरोसे चल रहा है । आप कैसे नीति आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं । उसी तरह से अभी एक मामला है कि स्कूल सब शिफ्ट कर रहे हैं । सरकार की योजना थी कि प्रत्येक इलाके में हम स्कूल देंगे उसी हिसाब से स्कूल बिहार में खुला । अभी एकाध महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने और उसमें कहा है कि तमाम हम ऐसे स्कूल को बगल के टोले में शिफ्ट करेंगे । मतलब क्या है एक कि0मी0, दो कि0मी0, क्या सरकार की मंशा थी कि वहां पर टोले के बसावट हैं- इसलिए हम कहेंगे कि मंत्री जी गौर करें, बगल के विद्यालय का मतलब एक कि0मी0, दो कि0मी0 दूर होता है लेकिन सरकार को ऐसा प्रसास करना चाहिए कि घर से निकले बगल में विद्यालय मिले । तमाम ऐसे स्कूलों

को बगल में शिफ्ट करने की योजना की जा रही है, उसपर काम भी चल रहा है । अभी केन्द्रीय मंत्रालय एक रिपोर्ट जारी किया है, ग्रेडिंग दिया है उसमें ए प्लस, प्लस की व्यवस्था है, ए प्लस की व्यवस्था है, ए ग्रेड, बी ग्रेड बिहार को सबसे अंतिम ग्रेड तीसरा ग्रेड में दिया है भारत सरकार का एक आंकड़ा है जो मेरे पास है । स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं रहने के कारण कहां से तीन सौ, दो सौ बच्चे बैठेंगे । आप किसी भी मीडिल, हाइस्कूल में जाइये । हाइस्कूल में 8 सौ, 9 सौ, 1 हजार बच्चे होते हैं और तीन, चार, पांच कमरे उसमें क्या होगा । एक में प्रिंसिपल बैठते हैं, एक में तमाम टीचर बैठते हैं, स्टाफ रूम होता है बच्चे कहां बैठेंगे । एक रूम, दो रूम में चल रहा है लगातार । मंत्री जी समस्तीपुर जिला से आते हैं मैं नाम गिना सकता हूँ कि हरिशंकरी उच्च विद्यालय है, कृष्णा उच्च विद्यालय जितवारपुर में है, धर्मपुर उच्च विद्यालय है बाकी उच्च विद्यालय है जाकर देखिए तीन कमरे में चल रहा है एक हजार बच्चे हैं, बगल के हैं कम से कम वहां देखने से पता चलेगा और समस्याएं दूर होगी । महोदय, उसी तरह से उच्च शिक्षा के बारे में क्या बताना वाइस चांसलर का रिपोर्ट पूरी दुनिया में जगहंसाई हो रहा है । अब ये कहेंगे कि वाइस चांसलर से हमें क्या मतलब है । उसके चयन में सरकार के प्रतिनिधि होते हैं मुख्यमंत्री जी की सलाह होती है । आखिर दूसरे प्रदेशों से क्यों लाया जाता है वाइस चांसलर को बिहार में शिक्षाविदों की कमी है क्या ? बिहार में अच्छे लोगों की, ईमानदार लोगों की कमी है क्या ? वैसे लोगों को लाते हैं जो बिहार को बदनाम करता है, समाचार अखबारों के फर्स्ट पृष्ठ पर छप रहा है । कौन वी0सी0, कौन वी0सी0 इस तरह का गंभीर आरोप यहां तक कि पैसे की बरामदगी हो रही है और ये राजभवन पर फेंकते हैं, लेकिन एकाउन्टेबिलिटी सरकार की होती है, एकाउन्टेबल मुख्यमंत्री हैं, सरकार है । जनता आपसे पूछेगी । आप उसमें हिस्सेदार हैं, आपके राय, विचार, मशविरे से कोई भी वी0सी0 बनता है ।

क्रमशः

टर्न-16/पुलकित/02.12.2021

(क्रमशः)

श्री अख्तरूल ईस्लाम शाहीन : इसलिए गंभीर मामला है, इस पर भी आना चाहिए । यहां तक कि उच्च शिक्षा की स्थिति है सिर्फ जाइये, नामांकन लीजिये, डिग्री लीजिये । 10 प्रतिशत से ज्यादा शिक्षक नहीं हैं । अभी भी 80 प्रतिशत शिक्षकों की आवश्यकता है पिछले 10 साल से जो भी मंत्री सामने बैठते हैं कहते हैं कि प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही

है । कैसे शिक्षा होगी लोग नामांकन ले रहे हैं, परीक्षा देकर डिग्री ले रहे हैं । पूरे बिहार की तमाम यूनिवर्सिटी का मैं डाटा दे सकता हूं कि कितने-कितने स्वीकृत पद हैं और ये दस साल से जवाब दे रहे हैं कि प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया हो रही है और कहीं भी नहीं है । बिना शिक्षक के बिहार में कैसे उच्च शिक्षा की कल्पना कर सकते हैं । पी0जी0 की पढ़ाई कितनी जगह है- समस्तीपुर में 50 लाख, 45 लाख, 40 लाख की आबादी है । एक से दो कॉलेजों में पढ़ाई होती है । आपका एक मानक होना चाहिए कि दो लाख, तीन लाख की आबादी पर पी0जी0 की पढ़ाई देंगे । हरेक अनुमंडल के एक कॉलेज में देंगे । कहां इतना पीछे चल रहा है दूसरी तरफ अब तो इनको प्रोफेशनल डिग्री की तरफ आना चाहिए कि अब कॉलेजों में प्रोफेशनल डिग्री दें । जो एम0बी0ए0, बी0बी0ए0 कहां गरीब का बच्चा करेगा उसमें लाख, दो लाख रुपया लगता है । तमाम वैसे इंस्टीट्यूट हर जिले में एक दो कॉलेज को देना चाहिए जहां बी0बी0ए0 हो, एम0बी0ए0 हो, बी0सी0ए0 हो इस तरह की डिग्री का हम प्रस्ताव करेंगे । मंत्री इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि तमाम इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री की भी व्यवस्था करेंगे । समस्तीपुर में जीतन राम मांझी जी शायद नहीं हैं वे आठ करोड़ रुपया बी0आर0बी0 कॉलेज को दिये थे और उसमें दो करोड़ रुपया बच गया था जो वापस ले लिया गया जबकि उसमें लिफ्ट वगैरह बहुत सारी चीजों का काम होना है । हम अनुरोध करेंगे माननीय मंत्री जी से बी0आर0बी0 कॉलेज का पैसा लौटा है उसको वापस करवा दिया जाय और दूसरी तरफ देखते हैं कि उर्दू के लिए इन लोगों का व्यवहार उलटा रहता है । शुरू से ही एक व्यवस्था बिहार में चली आई है कि किसी भी उच्च विद्यालय में छह शिक्षक कंप्लसरी किये गये थे जिसमें मैथ के शिक्षक, सांइस के शिक्षक और सोशल साइंस के शिक्षक, इंग्लिश के हिन्दी के ये कंप्लसरी थे लेकिन अभी वर्तमान में पता नहीं माननीय मंत्री जी जबकि उर्दू को चाहने वाले हैं, बोलने वाले हैं उसके बावजूद उर्दू के प्रति यह व्यवहार देखने को मिल रहा है । कई बार सदस्यों ने इन बातों को उठाया है जो कंप्लसरी हैं, अनिवार्य हैं उसको बरकरार रखा जाय । उसके बाद ही यह किया जाय क्योंकि कोई भी भाषा किसी जाति विशेष की नहीं होती है, जिस दृष्किोण से देखा जाय । अभी बंग्ला, बंग्ला वाला देख रहे हैं लगातार धरना दे रहे हैं, उर्दू-बंग्ला के लोग धरना पिछले कितने दिनों से दिये हुए हैं और आठ साल से, दस साल से ये लोग टहला रहे हैं । कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह की व्यवस्था की गयी कि आपकी गलती थी, आपने गलत तरह का क्वैश्चन किया था, क्वैश्चन था उसमें तो ये व्यवस्था कई राज्यों में ऐसी हुई है इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वैश्चन गलत हुए हैं, तो उसका

कोपभाजन बच्चों को नहीं भुगतना पड़ा है, उसको एडजेस्ट किया है । इसलिए मांग करेंगे कि सरकार जनरल टी0ई0टी0 की तरह 10 परसेंट छूट जो दी है उसमें राजस्थान है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल कई राज्यों में इस तरह की प्रॉबल्म आई इसलिए किये । उपाध्यक्ष जी, एक मिनट में, एक गंभीर समस्या है यह है कि एक संकल्प संख्या 162 है, इसमें इन लोगों ने कहा था कि हम सरकारी शिक्षक और मदरसा के शिक्षक को इक्वीलेंट दर्जा तमाम चीजों में देंगे लेकिन उस संकल्प के हिसाब से काम नहीं हो रहा है । वेतनभत्ता तमाम तरह की जो शिक्षा, स्वास्थ्य है उस दिशा में भी काम नहीं हो रहा है और...

उपाध्यक्ष : श्री ललित नारायण मंडल ।

श्री अख्तरूल ईस्लाम शाहीन : टीचर पर भी किया जा रहा है । इसलिए हम चाहेंगे कि समान काम, समान वेतन और फोर्थ ग्रेड से भी कम स्तर का शिक्षक को दर्जा दिया जा रहा है । फोर्थ ग्रेड से भी कम पैसा शिक्षकों को दिया जा रहा है । इस तरह का डिस्क्रियेशन होगा तो कैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा । इसलिए हम अपेक्षा करते हैं...

उपाध्यक्ष : बैठिये माननीय सदस्य ।

श्री अख्तरूल ईस्लाम शाहीन : कि जो डिस्क्रियेशन हो रहा है । फोर्थ ग्रेड से भी बदतर स्थिति में बिहार के शिक्षक लोग हैं, नियोजित शिक्षक हैं उन पर ध्यान दिया जाय और उनको समान काम के लिए समान वेतन दिया जाय । इन्हीं चन्द बातों के साथ समाप्त करते हुए हम आसन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री ललित नारायण मंडल ।

श्री ललित नारायण मंडल : धन्यवाद, सर । आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हम वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शिक्षा विभाग से संबंधित द्वितीय अनुपूरक में अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़े हुए हैं । महोदय, मैं सभापति जी का, अपने शिक्षा मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का और अपने मुख्य सचेतक श्रवण बाबू जी का शुक्रगुजार हूं कि हमको विधान सभा में द्वितीय अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलने के लिए मौका मिला है । महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 में शिक्षा विभाग के लिए स्कीम एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत विभिन्न मदों में द्वितीय अनुपूरक आगणन से कुल 77,46,20,80,000/- (सतहत्तर अरब छियालीस करोड़ बीस लाख अस्सी हजार) रुपये प्रावधानित करने का प्रस्ताव उपस्थापित है जिसका मैं समर्थन करता हूं और इसका विवरण इस प्रकार है । मित्रों, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कर्मियों के वेतन, सेवान्त लाभ, बकाया वेतन एवं सातवां वेतन पुनरीक्षण के

फलस्वरूप बकाये वेतनान्तर के लिए 5,45,08,00,000/- (पांच अरब पैंतालीस करोड़ आठ लाख) रुपये एवं सार्वजनिक पुस्तकालय एवं प्राधिकार में कार्यरत पदाधिकारियों, कर्मियों के बकाये वेतन में 50,00,000/- (पचास लाख) रुपये का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । साथियो, वित्त सम्पोषित महाविद्यालयों को तीन सत्रों का बकाया अनुदान देने हेतु 8,84,00,00,000/- (आठ अरब चौरासी करोड़) रुपये का सहायक अनुदान एवं राजकीय संस्कृत विद्यालय में सेवानिवृत्त, कार्यरत शिक्षकों के लिए, कर्मियों के बकाये वेतन के लिए 61,00,000/- (एकसठ लाख) रुपये का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम तीन माह में कोविड-19 के कारण राशि की निकासी नहीं हो सकी । इसलिए राज्य के प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति हेतु एन0बी0पी0डी0सी0एल0 एवं एस0बी0पी0डी0सी0एल0 को भुगतान हेतु 29,28,66,000/- (उनतीस करोड़ अठाईस लाख छियासठ हजार) रुपये एवं राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न नगर निकाय एवं जिला परिषद निकाय के नियोजित शिक्षकों के 200 रुपये प्रति माह की दर से यू0टी0आई0 पेंशन हेतु 2,19,14,000/- (दो करोड़ उन्नीस लाख चौदह हजार) रुपये का द्वितीय अनुपूरक व्यवस्था का प्रस्ताव है । इसमें राज्य योजना के अनुसार मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना हेतु राज्य सरकार योजना अन्तर्गत 41,75,00,000/- (इक्तालीस करोड़ पचहत्तर लाख) रुपये राशि की आवश्यकता है । मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना हेतु राज्य योजना अंर्तगत 54,72,00,000/- (चौवन करोड़ बहत्तर लाख) रुपये राशि की आवश्यकता है । मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना (सैनेटरी नैपकिन) हेतु 16,56,00,000/- (सोलह करोड़ छप्पन लाख) रुपये की आवश्यकता है । बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना हेतु 1,23,00,00,000/- (एक अरब तेईस करोड़) रुपये की आवश्यकता है । मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना (सात निश्चय) हेतु 6,35,27,00,000/- (छः अरब पैंतीस करोड़ सताईस लाख) रुपये की आवश्यकता है । मुख्यमंत्री प्रोत्साहन/छात्रवृत्ति योजना हेतु राज्य योजना अंतर्गत 61,95,00,000/- (ईकसठ करोड़ पंचानवे लाख) रुपये की आवश्यकता है । मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना (सात निश्चय) हेतु 4,33,50,00,000/- (चार अरब तैंतीस करोड़ पचास लाख) रुपये की आवश्यकता है । इस प्रकार उक्त स्कीमों के अंतर्गत टोटल 13,66,75,00,000/- (तेरह अरब छियासठ करोड़ पचहत्तर लाख) रुपये उपलब्ध कराने हेतु द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । साथियो, समग्र शिक्षा अभियान (प्रारम्भिक) हेतु राज्य

योजना अंतर्गत प्राथमिक, मध्य विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के वेतनादि व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कम राशि प्राप्त होने के कारण राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के वेतन में 15 प्रशित वृद्धि करने के निर्णय के फलस्वरूप ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में 32,43,79,00,000/- (बत्तीस अरब तेतालीस करोड़ उन्नासी लाख) रुपये ....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कन्क्लूड कीजिये ।

श्री ललित नारायण मंडल : अनुपूरक व्यवस्था का प्रस्ताव है । राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को विकास की सहायता मद में कुल 1,49,30,00,000/- (एक अरब उन्चास करोड़ तीस लाख) रुपये की आवश्यकता है । उसी तरह माध्यमिक विद्यालयों के लिए 91,47,00,000/- (इक्यानवे करोड़ सैंतालीस लाख) रुपये की आवश्यकता है । उसी प्रकार केन्द्र प्रयोजित योजना, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान (माध्यमिक), (प्राथमिक) और समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षक शिक्षा)... (क्रमशः)

टर्न-17/अभिनीत/02.12.2021

-क्रमशः-

श्री ललित नारायण मंडल : शिक्षक शिक्षा, मध्याह्न भोजन, प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत..

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए माननीय सदस्य ।

श्री ललित नारायण मंडल : एक मिनट महोदय । 14 अरब 35 करोड़ 23 लाख रुपया प्रावधान करने की व्यवस्था अनुपूरक से है ।

मित्रो, मैं यह कहना चाहता हूं कि इतनी राशि के लिए हमारे विद्वान शिक्षा मंत्री ने बिहार के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए जो अनुपूरक की आवश्यकता पड़ी है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और हम सदन से आग्रह करेंगे कि सदन हमारे शिक्षा विभाग को इस द्वितीय अनुपूरक मांग को स्वीकृत करने की कृपा करें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री भूदेव चौधरी जी । पांच मिनट समय है आपका ।

श्री भूदेव चौधरी : सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपके प्रति आभार अभिव्यक्त करता हूं ।

मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और जिस विभाग के विषय में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं वह शिक्षा विभाग है जिसको मानव

संसाधन विभाग भी कहा जाता है । सच यही है कि मानव संसाधन विकास और विभाग के माध्यम से ऐसी शिक्षा, ऐसी दीक्षा मिले जिससे कि यहां के नौजवानों को रोजगार मिले लेकिन मुझे लगता है कि 15-20 वर्षों में इस व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि ऐसी व्यवस्था हो गयी है जिससे बेरोजगारी और बढ़ रही है । पूज्य बापू महात्मा गांधी ने कहा था कि करोड़ों लोगों का निरक्षर रहना इस देश के लिए कलंक और अभिशाप है इससे मुक्ति पानी ही होगी लेकिन दुर्भाग्य यह है और मैं भारी मन से कहना चाहता हूं कि व्यवस्था इतनी चरमरा गयी है कि आज गांव में जो सरकारी विद्यालय है, चूंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं मैंने नजदीक से देखा है वहां अगर एक सौ बच्चे प्रथम वर्ग में एडमिशन लेते हैं तो हाईस्कूल जाते-जाते 48 प्रतिशत बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं । थपथपा रहे थे पीठ अपनी, सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने वहां साईकिल की व्यवस्था की है, पोशाक की व्यवस्था की है । मैं उसका विरोधी नहीं हूं मैं कहता हूं कि और दो-तीन साईकिल दी जाय, पोशाक की और बढ़ोतरी कर दी जाय । कुछ लोग कह रहे थे भोजन की व्यवस्था हुई है अब नाश्ते की व्यवस्था होगी । मैं इसका विरोधी नहीं हूं मैं कहता हूं कि नाश्ते के साथ दाल में एक चम्मच घी भी दिया जाय लेकिन मकसद क्या है इसका ? इसका मकसद, इसका उद्देश्य यह था कि जब बच्चे को खुराक मिलेगी, उन गरीब बच्चों के मां-बाप के पास वह औकात नहीं है कि वह बच्चे को लंच पैकेट दे सकें तो वह स्कूल जायेगा वहां भोजन करेगा, नाश्ता करेगा और उसको समुचित शिक्षा मिलेगी जिसके चलते उसका भविष्य उज्ज्वल होगा ।

आज सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं जो निरीह हैं, जो नि:सहाय हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो ठेला चालक हैं, जो किराने की दुकान चलाते हैं, जो खेतों में कुदाल चलाते हैं उसके बच्चे पढ़ते हैं । आह लगती है, हीन भावना पैदा होती है जब सरकारी स्कूल के बगल में प्राइवेट स्कूल है । मुझे दु:ख होता है कि आज 35 से 40 हजार प्राइवेट स्कूल खुल गये और वैसी जगह खुल गये जहां सरकारी विद्यालय हैं । शाम के समय में जब छुट्टी होती है और प्राइवेट स्कूल के बच्चे जब निकलते हैं तो उसकी पीठ पर एक काला बैग, उसके बाल सुधरे हुए, पैर में काला जूता, उजला मौजा, लंच पैकेट से भरा हुआ बैग, जब गरीब बच्चे, जब सरकारी स्कूल में छुट्टी होती है उसके पांव धूल-धुसरित होते हैं, उनके पांव उछरे होते हैं, उसकी कमीज का बटन टूटा होता है, उनके अंदर हीन भावना पैदा होती है । वह सोचता होगा कि काश अगर मेरी भी व्यवस्था अच्छी होती तो मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता, यह स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

डॉ0 कलाम, जो भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था कि अगर गरीबी से निजात पाना चाहते हो, अगर मजबूरी और बेरोजगारी से मुक्ति पाना चाहते हो उसका एक ही हथियार है और उस हथियार का नाम है शिक्षा । लेकिन 15 वर्षों में उस हथियार की धार मुड़ गयी है, वह भोथर हो गया है, शिक्षा की स्थिति खराब हो गयी है । हमलोग भी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, हमलोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं जिस दिन डिप्टी इंस्पेक्टर के आने की सूचना मिलती थी सर लोग तो चौकस होते ही थे बच्चों को भी चौकस करते थे कि डिसिप्लिन मेनटेन करना, अनुशासित रहना, शिष्ट रहना, सभ्य रहना, देखना डिप्टी इंस्पेक्टर आ रहे हैं कुछ ऊल-जलूल न बोल देना । उस समय जब डिप्टी इंस्पेक्टर आते थे तो सीधे क्लास रूम जाते थे और लड़कों से पूछते थे टेबुल का स्पेलिंग क्या होता है, टीचर का स्पेलिंग क्या होता है ये सारी चीजों की जानकारी वो लेते थे लेकिन दुर्भाग्य है सभापति महोदय आज जब डिप्टी इंस्पेक्टर आते हैं तो क्लास रूम नहीं जाते, वे वर्ग देखने नहीं जाते बल्कि ऑफिस जाते हैं । उस आफिस में पठन-पाठन की कोई बात नहीं होती, उपस्थिति की कोई बात नहीं होती, छात्रों की स्थिति की कोई बात नहीं होती सिर्फ और सिर्फ यह बात होती है कि बताओ इस महीने कितना तेल खर्च हुआ, कितना मसाला खर्च हुआ, कितनी दाल खर्च हुई । इन तमाम बातों से उनको अवगत कराना पड़ता है और दुर्भाग्य तो तब होता है जब वे छात्रों के बीच में जाते हैं तो वे पठन-पाठन की बात नहीं करते हैं कि आज क्या पढ़ाई हुई बल्कि यह पूछते हैं कि बताओ आज खिचड़ी में चोखा मिला था या नही ? यह पूछते हैं, जब शिक्षालय ही भोजनालय में बदल जाय तो महात्मा गांधी के सपनों का क्या होगा ? क्या होगा उसका भविष्य ? आप जरा गौर करिए और यही कारण है कि एक करोड़ पचास लाख नौजवान जो 15 से 35 वर्ष का नौजवान है वह अपने बूढ़े बाप को छोड़कर, बूढ़ी मां को छोड़कर, जवान पत्नी और बहन को छोड़कर, छोटे-छोटे बच्चों को बिलखते छोड़कर वह बिहार से बाहर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में दर-दर की ठोकरें खा रहा है । यही कारण है कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रही है । सही कहा कुछ लोगों ने मैं उनकी बातों को दुहराना नहीं चाहता हूं हमारे क्षेत्र में एक जेठौर उच्च विद्यालय है । जिसके...

उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए माननीय सदस्य ।

श्री भूदेव चौधरी : विषय में मैंने पूर्व में भी शिक्षा मंत्री को इस बात से अवगत कराया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगले वित्तीय वर्ष में इसके विकास में योगदान होगा लेकिन दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि आजतक कोई पहल नहीं हुई, इसलिए मैं शिक्षा

मंत्री से भी आग्रह करना चाहता हूं कि इसको आप थोड़ा गंभीरता से देखिए । जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उसकी भुखमरी दूर नहीं होगी, उसकी बेरोजगारी दूर नहीं होगी...

उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए अब ।

माननीय सदस्या श्रीमती प्रतिमा कुमारी ।

श्री भूदेव चौधरी : इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूं-

''गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की
करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की ।''

सरकार में व्यवस्था यही है कि किसकी तारीफ की जाय । आपने मुझको समय दिया है बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के प्रस्तुत मांग पर लाये गये कटौती प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूं । महोदय, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को ही बता देना चाहती हूं और उसी से स्पष्ट हो जायेगा कि क्यों मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन कर रही हूं । इसके लिए मैं अपने नेता विधान मंडल के कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय अजीत शर्मा जी को धन्यवाद देती हूं ।

महोदय, मैं राजापाकर क्षेत्र से आती हूं । राजापाकर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सभी उच्च विद्यालय की स्थिति जर्जर है । बाउंड्री वाल किसी में नहीं है । उदाहरण स्वरूप श्री बांके बिहारी अमीरचंद उच्च विद्यालय, भटौलिया, आर0डी0ए0 सीनियर सेकेण्डरी विद्यालय, दामोदरपुर, श्री गोरखनाथ उच्च विद्यालय बैकुण्ठपुर एवं उच्च विद्यालय राजापाकर साथ ही टेन प्लस टू के लगभग नौ विद्यालय मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं । डेस्क, बेंच का अभाव है, बाउंड्री वॉल नहीं है जिसके कारण आये दिन जानवर घुस जाते हैं और असामाजिक तत्वों से बच्चे-बच्चियों को खतरा बना हुआ है । बहुत सारे स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों की चॉंदी हो गयी है । किसी भी स्कूल में लाईब्रेरी नहीं है । स्कूल उन्नयन क्लास के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है । स्कूलों में विषयवार शिक्षक नहीं हैं । एक ही जगह जमे रहने के कारण शिक्षकों के द्वारा पठन-पाठन से ज्यादा राजनीति में रुचि ली जा रही है । अत: मैं आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगी कि जो शिक्षक बहुत दिनों से अपने विद्यालयों में डटे हुए हैं, बसे हुए हैं वैसे शिक्षकों को तीन वर्ष के अंतराल में उनका स्थनांतरण किया जाय । मेरा यह सुझाव है कि सभी स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए । साथ ही सभी सीनियर सेकेण्डरी स्कूलों में सेनेट्री पैड की वेंडिंग मशीन लगायी जाय ताकि बच्चियां न्यूनतम कीमत पर पैड प्राप्त कर सकें । इसके साथ ही मेरा

यह भी आग्रह है कि सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की आवश्यकता है ताकि स्वस्थ रहकर बच्चे-बच्चियां पठन-पाठन कर सकें । महोदय, विद्यालय में चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों और नाइट गार्ड की परमानेंट नियुक्ति होनी चाहिए जिसके कारण विद्यालय असुरक्षित रहता है । अतः मैं आपसे आग्रह करती हूं कि स्कूलों में नाइट गार्ड और चपरासियों की नियुक्ति परमानेंट होनी चाहिए ।

महोदय, मैं सरकार का आपके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में जिस तरीके से हमलोगों ने न्यूज के माध्यम से भी देखा उप स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उप स्वास्थ्य केंद्रों में गोबर, गोइठा रखा जा रहा है, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां डाक्टर का अभाव है । स्वास्थ्य मंत्री से यदि सवाल किया जाता है तो स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से जवाब आता है कि डॉक्टर कोई ज्वाईन करना नहीं चाहता है । मैं आसन से आग्रह करना चाहती हूं कि जो भी डॉक्टर सरकारी कॉलेज से पढ़कर जाते हैं वैसे डॉक्टरों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 10 वर्ष अनिवार्य की जाय । मैं आपसे, आसन से आग्रह करती हूं कि सरकारी विद्यालयों में प्राइमरी शिक्षा के माध्यम से इंग्लिश की भी पढ़ाई होनी चाहिए क्योंकि गरीब-गुरबे, दलित-महादलित के बच्चे इंग्लिश से वंचित रहते हैं जिसके कारण उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में असुविधा होती है । चूंकि मैं खुद दलित समाज से आती हूं इसलिए मैं जानती हूं कि दलितों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है । अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, निवेदन करती हूं कि प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश को भी शामिल किया जाय ।

-क्रमशः-

टर्न-18/हेमन्त/02.12.2021

...क्रमशः..

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : और उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त हो सके । मैं आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि स्कूलों में हाईस्कूल हो, उत्क्रमित विद्यालय जितने भी बने हैं, भवन तो जर्जर हैं ही, बहुत-से शिक्षक ऐसे हैं जो दस-दस, बारह-बारह सब्जेक्ट के एक-एक शिक्षक हैं और विषयवार शिक्षक न होने के कारण बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है । साईकिलों से, भोजन से, पोशाक से शिक्षा ग्रहण नहीं होती है । कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में अभियान चलाया था सर्वशिक्षा अभियान (Right To Education), उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भी बच्चे हैं, गरीब के

बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गरीब-गुरबा, दलित, पिछड़े के बच्चे-बच्चियां शिक्षा के माध्यम से अपनी गरीबी को, अपनी बेरोजगारी को, अपनी लाचारी को दूर कर सकें और उनको समान शिक्षा प्राप्त हो सके ।

अत: मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूं कि मेरी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दिया जाय और स्कूलों में मूलभूत सुविधायें प्रदान की जायं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत ।

श्री कुमार सर्वजीत : उपाध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हम बोलने के लिए खड़े हुए हैं । उपाध्यक्ष महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया ।

उपाध्यक्ष : चार मिनट समय आपका है ।

श्री कुमार सर्वजीत : चार ही मिनट में बोल देंगे सब कुछ । हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि गांव के अंदर जो प्राईमरी स्कूल है, 2010 के पहले से सरकार ने इस पर पाबंदी लगायी है । आबादी बढ़ी है, सरकार बसावटों में सड़क का निर्माण कर रही है, छूटी हुई बसावट में, तो कौन सी छूटी हुई बसावट का आप निर्माण कर रहे हैं ? आबादी बढ़ी, टोला बढ़ा और जो दलितों की बस्तियां हैं, दूर-दूर जाकर अपना घर बसाया है और प्राईमरी स्कूल लगभग 2009-10 से बंद हैं पूरे बिहार में । हमारा आग्रह होगा कि एक बार फिर से विचार करिये और जो टोले छूटे हुए हैं, जहां दो किलोमीटर पर प्राईमरी स्कूल हैं वहां पर गरीब के बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, कम-से-कम उनको पर्याप्त शिक्षा मिल सके ।

विश्वविद्यालय का, हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप हालात देख रहे हैं । कई सदस्य 15 साल पहले की बात करते हैं और इस सरकार में यू0पी0 के न जाने कितने वाईस चांसलर आपके पैसे लेकर जा रहे हैं । यह हम नहीं कहते हैं पूरे देश-दुनिया ने देखा है । कृषि विश्वविद्यालय, उसके हालात आप देख लीजिए, इतनी चरम सीमा पर उसका भ्रष्टाचार है, बिहार के लोगों में योग्यता नहीं है क्या ? वह वी0सी0 नहीं बन सकते हैं क्या ? आपने कितने दिनों से उनका प्रमोशन रोक रखा है, कौन-सी वजह है ? उनको क्यों नहीं प्रमोशन मिलता है ? क्या बिहार में हमारे जो शिक्षक हैं, जो प्रोफसेर हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वह किसी कॉलेज के वी0सी0 बन सकते हैं ?

(व्यवधान)

अब उस पर चर्चा करनी बेकार है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में सबसे पुराने सदस्य श्री हरिनारायण बाबू बैठे हुए हैं । इन्होंने पशुपालन विश्वविद्यालय के इतने सारे सबूत दिये थे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे भ्रष्टाचार के सबूत इस सदन में पेश किये थे । कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आखिर कौन बढ़ावा दे रहा है, महोदय, कौन दे रहा है बढ़ावा इसको ? अगर कोई इतने पुराने सदस्य साक्ष्य के साथ आपको सदन में सारी चीजें पेश करते हैं और वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है । माननीय राज्यपाल महोदय उनको नोटिस भेजते हैं, उसके बाद सारा की सारा रफा-दफा हो जाता है । पूरे विश्वविद्यालय में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, तो मैं समझता हूं कि बिहार कभी एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ेगा ।

कोविड-19 से माननीय मंत्री जी, दस लाख बच्चे...

उपाध्यक्ष : कन्कलूड कीजिए थोड़ा ।

श्री कुमार सर्वजीत : स्कूल आपके छोड़ दिये और माननीय सदस्य ने कहा कि चरवाहा विद्यालय, वह चरवाहा विद्यालय की चर्चा नहीं करते, वह दलितों की, गरीबों की हालत पर इस सदन में मजाक उड़ाते हैं । दस लाख बच्चे बेघर हो गये, स्कूल छोड़ दिया और माननीय लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था, सुअर चराने वाले, भैंस चराने वाले, एजुकेशन क्या होती है. .

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए माननीय सदस्य ।

श्री कुमार सर्वजीत : भैंस खेत में चरेगी और अपने अंदर जागरूकता लाइये पढ़ने के लिए । चरवाहा विद्यालय में कोई किताब-कॉपी की पढ़ाई नहीं होती थी, उसको बताया गया था कि आपको स्कूल जाना नैसेसरी होगा और वह एक माध्यम था कि आपको हम स्कूल जाने की प्रेरणा कैसे देते हैं और जो हालात हैं उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में, दलितों का, किन लोगों ने छोड़ा है ? दस लाख गरीब, दलित बच्चों ने स्कूल छोड़ा और कौन लोग डी0पी0एस0 में पढ़ते हैं, कौन लोग डी0ए0वी0 में पढ़ते हैं ? हम तो नहीं पढ़ते हैं । हमारी शिक्षा गांव में हुई । हम गांव में पढ़कर यहां तक पहुंचे हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : उपाध्यक्ष महोदय, बस एक लाईन में । हम शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो दस लाख बच्चे आपकी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हुए इस कोविड-19 में, जिन्होंने छोड़ा है स्कूल, उसके लिए आप कौन-सा कदम उठा रहे हैं कि पुनः वे अपने स्कूल में जायं और अपनी शिक्षा ग्रहण करें । बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, आप आंकड़ा निकालिये, आप सर्वे निकालिये कि कौन-से ऐसे सरकारी स्कूल हैं, कौन-से ऐसे

विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां सरकारी स्कूल में कितने बच्चे पढ़कर, आपकी एजुकेशन की जो गाइडलाईन है उससे कितने बच्चे बड़े अधिकारी बने हैं ? बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश कुमार ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, इस अनुपूरक शिक्षा बजट पर बोलने का अवसर मिला इसके लिए मैं आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । मैं जगत जननी जानकी की धरती से आया हूं और विद्यापति की धरती मिथिला के केंद्र से आया हूं जहां से पूरे विश्व को शिक्षा की रौशनी मिली, उस जगह से मैं यहां बैठे तमाम सदस्यों का अभिनंदन करता हूं और सदन के माध्यम से पवित्र सीता प्राकट्य स्थली के नागरिकों का अभिवादन करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस सदन में आपके समक्ष बोल सकूं । मिथिला के केंद्र से आज जो मुझे भेजा गया है सीतामढ़ी से, यह शुभ घड़ी है, वृहस्पतिवार का दिन है और एकादशी तिथि है, विष्णु की तिथि है और मिथिला की धरती का मैं पुत्र हूं । महोदय, मैं सरस्वती की वंदना के साथ सबों के मन में सद्विचार और विवेक की प्रार्थना करूंगा-

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला
या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा
या श्वेतपद्मासना ।
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ।।

जगदंबा सरस्वती बिहार के सभी लोगों की जड़ता का हरण करे और हम सबों को सद्ज्ञान दे, विवेक दे, वैराग्य दे ।

महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने शिक्षा में जो मानदंड खड़ा किया है वह किसी के कालिख पोतने से या बादल लगने से सूर्य को ढका नहीं जा सकता । महोदय, शिक्षा की शुरूआत कहां से होती है ? प्रारंभिक शिक्षा से होती है और प्रारंभिक शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जो संज्ञान लिया है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोगों की विजुअलिटी है, जो मोड-ऑफ-एक्शन है, क्या विपक्षी इसकी कल्पना भी कर सकते हैं ? उनके मन में यह कल्पना ही नहीं आ सकती ।

टर्न–19/धिरेन्द्र/02.12.2021

क्रमशः

श्री मिथिलेश कुमार : प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना, चरवाहा विद्यालय की बात करने वाले और सूअर और गाय और भैंस चराने का नाम लेकर जनता को ठगने वाले लोगों के लिए यह आईना है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार गरीब बच्चों के लिए मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना बनाती है । सूअरों से, भैंसों से उनको बांधकर नहीं रखना चाहती है, उनको विश्व के मानस पटल पर शिक्षा का दीप जलते हुए दिखाना चाहती है । राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की छात्रवृत्ति योजना, क्या विजुएलिटी है आपकी, आप में यह चिंतन है, आप में यह दुरदर्शिता है कि गरीबों के बच्चों को कोविड के काल में, कैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार कोविड को नियंत्रित कर के पूरे भारत में, मैं आदरणीय श्री मंगल पाण्डेय जी को इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार का पूरे भारत में पांचवे स्थान पर कोविड नियंत्रण में रैंकिंग रहा और उस कोविड को नियंत्रित कर हमने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी । यह विपक्षी लोग कभी कल्पना कर सकते हैं कि ऑनलाईन शिक्षा भी गाँव में बच्चों को दी जा सकती है । महोदय, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अभिवंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालय में नामांकन की परिकल्पना एन0डी0ए0 की सरकार ने की है और जहां भी निजी विद्यालय चल रहे हैं वहां प्रतिशत के आधार पर वंचितों, दलितों और गरीबों के बच्चों का नामांकन हो रहा है और जन–प्रतिनिधि के नाते अपने क्षेत्र में मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ । महोदय, केन्द्र प्रायोजित योजना जो है उस योजना में जन–शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के बाद जन–शिक्षा, जन–शिक्षा में महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए अक्षर आंचल योजना की शुरूआत की है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने । राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने वर्ष 2020–21 के लिए किलकारी योजना के तहत भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित जिला स्तर पर चयनित पांच बच्चों के नाम आये हैं अभिजीत कुमार, उमा कुमारी, आनंद कुमार, प्रिंस कुमार और मोहित कुमार । महोदय, जन–शिक्षा के अंतर्गत 6–14 वर्ष के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य में महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए आंचल योजना का संचालन किया जा रहा है । महोदय, परीक्षा भवन का निर्माण हो रहा है, डिग्री कॉलेज की स्थापना अनुमंडल स्तर पर हो रही है । महोदय, राजकीय महिला

विद्यालय, गर्दनीबाग का जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई है । महोदय, केन्द्रीय विश्व विद्यालय, मोतिहारी के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है और उस पर निर्माण कार्य होगा । बिहार, शिक्षा की रोशनी पूरे भारत में प्रशस्त करेगी । महोदय, नालंदा विश्व विद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है, वह नालंदा, जहां संपूर्ण विश्व का छात्र आकर सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त करता था, सभी विद्याओं में पढ़ाई होता था, उस नालंदा की भूमि के लिए एन0डी0ए0 की सरकार ने अभी भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव डाली है । महोदय, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इसकी कल्पना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अलावा अन्य किसी सरकार के मन में इसकी परिकल्पना भी नहीं आ सकती थी । महोदय, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, किशोरी स्वास्थ्य योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक-बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, छात्रवृत्ति योजना, उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना । महोदय, राज्य में अवस्थित 8386 पंचायतों में से 5082 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया चुका है और शेष पंचायतों में वर्ग-9 की पढ़ाई प्रारंभ कर दी गई है और उक्त पंचायतों में भूमि की उपलब्धता के मद्देनजर नये विद्यालय भवन का निर्माण क्रमिक रूप से कराने की योजना है एन0डी0ए0 सरकार की । महोदय, हमारी जो भावी योजना है, उसमें इंटरमीडिएट उत्तीर्ण सभी वर्ग की अविवाहित छात्राओं के प्रति छात्रवृत्ति का 25 हजार रुपया डी0बी0टी के माध्यम से उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने का हमारा कार्यक्रम है । महोदय, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड में भी हमने परिस्वीकृत 429 एवं 223 अनुदानित विद्यालयों की संख्या 531 हमलोगों ने उसमें दर्ज किया है और प्रस्तावित संस्कृत विद्यालय 3,776 एवं 711 कोटि का है । महोदय, संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे आने वाले दिनों में हमलोग उत्तर प्रदेश की योजना यहां लागू करेंगे और वर्ग-1 से संस्कृत शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने वाले हैं । महोदय, मध्यमा परीक्षा, 2020 में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 21,625 है और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा निर्गत मध्यमा का प्रमाण-पत्र....

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, सी0बी0एस0ई0 के द्वारा मान्यता प्राप्त है । महोदय, समाप्त करने का तो अवसर ही नहीं है, किताब नहीं है यह आईना है । मेडिकल कॉलेजेज, पॉलिटेक्निक कॉलेजेज, टेक्निकल कॉलेजेज, बी0एड0 कॉलेजेज, डी0ए0वी0 कॉलेजेज कितने कॉलेजों की गिनती कराई जाय...

उपाध्यक्ष : श्री राकेश रौशन । आपका तीन मिनट है ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, मैं आग्रह करूंगा तमाम सदन के सदस्यों से कि एन0डी0ए0 की इस शिक्षा के नीति को सभी लोग मिलकर समर्थन करें..

उपाध्यक्ष : श्री राकेश रौशन ।

श्री मिथिलेश कुमार : और बिहार को फिर से भारत के अग्रणी पंक्ति में खड़ा करें । जय हिन्द ।

श्री राकेश कुमार रौशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और आज जिस विभाग पर चर्चा हो रही है, शिक्षा विभाग जोकि समाज और राष्ट्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा का ही है, उस पर हमलोग चर्चा करने के लिए यहां पर एकजुट हुए हैं तो मैं सबसे पहले, चर्चा शुरूआत करने से पहले, मैं माननीय मंत्री जी, जिन्होंने यह विनियोग विधेयक पेश किया है, उनका इसी सत्र में जो बजट भाषण हुआ था, उस बजट भाषण में जो उनकी सरकार का लक्ष्य था उन्हीं बातों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ । उन्होंने इसी सदन में बोला था कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा गुणवत्ता को शत प्रतिशत सुनिश्चित करना और शैक्षणिक संस्थानों में तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार कृतसंकल्प है तथा यू0एन0ओ0 द्वारा घोषित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य को पूरा करना है, यह माननीय मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए कहा था। हमलोगों को भी बहुत अच्छा लगा था कि बिहार जैसे गरीब प्रदेश में जब सरकार की इस तरह की सोच है तो निश्चित रूप से बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा लेकिन कल जो किताब हमलोगों को मिली और इन्होंने जो बिहार के डेवलपमेंट का स्टैटिक्स आंकड़ा दिया है, उसका जब हमने विश्लेषण किया तो पाया कि अभी जो भारत में साक्षरता दर की स्थिति है वह 73 परसेंट है और बिहार के अंदर जो साक्षरता की दर है वह 61.8 परसेंट है । देश में छात्र-शिक्षक अनुपात का जो राष्ट्रीय मानक है वह 30:1 है यानी 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए, जबकि बिहार में वर्ष 2020 के सर्वे के हिसाब से यह मानक 38:1 है यानी 38 छात्र पर 1 शिक्षक । अब, यह जो आंकड़ा है यह खुद बताता है कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास किया है और इन्हीं बातों का विश्लेषण करते हुए नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बिहार शिक्षा के मामले में फिसड्डी राज्य है

क्रमशः....

टर्न–20/संगीता/02.12.2021

''क्रमशः''

श्री राकेश कुमार रौशन : चूंकि सरकार ने अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया और अभी हमारे साथी बहुत महिमामंडित कर रहे थे सरकार को लेकिन यदि सरकार समय रहते अपने लक्ष्य को पूरा करती तो निश्चित रूप से हम बिहार के अंदर शिक्षा का एक कीर्तिमान स्थापित कर सकते थे...

उपाध्यक्ष : समाप्त किया जाये, समय हो गया, 3 ही मिनट था आपका ।

श्री राकेश कुमार रौशन : 2 ही मिनट था हुजूर ? अब 2 मिनट में तो हुजूर कुछ बोला नहीं जा सकता लेकिन अपने क्षेत्र की कुछ समस्या है उसकी हम चर्चा करना चाहेंगे । ऐसे हुजूर, जो क्वॉलिटी एजुकेशन की बात कही जाती है एक तरफ परसों यहां पर आपने देखा इसी सदन में बिहार प्राइवेट विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक यहां पर पारित कराया गया और एक तरफ हम कहते हैं कि सब कॉमन स्कूलिंग सिस्टम का व्यवस्था होगा बिहार में और दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं तो फिर जब प्राइवेटाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं तो फिर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की जो बात कही जाती है यह बिहार की जनता के साथ धोखा देने की बात है इसके सिवा तो कुछ हो नहीं रहा है । जो खुद सरकार ने पिछले इसी सत्र में इस विधेयक को पारित कराया है और समय की कमी है महोदय, हमने बहुत सारी बातों को रखा था लेकिन...

उपाध्यक्ष : समाप्त किया जाय ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, आपके माध्यम से मैं नालन्दा जिला जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है वहां से आता हूं । वहां जो हालात है शिक्षा का, काफी बदतर स्थिति है खासकर हमारे निर्वाचन क्षेत्र इस्लामपुर में 2 ऐसे विद्यालय हैं जिनको माध्यमिक विद्यालय का दर्जा मिला है लेकिन अभी तक माध्यमिक विद्यालय का भवन नहीं बना है महोदय । वह एक लारनपुर उच्च विद्यालय है और एक खुशहालपुर उच्च विद्यालय है । ये दोनों का जो भवन है जर्जर स्थिति में है, वहां पर विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता और पूरे बिहार में न्याय के साथ विकास की बात कही जाती है...

उपाध्यक्ष : समाप्त किया जाय माननीय सदस्य ।

श्री राकेश कुमार रौशन : और खुद मुख्यमंत्री जी के गृह जिला की यह हालत है इसलिए मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राज कुमार सिंह जी ।

श्री राकेश कुमार रौशन : कि इन विद्यालयों के भवन का अविलंब निर्माण कराया जाय ।

श्री राज कुमार सिंह : ''वो दौर भी देखा है तारीख की नजरों ने,
लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई ।''

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका और अपनी पार्टी जनता दल यूनाईटेड का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस द्वितीय अनुपूरक मांग के पक्ष में मुझे बोलने का अवसर मिला है । बिहार...

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मुझे इंट्रप्ट किया जाता है वह मेरे समय में से माइनस किया जाय । मैं आज किसी प्रकार के आंकड़े की बात नहीं करूंगा ...

उपाध्यक्ष : 8 मिनट समय है आपका ।

श्री राज कुमार सिंह : मैं आंकड़े की बात नहीं करूंगा क्योंकि आंकड़े पटल पर रखे जा चुके हैं । मैं बिहार की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में क्या रही है पारंपरिक तौर से और आज क्या है और विगत कालांतर में क्या होते चला गया उसपर मैं अपनी बात को कहूंगा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहार ज्ञान की धरती रही है और यह विज्ञान की जननी भी रही है । यहां यदि गौतम बुद्ध और महावीर ने ज्ञान प्राप्त कर इस देश ही नहीं दुनिया को अपने ज्ञान से प्रभावित और प्रकाशित किया तो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार कर और ''थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी'' का देकर विज्ञान को भी एक नई परिभाषा देने का प्रयास किया । यह भूमि नालन्दा और विक्रमशीला विश्वविद्यालय की है...

(व्यवधान)

मैं आ रहा हूं सारी बातों पर आपको समझ में आ जाएगा लेकिन इन सारी गौरवशाली परंपराओं के बाद इस बिहार को नजर लग गई । पहले नजर लगी बख्तियार खिलजी जैसे आक्रांता की और कालान्तर में नजर लग गई लालटेनधारी राजनेता की । मुझे याद है 80 के दशक में मैं यहां पर पढ़ाई करता था शिक्षा की स्थिति अच्छी थी 80 के दशक में । मैं साइंस कॉलेज से पटना यूनिवर्सिटी गया था और उस वक्त जब लोगों ने मुझे पूछा कि आप क्यों आए यहां पर आप साइंस कॉलेज से आए तो आश्चर्य किया कि आप साइंस कॉलेज से रामजस कॉलेज क्या करने आ गए । सच में शिक्षा की स्थिति उस वक्त अच्छी थी । लेकिन धीरे-धीरे 90 आते-आते शिक्षा की स्थिति बिल्कुल चौपट हो गई । 1990 में जनादेश ने जिस एक भूल को, लम्हे के उस एक भूल किया जिसने बिहार को बदनामी और गुमनामी के ऐसे गर्त में डाल दिया कि जिसका शिकार सबसे पहले शिक्षा हुई और उस बदनामी के अंधकार का शिकार यहां बिहार की शिक्षा हुई और बिहार

जंगलराज और दहशत का पर्याय बन गया एक साजिश के तहत । मेरा मानना है कि एक साजिश के तहत शिक्षा की प्राथमिकता को खत्म किया गया क्योंकि शिक्षित समाज किसी अराजक नेतृत्व को कभी बर्दाश्त नहीं करती है उसको जल्दी बदल देती है । दिखावे के लिए चरवाहा विद्यालय की परिकल्पना की गई, मुझे तो आश्चर्य होता है आज और मेरी समझ में नहीं आया कि चरवाहा विद्यालय की परिकल्पना में जो नारा दिया गया था कि गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, भैंस चराने वाले आओ पढ़ाई करो । इस परिकल्पना में उन चरवाहों को चरवाहा बनाए रखने की साजिश थी या उनको शिक्षित कर इंजीनियर, डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर और एक शिक्षित नागरिक और एक नेता बनाने की थी । अगर ऐसी थी तो फिर इस चरवाहा विद्यालय ने प्रगति क्यों नहीं की, आज चरवाहा विद्यालय की क्या स्थिति है ? चरवाहा विद्यालय के प्रबंधन में 6-6 विभाग को लगा दिया गया । शिक्षा विभाग के साथ-साथ कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, उद्योग विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पशुपालन विभाग और इन सभी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया चरवाहा विद्यालय और आप जाकर देखें चरवाहा विद्यालय नशाखोरी, जुआबाजी और ताश का अड्डा बनकर रह गया, वहां शिक्षा मर गई...

(व्यवधान)

बीच में, आप बाद में बोल लीजिएगा । मैंने कहा कि चरवाहा विद्यालय की परिकल्पना शायद अच्छी रही हो लेकिन उसमें साजिश थी । उसमे साजिश थी चरवाहों को चरवाहा बनाए रखने की क्योंकि उसमें नारा सीधा-सीधा था गाय भी चराओ, भैंस भी चराओ और पढ़ाई भी करो । अगर आपको चरवाहा विद्यालय से शिक्षित समाज को...

उपाध्यक्ष : कन्क्लूड कीजिए माननीय सदस्य ।

श्री राज कुमार सिंह : सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से शिक्षा को मेरा मानना है कि शिक्षा किसी भी देश और राज्य की आर्थिक रीढ़ होती है लेकिन यहां तो शिक्षा की ही रीढ़ तोड़ दी गई साजिश के तहत और बिहार जो पहले से पिछड़ा था, वह और फिसड्डी हो गया लेकिन अंधेरा छंटता है और अंधेरा छंटा भी और वर्ष 2005 में एक ऐसी आशा एक नई किरण की यहां पर शुरूआत हुई और बिहार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं आर्थिक विकास के सभी क्षेत्र में अपना एक परचम लहराने का काम किया और इसमें श्री नीतीश कुमार जी की एन0डी0ए0 के नेतृत्व वाली सरकार का सबसे बड़ा योगदान है । आज जितना बदलाव हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में मैंने तो कहा है कि मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा लेकिन आज 71 हजार 832 विद्यालयों में 2 करोड़ 34 लाख छात्रों का नामांकन है और वे पढ़ाई कर रहे हैं । जो 2004-05 में साक्षरता का दर, शिक्षक भी 4

करोड़ 67 लाख हैं और प्रत्येक 30 छात्र पर एक शिक्षक हैं और आप जान लें और यही स्टैंडर्ड है...

(व्यवधान)

आपको मैं कहूंगा आप इंट्रप्ट कर रहे हैं लेकिन मैं उससे विचलित नहीं हो रहा हूं । आपको इतना ही कहूंगा कि बदलाव अगर हो रहा है तो बदलाव आपको नहीं दिखेगा । आप देखना नहीं चाहते हैं बदलाव । आप बदलाव देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए माननीय सदस्य ।

श्री राज कुमार सिंह : इतना ही कहकर कन्क्लूड करूंगा

''यह अलग बात है कि तुम नहीं बदलोगे मगर जमाना बदल रहा है ।
गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चराग आंधी में जल रहा है । ''

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान साहब ।

टर्न-21/सुरज/02.12.2021

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान साहब । नहीं हैं । माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती मंजू अग्रवाल ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, आज मैं विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में एवं सरकार द्वारा लाये गये विनियोग विधेयक का विरोध करती हूं । महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय, श्री लालू प्रसाद यादव जी को, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं श्रीमती राबड़ी देवी जी को, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जिन्होंने आज मुझे यहां बोलने का अवसर प्रदान किया । सरकार ने मध्याह्न भोजन, साईकिल, पोशाक छात्रवृत्ति सहित तमाम योजनाओं के माध्यम से बच्चों को विद्यालय की ओर खींचने की कोशिश तो की लेकिन वह शिक्षा के असल उद्देश्य यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मामले में पूरी तरह नाकाम रही । इसका बड़ा कारण इस व्यवस्था की रीढ़ शिक्षकों की अनदेखी है । मिड-डे-मील बच्चों को स्कूल में बुलाने और उन्हें वहां रोके रखने का एक बड़ा माध्यम है परंतु इसमें आये दिन होने वाले घोटालों की समस्या के अलावा अधिकांश विद्यालयों में अब तक न तो सही तरीके के रसोईघर हैं और न ही बच्चों को बिठाकर खिलाने की जगह है इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । केन्द्र

सरकार सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हजारों करोड़ रुपये राज्यों को उपलब्ध कराती है । इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक 5 किलोमीटर की परिधि में कम से कम एक माध्यमिक स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है इसके तहत राज्य में 949 मध्य विद्यालयों को उन्नत किया जाना है पर...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये, आपका समय हो गया ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : बिहार इन तमाम लक्ष्यों से कोसों दूर है । राज्य की करीब 65 फीसद पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर विद्यालय नहीं हैं...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये माननीय सदस्या जी ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : शिक्षा व्यवस्था की चार खामियां मैं बताना चाहती हूं और ये खामियां जो हैं...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान जी ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सर्वे के आधार पर, वर्तमान स्थिति के आधार पर है पहला बुनियादी सुविधाओं का अभाव...

उपाध्यक्ष : चार मिनट हैं आपके पास ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : 10 प्रतिशत स्कूलों के पास भवन नहीं हैं, 50 प्रतिशत में चहारदीवारी नहीं है, 70 प्रतिशत के पास खेल के मैदान नहीं हैं, 10 फीसदी के करीब स्कूलों में लड़के-लड़कियों के लिए अलग शौचालय का अभाव है आज भी यह रिपोर्ट प्रभावी है.. .

उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, समाप्त कीजिये ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : दूसरा शिक्षा पर, नहीं थोड़ा सुन लिया जाए, ये समाप्त करने की बात नहीं है ये आपलोग जो बोलते हैं कमियां हैं, मैं कमियां गिना रही हूं । दूसरा, शिक्षकों पर बच्चों को बेहतर भविष्य दे पाएं ऐसी जानकारी उनके पास नहीं है । शिक्षकों की अनुपस्थिति देखी गई है । जांच के तंत्र में भी गड़बड़ी है...

उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये माननीय सदस्य ।

श्री अखतरूल ईमान : हाउस को आर्डर में लिया जाए सर ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : समाप्त कीजिये ।

श्री अखतरूल ईमान : हाउस को आर्डर में लिया जाए सर । मेरा टाइम सर देख लिया जाय । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपका आभारी हूं जो आपने हमें समय दिया है । मान्यवर इस वक्त जरूरत इसकी है कि व्यापक बहस करायी जाय और तमामतर विभागों पर सरकार के कार्यकलाप पर रौशनी डाली जाए लेकिन अच्छा किया है शिक्षा को विषय बनाकर वाद-विवाद को आपने आगे

बढ़ाया है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं । मुझसे अगर पूछा जाय कि एन0डी0ए0 के कौन से काम को तुम अच्छा देखते हो । मैं एन0डी0ए0 के कार्यकलापों, उनके विचारों से मतभेद रखता हूं बल्कि मुखालफत करता हूं लेकिन दो चीजें ऐसी हैं शराबबंदी जिसने एक बड़ा सबक पढ़ाया है बिहार को, मैं उसका समर्थन करता हूं और दूसरा यह है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की शैली, जो बोलते हैं तो दिल को लुभा लेते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद काम भी वह करेंगे इसी उम्मीद पर कुछ बातें शिक्षा के बारे में रखना चाहता हूं ।

मान्यवर, कोविड की वजह से एक साल से गरीबों के बच्चों का स्कूल छूट गया है, अमीरों के बच्चे गूगल मीट में, जूम में, गूगल क्लास पर क्लास कर रहे हैं । अभी 7 नवंबर को जो रिपोर्ट आयी है उसने बता दिया है कि एडमिशन बढ़ा है, 96 परसेंट बच्चे स्कूल पहुंचे हैं लेकिन दूसरा रूप यह है कि 30 प्रतिशत बच्चे क्लास आठ के उससे ज्यादा के लोग अपने सलेबस की किताब नहीं पढ़ पाते हैं इस पर गौर करने की जरूरत है कि शिक्षा किसका नाम है, उसको हमें देखने की जरूरत है चूंकि बिहार में खनिज नहीं है और मानव संसाधन के विकास के बगैरह बिहार का विकास नहीं हो सकता । मैं आपको स्कूल की स्थिति बताना चाहता हूं कि इस वक्त बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान की हैसियत हासिल है और नतीजा यह है कि बिहार के 80 हजार से ज्यादा स्कूलों में उर्दू के टीचर नहीं हैं और उर्दू बंगला टेट जो पास किये हैं सात साल पहले, ये बच्चे आज डंडे खा रहे हैं । किसी का सुहाग उजड़ रहा है, किसी की मां रो रही है, कोई खुदकुशी कर रहा है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहाली कीजिए लेकिन आपने एस0टी0ई0टी0 को 50 परसेंट में बहाल किया और उर्दू और बंगला के लिए आपने 60 परसेंट अनिवार्य रख लिया । मैं समझता हूं कि संविधान की धारा-15 कास्ट और लैंग्वेज की बुनियाद पर किसी के साथ भेद-भाव न किया जाय उसका वायलेशन है । मैं चाहता हूं कि इन पर गंभीरता से सरकार विचार करे और ये बच्चे 5 परसेंट मांग रहे हैं बल्कि 50 प्रतिशत देकर इनकी बहाली की जाय ताकि उर्दू जो बिहार की दूसरी सरकारी जुबान है उसके पठन-पाठन का कार्य हो सके ।

महोदय, मैं अभी आपको कहना चाहता हूं कि आपने अभी 40500 मिडिल और प्राईमरी स्कूल के और 5300 हाई स्कूल के टीचरों के लिए बी0पी0एस0सी इम्तहान लेने का फैसला किया है उसमें पंचायत के और नगर के शिक्षकों के नियमों को माना है लेकिन मदरसे के टीचरों के नियमों को नहीं माना है । मैं चाहता हूं कि उस पर भी विचार करें । मैं चाहता हूं कि इन नियोजित शिक्षकों की तनख्वाह बढ़े, उनको वक्त पर

तनख्वाह मिले और शिक्षक, शिक्षक बने और शिक्षा के अलावा दूसरे कामों में उनको नहीं लगाया जाय । मदरसा एजुकेशन बोर्ड, बिहार में अक्लीयतों की तालीम का एक बड़ा इदारा है ।

महोदय, मदरसा एजुकेशन बोर्ड की हालत बहुत बुरी है आपने 2449 प्लस एक-एक मदरसे को तनख्वाह देने की बात कही है । सिर्फ 814 मदरसों को दिया है आपने, 1600 मदरसों के टीचर भूखमरी के शिकार हैं । उनकी तनख्वाह जल्द से जल्द जारी कराई जाए । मदरसों के 2005 से पहले के टीचरों को आप पेंशन उन पर लागू कीजिये, मदरसों की कमेटी की बहाली के सिलसिले में आप कोई निर्णय लाइये । टी0ए0एट0 वहां पर बहाल कीजिये, कमेटी के चेयरमैन्स बहाल कीजिये, मदरसा के रूल-रेगुलेशन ठीक कीजिये । अभी आप देखेंगे कि आपने आज सदन में आश्वासन दिया है कि हाफिज के ओहदे को तरक्की दी जायेगी लेकिन मेरे पास सेक्रेटरी का लेटर है कि हाफिज के ओहदे को तरक्की नहीं दी जायेगी, किसको माना जाय । माननीय मंत्री, आप जो कुछ सदन में बोल रहे हैं वह नियम है इसलिए वहां बहुत सारे हाफिज को तरक्की दी गई है लेकिन ये रूका पड़ा है इस काम को जारी कराया जाए ।

महोदय, मदरसा की कमेटी जल्दी से जल्दी बहाल करायी जाए....

उपाध्यक्ष : कनक्लूड कीजिये ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय मदरसा समसुल ओहदा में 35 टीचर की जगह पर सिर्फ 10 हैं, गवर्नमेंट उर्दू लाईब्रेरी में 10 की जगह पर सिर्फ 2 हैं अंजुमन तरक्की उर्दू, उर्दू एकेडमी, उर्दू लाईब्रेरी यहदुरा तहकीकात बंद पड़ा हुआ है । ए0एम0यू0 किशनगंज को अभी तक फंड नहीं मिल सका है । उसके फंड को जारी कराने के लिए सरकार मरकज से सिफारिश करे, इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करती है सरकार । नीति आयोग ने कहा है कि सीमांचल सबसे पिछड़ा है मेरा मुतालिबा है कि सीमांचल के तमामतर ब्लॉक में वहां पर रेजिडेंसियल इसको कायम किया जाय । कॉलेज में बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन नहीं बल्कि...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री अखतरूल ईमान : सर दो मिनट सर । उम्रे दराज मांगकर लाये थे चार दिन दो आरजू में कट गये दो इंतजार में । बहुत कम समय मिला है सर । दो बात सुन ली जाय । डाइट में आप प्राईमरी स्कूल के टीचर को ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां पर बी0एड0 की पढ़ाई शुरू कराई जाए । दास्तां-ए गम हम जब सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे । उर्दू मर रही है, मिट रही है उर्दू तालिम को जिंदा कीजिये । उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जुबान है ।

मान्यवर, हमारे मंत्री जी उर्दू की भाषा जब बोलते हैं सबको लपेट लेते हैं बल्कि विपक्ष को चुप करने के लिए उर्दू के शब्दों का बड़ा सुंदर प्रयोग करते हैं । उर्दू जिंदा नहीं रहेगी तो हिन्दी भी मर जायेगी । उर्दू हिन्दी दोनों जुड़वा बहन हैं । उर्दू के तमाम टीचरों की बहाली की जाय । मदरसे की हालत अच्छी बनाई जाय । ए0एम0यू को फण्ड दिलाया जाय ताकि उर्दू आबादी यकीन करने लगे कि ये जो सरकार कहती है इंसाफ के साथ तरक्की तो दोनों आंखों में रौशनी होगी तभी दुल्हन खुबसूरत होगी....

उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये । माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी ।

श्री अखतरूल ईमान : उर्दू टेट के नौजवानों को फौरन बहाल कीजिये और मदरसा के सारे लंबित मसले को हल कीजिये । आपने समय दिया इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि वजीर-ए तालीम जो बड़ी संजीदगी से उर्दू के मसाहिल को सुन रहे हैं इन उर्दू के मसाहिल को हल करने में फौरी इंतजाम करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया ।

टर्न-22/राहुल/02.12.2021

श्री सत्यदेव राम : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा विभाग की अनुदान मांग पर वाद-विवाद चल रहा है एक पक्ष बिहार में शिक्षा को बेहतर बता रहा है । हम लोग जब देखते हैं तो देखते हैं कि शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है । हम एक ही बात इस संदर्भ में कहना चाहते हैं कि अगर बेहतर शिक्षा है तो चलिये हम सब लोग अपने-अपने बेटों को उस विद्यालय में पढ़ायें, मंजूर होगा, किसके लिए बहस कर रहे हैं ? अगर इस सरकार में दम है तो यह फैसला करे कि सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी अफसर का बेटा-बेटी सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा मैं इसके लिये आपसे चैलेंज करता हूं । दम हो तो फैसला कर लीजिये लेकिन मैं जानता हूं कि आप नहीं करेंगे । महोदय, हम आज ही शून्यकाल में सरकार से मांग किये थे कि आज पूरे बिहार में प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, 70 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय नहीं हैं जिससे बच्चियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है...

(व्यवधान)

गलत होता तो हम चैलेंज करेंगे यह आज पूरे बिहार के विद्यालयों की स्थिति है । महोदय, यह कह दीजिये की गलत है जितने मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके आपने उच्च माध्यमिक विद्यालय में तब्दील किया है, क्या यह बात सही नहीं है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, मध्य विद्यालय के शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बोलिये । आपको तो यह बात, हम वही से शुरू किया हूं कि शिक्षा की

हालत को इससे समझा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को पढ़ा रहे हैं । यही नहीं महोदय, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है और बच्चों की परीक्षा ली जा रही है और इसको आप देखेंगे तो यह बड़े स्तर पर है । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सारी चीजें हो रही हैं वह शिक्षा में जो दोहरी नीति है यह दोहरी नीति के कारण हो है । महोदय, हम तो मांग करेंगे कि शिक्षा को एकल नीति में आप लाइये, मुचकुंद दुबे की रिपोर्ट को आप लागू कीजिये । मुचकुंद दुबे ने कहा था कि एकल शिक्षा नीति देश में, बिहार में होनी चाहिये लेकिन सरकार यह नहीं करेगी, अगर एकल शिक्षा नीति जिस दिन लागू हो जायेगी उस दिन बकरी चराने वाले, सुअर चराने वाले, गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले का बेटा डी0एम0 होगा आपका बेटा सिर्फ डी0एम0 नहीं हो सकता है लेकिन आप सचेष्ठ रूप से यह दोहरी नीति लागू करके गरीबों के बेटा और बेटी को पढ़ने से वंचित कर रहे हैं, उसको डी0एम0, एस0पी0 बनने से वंचित कर रहे हैं । इसलिए हम मांग करते हैं कि इस दोहरी शिक्षा नीति को सरकार खत्म करे और एकल शिक्षा नीति प्रणाली लागू करे ताकि गरीबों के बेटा-बेटी को भी दरोगा, एस0पी0, क्लेक्टर बनने का अवसर मिल सके लेकिन हम जानते हैं कि आप ऐसा नहीं होने देंगे । यह शिक्षा की हालत है महोदय । अब कहने के लिये यह डबल इंजन की सरकार चल रही है लेकिन डबल इंजन का अर्थ मैं समझता हूं महोदय कि डबल इंजन लग जायेगा तो ट्रेन पहाड़ों पर चढ़ जायेगी लेकिन आज इस डबल इंजन में दम ही नहीं दिखता है । मैं दो साल से मांग कर रहा हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र यू0पी0 के बोर्डर पर है, जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है आज वहां एक डिग्री कॉलेज की जरूरत है लेकिन इस सरकार में यह फैसला करने की हिम्मत नहीं है यह जिला स्तर पर चलायेंगे, पंचायत स्तर पर टेन प्लस टू के विद्यालय चलेंगे लेकिन डिग्री कॉलेज इनसे नहीं बन रहा है । हम मांग करते हैं कि सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर है तो प्रखंड स्तरों पर डिग्री कॉलेज की मान्यता दे ताकि जो पंचायत स्तर पर इंटर कॉलेज, टेन प्लस टू के विद्यार्थी जो पास कर रहे हैं उनको वहीं पर घर से खाना खाकर के डिग्री हासिल करने का मौका मिल सके...

उपाध्यक्ष : कंकलूड कीजिये माननीय सदस्य । कंकलूड कीजिये ।

श्री सत्यदेव राम : अभी हमारा कंकलूड कैसे होगा ?

उपाध्यक्ष : मात्र 9 मिनट का समय था आपके पास ।

श्री सत्यदेव राम : 9 मिनट हमको और दे दीजिये ।

(व्यवधान)

महोदय, हमारा समय जायेगा न इसी में...

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मंत्री के बेटे को, विधायक के बेटे को, अफसरों के बेटे को सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहिये, शायद इनको जानकारी नहीं है कि इनके पूर्व नेता स्वर्गीय विनोद मिश्र जी के लड़के विदेश में पढ़ते थे. ..

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : सत्यदेव बाबू बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : मेरा समय जा रहा है उनको बैठाइये ।

उपाध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री सत्यदेव राम : मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य ने कहा है कि विनोद मिश्र का लड़का विदेश में पढ़ता है तो मैं कहना चाहता हूं कि वह आपकी नीति के कारण है लेकिन मैं आपसे तो यह कहना चाहता हूं कि विनोद मिश्र के तो लड़के ही नहीं हैं, आपको कहां से पता चल गया है । अब देखिये इतना असत्य मत बोलिये मुझे मालूम है कि केंद्र से असत्य का पहाड़ा जो है ये बिहार सरकार पढ़ ली है । महोदय, यह नीति आयोग की जो रिपोर्ट है बरसों के न्याय के साथ विकास, यह सरकार के नारे की पोल खोल दिया है । महोदय, यह पोल खुल गयी है और सरकार को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए । सरकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नीति आयोग, वह हमने नहीं बनाया है वह आप ही की सरकार की बनाई हुई संस्था है और जब वह कह दिया है कि बिहार चौथे स्थान पर फिसड्डी है, पूरे देश में सबसे फिसड्डी है तो इसको ईमानदारीपूर्वक कबूल करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, अभी थोड़ा-सा और समय हमको दिया जाय । एक भूमि सुधार का मामला है । महोदय, भूमि सुधार मंत्री ने एक बयान दिया है अखबार में कि 90 हजार गरीबों को आवासित किया गया है और उन्होंने आंकड़ा भी दिया है और यह भी बताया है कि सभी लोगों को 5-5 डिसमिल जमीन दी गयी है । महोदय, यह 90 हजार लोगों को, हमारा गणित थोड़ा कमजोर है ।

क्रमशः

टर्न–23/मुकुल/02.12.2021

क्रमशः

श्री सत्यदेव रामः उपाध्यक्ष महोदय, आप ही थोड़ा गुणा–भाग करके हमको बता दीजिए कि 90 हजार लोगों को 5 डिसमिल के हिसाब से कितनी जमीन हुई और इन्होंने जमीन का जो आंकड़ा दिया है वह मात्र 52 एकड़ का आंकड़ा दिया है । महोदय, यह किस तरह का झूठ है, बिहार के लोगों को किस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है ।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह ।

श्री सत्यदेव रामः उपाध्यक्ष महोदय, अब बताइये कि यह अपना आंकड़ा खुद नहीं संभालकर देते हैं और क्या ये बिहार के लोगों को मूर्ख समझ लिये हैं ।

उपाध्यक्षः समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह जी ।

श्री सत्यदेव रामः उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट और रुक जाइये ।

श्री अजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा विभाग के अनुदान के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जो शिक्षा की स्थिति है वह आइने की तरह दिखाई पड़ती है । सरकार ने यह फैसला लिया था कि बिहार के सभी बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन कराने के लिए उनके वार्ड और उनके मोहल्ले में हम स्कूल का निर्माण, प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करेंगे और उस फैसले के आधार पर सरकार ने स्कूल का निर्माण भी कराया था लेकिन उसके बाद न जाने सरकार के मन में फिर कैसे परिवर्तन हुआ कि फैसला ले लिया कि जिस नवसृजित विद्यालय के पास भवन नहीं है, जमीन नहीं है हम उसको डिमोलिस कर देंगे दूसरे स्कूल में दो किलोमीटर, एक किलोमीटर दूर उसको हम शिफ्ट कर देंगे तो कैसे सभी बच्चों का नामांकन हो सकता है । सरकार आज कटघरे में खड़ी है जो फैसला किया था खुद अपने फैसले के खिलाफ सरकार ने फैसला लिया है । इसलिए आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं, दूसरी बात आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि आपने स्कूल जो लगभग 28–29 सौ हाईस्कूल जो इस बिहार के अंदर थे आज उसके भवन की क्या हालत है ? कभी जाकर पता लगाने की कोशिश सरकार ने की ? मैं दावे के साथ कह रहा हूं समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर के समरथा हाईस्कूल में कम से कम

एक दर्जन जिलों के बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते थे यह गौरव था उस स्कूल के पास लेकिन आज उस विद्यालय के पास भवन नहीं है । जो भवन है भी वह किसी भी समय गिर जायेगा और जब गिर जायेगा सैकड़ों बच्चे उसमें मारे जायेंगे । कौन होगा इसका जवाबदेह ? हम आपसे कहना चाहते हैं आज भवन सिर्फ समरथा स्कूल में नहीं है ऐसी बात नहीं है बल्कि विभूतिपुर के अंदर और बिहार के अंदर जो 28 सौ स्कूल पुराने हैं उसमें करीब 14 सौ स्कूल के पास आज भवन नहीं है । जब भवन नहीं है तो बच्चे कहां पढ़ेंगे ? स्कूल में शिक्षकों की कमी है । आपने प्रोन्नति कर दिया रातोंरात, चुनाव का समय था आपने तीन हजार स्कूल को, मध्य विद्यालय को आपने हाईस्कूल में उत्क्रमित कर दिया लेकिन उसके पास जमीन नहीं, उसके पास भवन नहीं, उसके पास शिक्षक नहीं वहां पर आप फॉर्म भरवाते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि एक नहीं दर्जनों स्कूल ऐसे हैं समस्तीपुर जिला में जहां एक भी शिक्षक नहीं है । फॉर्म भराता है, परीक्षाएं होती हैं, लड़के पास करते हैं कैसे पास कर रहे हैं बिना शिक्षक के ? पढ़ाना चाहते हैं तो कैसी शिक्षा आप देना चाहते हैं ? शिक्षा में अगर आप सुधार की बात करना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा । आज इंटर स्कूल की क्या हालत है ? हमलोग प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष हैं, स्कूल में जाते हैं और जब जांच करने के लिए कहते हैं कि प्रयोगशाला की तरफ चलो, हेडमास्टर ले जाता है प्रयोगशाला पर एक-एक इंच मिट्टी, धूल-कण जमा हुआ है । कभी प्रैक्टिकल नहीं चलता, प्रैक्टिकल में कोई टीचर नहीं है, टेक्निशियन नहीं है और जब प्रैक्टिकल नहीं है तो कैसे आप प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन लेते हैं । शिक्षा मंत्री अभी नहीं हैं...

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए ।

श्री अजय कुमार : महोदय, हमारा टाइम दो मिनट है, दो मिनट अभी नहीं हुआ है । हम आपसे कहते हैं नामांकन की समस्या है । आज नामांकन की इतनी बड़ी समस्या है कि जितने बच्चे मैट्रिक पास करते हैं उन सभी बच्चों का एडमिशन इंटर में नहीं होता है । जो इंटर पास करते हैं दर-दर की ठकरें खाते हैं स्नातक में एडमिशन के लिए उनका एडमिशन नहीं होता है और आप शिक्षा की जो बहुत दुहाई दे रहे हैं ये नहीं हो सकता है । महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बिहार के अंदर विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार है किसी से छुपा हुआ है ? आप तो सभापति महोदय मिथिला विश्वविद्यालय आपके अंतर्गत आता है, आपका जिला भी उसी में है इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है । अभी वहां के छात्र आंदोलन कर रहे हैं वहां पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है । वहां

परीक्षा के नाम पर आठ करोड़ रुपया बनारस की एक एजेंसी को भेज दिया गया । कोई लेखा-जोखा नहीं है विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं हो सकता है सरकार लाठी चलाकर उसको हटा दे । हम एक लाईन कहकर अपनी बात को..

उपाध्यक्ष :माननीय सदस्य सूर्यकांत पासवान जी ।

श्री अजय कुमार : एक लाइन में खत्म करना चाहते हैं कि हाईस्कूल के पास जो जमीन है वह सरकार की है, क्या सरकार उसका सीमांकन कराकर उसको डायट कराने का फैसला लेना चाहती है कि नहीं ? भू-स्वामी सब वहां कब्जा किए हुए है ...

उपाध्यक्ष :समाप्त कीजिए ।

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, सरकार भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है मगर आज बिहार के विश्वविद्यालय भी भ्रष्टाचार में आकंठ डुबे हुए हैं । महोदय, सब तरह का घोटाला तो सुने हैं लेकिन आज विश्वविद्यालय में कागज घोटाला भी उजागर हुआ है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष :बैठिए, अभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं । बैठ जाइये ।

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में राज्य के सभी स्कूलों के छात्र और छात्राओं को स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा देने का फैसला लिया था मगर यह फैसला सरजमीं तक नहीं पहुंचा है । महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र में अपना फैसला लागू करे । महोदय, बिहार में युवाओं का हाल बदहाल है । बी0एस0सी0सी0 की वर्षों से लंबित बहाली की प्रक्रिया सात वर्षों से संपन्न नहीं हो पायी है और सरकार युवओं को 19 लाख रोजगार देने की झूठी बात कर रही है । महोदय, सरकार ने पिछले दिनों बखरी में डिग्री कॉलेज खोलने की बात की थी लेकिन आज वह डिग्री कॉलेज पदाधिकारियों की भेंट चढ़ गया है । महोदय, स्वास्थ्य की बात करें तो बखरी विधान सभा के अंदर एक पी0एच0सी0, बखरी है जिसको असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गयी और आज वह पी0एच0सी0 बंद है । महोदय, मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उस पी0एच0सी0 को पुनः

चालू किया जाय । वहां के जो हमारी गरीब-गुरबा महिलाएं प्रसव के लिए कोसो दूर 30-40 किलोमीटर बेगूसराय जाना पड़ता है । इसलिए महोदय, उस पी0एच0सी0 को अविलंब चालू करवाया जाय और जो दोषी लोग हैं जो उस कार्रवाई में संलिप्त हैं महोदय उन पर कार्रवाई हो । निर्दोष लोगों को जिनको वहां का प्रशासन झूठे मुकदमे में फंसाने का काम कर रहा है मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच हो...

उपाध्यक्ष :माननीय सदस्य समय हो गया अब समाप्त कीजिए ।

श्री सुर्यकांत पासवान : और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई न हो ।

उपाध्यक्ष :अब समाप्त कीजिए ।

श्री सुर्यकांत पासवान : ठीक है महोदय । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष :माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह । पांच मिनट समय है आपका ।

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हुआ हूं । चर्चाएं बहुत हुई चाहे वह बजट किसी का हो, शिक्षा का हो, कृषि का हो जिसका भी बजट हो जब वह अपने निर्धारित लक्ष्य से विचलित हो जाता है तब नीति आयोग मापदंड तय करता है कि बिहार पिछड़ा है । अभी हमारे जेडीयू के मित्र ने कहा कि जब मैं 1980 में पटना साइंस कालेज में था और जब यहां से रामयस कॉलेज गया तो लोगों ने कहा कि इतने प्रतिष्ठित कॉलेज से आप यहां क्यों आये ।

-क्रमशः-

टर्न-24/यानपति/02.12.2021

क्रमशः.....

श्री अजय कुमार सिंहः हमलोग भी भागलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे और उस विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष महोदय, एशिया के मानक साइंटिस्ट के रूप में डॉ0 दत्ता मुंशी जी थे और

पटना विश्वविद्यालय में बॉटनी विभाग में डॉ0 रामपरीक्षण राय जी थे और उस समय जब रिसर्च का काम होता था तो राष्ट्रीय जर्नल के अलावे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी उसके पत्र छपा करते थे कभी-कभी मेरा भी एक छपा है उसमें । तो जब हम इसके तह तक जायेंगे कि नीति आयोग हमें अपने मानदंड में क्यों नीचे रखे हुए है जब यह तय कर लेंगे कि हम इसमें कैसे ऊपर जाएंगे तो लक्ष्य जो है शिक्षा के बजट का वह पूरा हो सकता है । अभी माननीय सत्यदेव राम जी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी है कि जितने पदाधिकारी हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ा करें । महोदय, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि स्कूल के प्राइमरी विद्यालय हों, माध्यमिक विद्यालय हो, हायर एजुकेशन हो वहां के शिक्षक भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं । जब वहां के शिक्षकों को अपने बच्चों को उस सरकारी स्कूल में पढ़ाने पर भरोसा नहीं है तो आमजन की क्या दशा होगी । एक जमाने में अभिभावक बच्चों को स्कूल में डालकर निश्चिन्त हो जाता था अभिभावक कि हमारा बच्चा दिग्भ्रमित नहीं होगा हायर एजुकेशन में अपने बच्चों को पढ़ाने में गार्जियन निश्चिन्त हो जाता था कि हमारा बच्चा दिग्भ्रमित नहीं होगा जबतक ऐसा इंतजाम हमारे शिक्षण संस्थानों में नहीं होगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं अशोक राजपथ पर नावेल्टी की दुकान पर मैं यू0जी0सी0 नेट के लिए अंग्रेजी की एक टेक्स्ट बुक खरीदने गया था उसने कहा कि अब कॉलेज में टेक्स्ट बुक से पढ़ायी नहीं होती, पासपोर्ट से पढ़ायी होती है तो जब पासपोर्ट से पढ़ायी होगी पटना यूनिवर्सिटी जैसे सम्मानित विश्वविद्यालय में तो अब इससे अधिक कहा नहीं जा सकता । महोदय, दूसरी ओर जो ज्वलंत समस्या है कृषि के संबंध में आज इसी सदन में माननीय कृषि मंत्री जी कुछ कह रहे थे, इस पर प्रकाश डालना जरूरी है कि इस सूबे में कृषि का रोड मैप है और 2012-13 में यह व्यवस्था की गयी थी कि हमारे यहां जो भी कृषि विश्वविद्यालय हैं यहां बीज का उत्पादन होगा और उस बीज को नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में दिया जाएगा लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिखायी नहीं देता है । महोदय, आई0सी0ए0आर0 के द्वारा जो नार्थ-ईस्ट रीजन के लिए जो रिकमेन्डेड सीड हैं इसके अलावे भी जबलपुर हो, कटक हो, हैदराबाद हो वहां के बीज भी यहां के विश्वविद्यालयों में, एक बार तो मैंने ही दिया था ट्रायल करने के लिए जबलपुर विश्वविद्यालय का बीज लेकिन यहां कुछ किया नहीं जा रहा है तो बीज की जो स्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां मैं एक आवेदन लेकर गया था मैंने कहा कि गेहूं बिहार सूबे में पकता नहीं है सूख जाता है, इसलिए यहां कम दिन के प्रभेद के बीज की उपलब्धता इस प्रदेश में होनी चाहिए । महोदय.....

उपाध्यक्षः अब समाप्त कीजिए माननीय सदस्य ।

श्री अजय कुमार सिंहः महोदय, जहांतक खाद का सवाल है विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कहते हैं कि समेकित खाद का प्रबंधन होना चाहिए चाहे वह स्फूर हो, म्यूरेक और पोटास हो, यूरिया हो जो मेजर एलिमेंट है लेकिन खाद की उपलब्धता पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि खाद की उपलब्धता कम है, केंद्र से ही कम आ रही है । दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने कहा कि 266 रु0 में यूरिया मिलता है मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं मैं मुंगेर जिले से हूं और हमारा रेक प्वायंट नौगछिया है, हमारा रेक प्वायंट बेगूसराय है, हमारा रेक प्वायंट जमुई है अगर मुंगेर का होलसेलर वहां से उठाता है तो कंपनी वाला वहां उसे उस रेट में देता है तो इसके बीच का जो कैरेज कॉस्ट है इसके बारे में मंत्री जी संज्ञान लेना चाहेंगे ।

उपाध्यक्षः समाप्त कीजिए ।

श्री अजय कुमार सिंहः महोदय, एक लाईन और मैं कहना चाहता हूं ग्रामीण विकास कार्य के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर मामला है । आर0सी0डी0 ने एक पत्र जारी किया कि 10 परसेंट से नीचे आप निविदा डाल सकते हैं जो स्थिति ग्रामीण सड़कों की है चूंकि नॉडल एजेंसी आर0सी0डी0 है उनके गाइडलाईन पर ग्रामीण कार्य विभाग को भी काम करना है तो उसमें 10 प्रतिशत की जगह 20-25 प्रतिशत.....

उपाध्यक्षः समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य श्री बच्चा पांडेय जी ।

श्री अजय कुमार सिंहः कम पर निविदा डाली जाती है जिससे गुणवत्ता खराब होती है तो जो लक्ष्य बजट में निर्धारित हो और गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो तो इसका ध्यान आसन के माध्यम से.....

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य श्री बच्चा पांडेय जी । माननीय सदस्य श्री संतोष कुमार मिश्रा ।

श्री बच्चा पांडेयः सभापति महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं । सभापति महोदय, जैसे कि हम जानते हैं और सुनते भी हैं कि शिक्षा का विद्या व मनुष्य के जीवन जीने का कला विकसित करता है और साथ ही शिक्षा के अभाव के कारण ही समाज में भ्रष्टाचार के फलने-फूलने का अवसर भी देती है । यह हमारा वही बिहार है जो पूरे हिंदुस्तान में लगभग 45 प्रतिशत आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 अकेले पैदा करता था परंतु बिहार के सरकारी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षा की अतिशीघ्र गिरावट के कारण सभी अधिकारियों, नौकरशाहों और शिक्षक अपने बच्चे को निजी विद्यालयों में पढ़ाने के बजाय पूर्व शिक्षा की बदौलत अकेले पूरे बिहार में, दुनिया में परचम लहरा चुका है । सभापति महोदय, जब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में

महाविद्यालयों, विद्यालयों को देखता हूं तो यह आभास होता है, सभापति महोदय, सरकारी विद्यालयों में दो प्रकार के शिक्षक होते हैं जिसमें एक वेतनमान और दूसरा जो है मानदेय पर दोनों शिक्षक अपने में पढ़ने-पढ़ाने को लेकर हमेशा विवाद करते रहते हैं और इसका शिकार बच्चे होते हैं । जबतक शिक्षक को वेतन विसंगति से दूर नहीं किया जायेगा तबतक विद्यालय में अक्सर युद्ध का अखारा बनता रहेगा और बच्चे का भविष्य चौपट होते रहेगा तथा बच्चे हीन भावना से ही ग्रसित रहेंगे । सभापति महोदय, भारत के मानचित्र पर जिस बिहार के अतीत गौरवशाली रहा हो, जिसके गौरव की गाथा दुनिया वैसे मानती हो आज शिक्षा की गिरावट के कारण बिहार, हमारा बिहार बीमारू बिहार बन गया है । आज की शिक्षा स्वयं नीति और इतनी दुर्भाग्यपूर्ण, भेदभावपूर्ण एवं अभिजात्य शिक्षा बन गई है जो हमेशा शर्मसार कर रही है । सभापति महोदय, अबतक बहेरी विधान सभा में विद्यालय की जहां नदियों के पानी को लोटे में समेटने का काम किया जाता है जैसे गंडक कॉलोनी उच्च विद्यालय तरवारे की बात लिया जाय विद्यालय में 10 प्लस टू हो चुका है किंतु पठन-पाठन के लिए कुल कमरे कितने हैं, मात्र पांच कमरे हैं । सभापति महोदय, विद्यालय में कुल 2975 छात्र-छात्राएं हैं जिनका दो सत्र में पठन-पाठन होता है । गौरतलब है कि एक सत्र में लगभग 1437 छात्र हैं । भला सोचिए सभापति महोदय क्या एक कमरे में 287 छात्र-छात्राएं बैठने का स्थान मिल सकता है ? यह कतयी उचित नहीं है, इस विद्यालय में चारदीवारी नहीं है जबकि पूर्व में ही 29 लाख रुपया विकास फंड का पड़ा हुआ है । वहां प्रबंधन समिति का भी गठन हो चुका है लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण विद्यालय में कोई विकास नहीं हो रहा है । सभापति महोदय, छात्र के अनुपात में शिक्षक का पद नहीं है । 40 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए जोकि अभीतक किसी विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था नहीं सुनिश्चित की गयी है ।

टर्न-25/अंजली/02.12.2021

...क्रमशः..

श्री बच्चा पाण्डेयः उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की यह दुर्दशा आखिर बिहार में क्यों है । कहीं-कहीं तो यही देखने को मिलता है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक और लिपि के एक ही स्थान पर आठ साल से दस साल से पदस्थापित हैं जो कि वह स्थानीय हैं और स्थानीय के चलते धौंस दिखाकर पठन-पाठन को बाधित करते हैं ।

उपाध्यक्षः अब आप बैठ जाइए । माननीय सदस्य, श्री अनिल कुमार जी ।

श्री अनिल कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं । इसके लिए मैं आपका और आदरणीय जनक बाबू का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता

हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के बिहारी को पूरे भारत एवं विश्व में पहचान दिलाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार शिक्षा के क्षेत्र में एक नई गाथा को लिख रहा है । आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक सेवा एवं विश्व के टॉप कंपनीज में करोड़ों के पैकेज पर काम करने वाले युवा का सपना साकार हुआ । कहीं न कहीं इसमें एन0डी0ए0 सरकार की अच्छी शिक्षा नीति के बदौलत ही संभव हो पाया है । शिक्षा से ही एक अच्छे भारत एवं संपन्न बिहार का निर्माण हो, इसके लिए एन0डी0ए0 की सरकार सतत प्रयासरत है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत वर्षों में बिहार में शिक्षा की उन्नति के लिए कई ठोस कार्य हुए, 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4 हजार 366 करोड़ रुपये था जो बढ़ कर के 2020-21 में 37 हजार 357 करोड़ रुपये हो गया । वर्तमान में बजट का बड़ा भाग लगभग 20 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है । 2005 में साढ़े 12 परसेंट बच्चे विद्यालय से बाहर थे जो वर्तमान में घटकर 1 परसेंट से भी कम रह गए, जिन्हें वित्तीय वर्ष में 2020-21 में न विशेष नामांकन अभियान चलाकर विद्यालय में नामांकन कराया गया है । महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत 2 लाख 78 हजार 538 वर्ग कक्ष एवं 15 हजार 791 प्राथमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है । 19 हजार 641 प्राथमिक विद्यालयों का मध्य विद्यालयों में भी उत्क्रमण किया गया है । राज्य के सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किये जाने वाले राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में शेष 3 हजार 304 अन आच्छादित पंचायतों में शैक्षिक सत्र 2020 और 2021 से 9वीं की पढ़ाई प्रारंभ कर दी गई है । डी0वी0टी0 के माध्यम से योजनाओं की राशि बच्चों को हस्तांतरण जैसे बालिका पोशाक योजना, किशोरी स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, प्री-मैट्रिक, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना इत्यादि का ट्रांसफर उनके खाते में 2 हजार 892.20 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है । महोदय, वित्तीय वर्ष में एवं आने वाले वित्तीय वर्ष में शिक्षा विभाग की प्राथमिकताएं जो तय की गई सरकार के द्वारा, उसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को जारी रखा जायेगा । उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इंटर उत्तीर्ण अविवाहित बालिकाओं को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये एवं स्नातक उत्तीर्ण महिलाओं को 25 हजार की राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये की जायेगी । शैक्षणिक सत्र 2021-22 तक सभी मध्य एवं माध्यमिक उच्च विद्यालयों में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक, प्राचार्यों की नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जाएगी । सभी छात्र-छात्राओं को भारतीय संविधान, नियमावली,

धारा एवं अनुच्छेद से संबंधित प्रावधान की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी । गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्यक्रम सरकार चलाएगी । वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा के लिए 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । महोदय, महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत हर आयु के लोगों को साक्षरता प्रदान किया जा रहा है । संस्कृत के शिक्षा स्तर को भी बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है । बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना के अंतर्गत प्रस्वीकृत 429 एवं 223 कोटि के अनुदानित विद्यालयों की संख्या 531 की गई है । अंत में संपूर्ण बिहारवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी को बिहार में वर्ल्ड क्लास शिक्षा नीति लागू करने की अपेक्षा रखते हुए शुभकामनाएं देना चाहता हूं । इसके अलावा, मैं दो चीजें और अपनी तरफ से रखना चाहता हूं । माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि ओपन टेंडर कराकर के विद्यालय के बांउड्री और चहारदिवारी का निर्माण कराया जाय क्योंकि बहुत ही विद्यालयों में अतिक्रमण रहता है इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, इस पर ध्यान दिया जाय । इसके अलावा महोदय, बहुत दिनों से, बहुत सारे शिक्षक करीब-करीब आठ-आठ सालों से एक ही स्कूल में जमे पड़े हुए हैं, वे उस स्कूल में रह कर के आम जनता के साथ मिलकर, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के राजनीति करते रहते हैं उससे कई लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए उनका स्थानांतरण किया जाय । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री संतोष कुमार मिश्र जी ।

श्री संतोष कुमार मिश्र: बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय । आदरणीय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के अंतर्गत शिक्षा विभाग के तहत जो कटौती प्रस्ताव विपक्ष ने सदन के समक्ष रखा है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं । बाकी अन्य विभागों के जो गिलोटीन द्वारा मांग प्रस्तुत की गई है उन पर भी कुछ बातों को मैं आपके समक्ष रखूंगा, परंतु शिक्षा जो कि ऐसा क्षेत्र है, किसी भी देश या प्रदेश के विकास हेतु शिक्षा एक ऐसा मानक है और शिक्षा में भी खासतौर से प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा, अगर हमारी प्रारंभिक जड़ें ही मजबूत नहीं रहेंगी, हमारी माध्यमिक जड़ें ही मजबूत नहीं रहेंगी तो हम उच्च शिक्षा की बातें कहां ले जाएंगे । बिहार में अगर देखा जाय तो जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांचवीं सदी में हमारे बिहार में कई सारे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशीला विश्वविद्यालय और उसके तहत बिहार की धरती को ज्ञान की धरती कहा गया । बुद्ध,

महावीर जैसे महान संतों ने यहां ज्ञान पाया लेकिन उसके उत्तरार्द्ध में आगे अगर चला जाय तो हुआ ऐसा कि कुछ बर्बर शासकों द्वारा जो इनविजन हुआ बिहार में उसके तहत अगर देखा जाय तो इन विश्वविद्यालयों को तहस-नहस कर दिया गया, उसके बाद भी अगर शिक्षा की स्थिति बिहार में देखी जाय तो आज के परिवेश में क्रमशः दयनीय ही रही है पिछले 16 वर्षों के शासन काल में । जो यह आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो सरकार चल रही है, अगर उस पर हम चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से अगर देखा जाय तो प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की जो स्थिति है बद से बद्तर स्थिति में है । पता नहीं क्यों सरकार प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि अगर हम प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा ही नहीं प्रदान कर सकते हैं तो कैसे हम यह कल्पना कर सकते हैं, कैसे हम यह परिकल्पना कर सकते हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर इंजीनियर, डॉक्टर, एम0बी0ए0, प्रोफेशनल, आई0ए0एस0 या आई0पी0एस0 बनेंगे । कैसे हम एक बेहतर समाज का अपने प्रदेश में निर्माण कर सकते हैं और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं इस प्रदेश में चल रही हैं, शराबबंदी जिसको लेकर कि सरकार इतनी सजग होना चाहती है, कानून आया हम सब ने संकल्प लिया, अगर हमारे पास शिक्षा ही नहीं रहेगी, हमारे बच्चे शिक्षित ही नहीं होंगे तो इस कानून को शराबबंदी कानून को आप कैसे लागू करा पाएंगे यह सोचने की बात है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं बिहार की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है वह 69.83 प्रतिशत है ।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री संतोष कुमार मिश्रः दो-चार बातें कहकर, मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं महोदय, 69.83 प्रतिशत है जो कि करीब-करीब 7 प्रतिशत नेशनल एवरेज से कम है, राष्ट्रीय औसत 77.7 प्रतिशत है और उसमें भी महिलाएं जो हैं बिहार की और खासतौर से रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वे काफी ही पीछे हैं इस शिक्षा के, साक्षरता के क्षेत्र में । नीति आयोग ने पहले ही, जैसा कि मेंशन किया गया है कि नीति आयोग का जो स्कूल एजुकेशन कोशन इंडेक्स जो होता है, ई0क्यू0आई0 जो होता है स्कूल एजुकेशन का कोशन इंडेक्स जो है वह मात्र 40 परसेंट है बिहार में, इसका मतलब कि उन्होंने कहा है नीति आयोग ने कि बिहार इस मामले में फिसड्डी है । कुछ रिपोर्ट आप देखेंगे महोदय, बुनियादी ढांचों की, क्यों यह व्यवस्थाएं हम लागू नहीं कर पा रहे हैं इतना खर्च करने के बाद भी 38 हजार करोड़ का इस बार का बजट है । 7744,01,72,000/- (सात हजार सात सौ चौवालीस करोड़ एक लाख बहत्तर हजार रुपये) अनुपूरक मांगा जा रहा है

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

लेकिन जहां तक देखा जाय अगर ये सारी मांगे सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाय तो कहीं वेतन मद में जा रहा है या किसी अन्य मद में, शिक्षकों के वेतन मद में, बकाया वेतन मद में, शिक्षकों को या विश्वविद्यालयों को दिया जा रहा है । प्राथमिक विद्यालयों को,

...क्रमशः...

टर्न-26/सत्येन्द्र/02-12-2021

श्री संतोष कुमार मिश्रः(क्रमशः) प्राथमिक विद्यालयों को, मध्य विद्यालयों को विकसित करने के लिए उनके भवन का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, लाइब्रेरी के निर्माण में या अन्य पीने के पानी मुहैय्या करने के संदर्भ में अगर देखा जाय तो यह राशि वहां नहीं खर्च की जा रही है । महोदय, सरकार की प्रतिबद्धता बुनियादी ढांचे को शिक्षा का जो बुनियादी ढ़ांचा है और खासकर के जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है ,उसके बुनियादी ढ़ाचे को मजबूत करने के लिए सरकार को कदम आगे बढ़ाना चाहिए । मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, अगर देखा जाय तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट हैं जिसको यहां पर मैं साझा करना चाहता हूँ । महोदय, सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है- स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो पिछले एक साल से कोरोना की मार हो या अन्य कोई भी बात हो मात्र तीन प्रतिशत ही ऐसे जो गरीब लाचार हमारे छात्र हैं उनको इसका लाभ मिल पाया है।

अध्यक्षः अब बैठ जाईए ।

श्री संतोष कुमार मिश्रः एक बात और कहना चाहता हूँ माननीय कृषि मंत्री यहां उपस्थित है । रोहतास जिले में खाद की किल्लत बहुत ही ज्यादा है । माननीय कृषि मंत्री जी डी0ए0पी0 की उपलब्धता गेहूं की बुआई के लिए बहुत ही जरूरी है। आज हमने सदन में भी यह मामला उठाया है, मात्र 2200 एम0टी0 रोहतास जिले में अभी तक प्राप्त हुआ है जबकि 15 हजार से ज्यादा एम0टी0 की जरूरत है। अगर आप प्रयास करेंगे और जो कम्पनियां है फर्टिलाईजर की, उनसे आप बात करेंगे तो वे रेक लगायेंगे जरूर, मेरी भी बात हुई है उन कम्पनियों से आप अगर.....

अध्यक्षः अब बैठ जाईए माननीय सदस्य।

श्री संतोष कुमार मिश्रः अगर प्राथमिकता के तौर पर आप विचार करेंगे तो जो 21 प्रतिशत डी0ए0पी0 आजतक बिहार को मिला है आप चाहें तो केन्द्र से अपना एलोकेशन बढ़वा लें....

अध्यक्षः अब सरकार का उत्तर । माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन सरकार द्वारा पेश द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर विमर्श कर रहा है । परम्परानुसार व्यय विवरणी के सभी मांगों पर विमर्श करना संभव नहीं हो पाता है इसलिए एक किसी विभाग के मांग पर विमर्श होता है और उसके लिए आपने सरकार की अनुशंसा पर शिक्षा विभाग का चयन किया है इसके लिए मैं विभाग की तरफ से आपको आसन के प्रति और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ । महोदय, यह लाजिमी भी था कि एक तो अनुपूरक व्यय विवरणी में सबसे अधिक मांग भी शिक्षा विभाग की ही थी और दूसरी बात जो अभी इतने लंबे समय तक लगभग ढ़ाई घंटे से विमर्श चल रहा है और लगभग हमारे 19 साथियों ने इस पर विचार रखे हैं, सभी की बातों से एक चीज जो निर्विवाद रूप से निकल कर आयी है वह है शिक्षा के महत्व के बारे में या शिक्षा विभाग के कार्य के बारे में । महोदय, शिक्षा के बिना किसी सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और कहीं भी किसी भी समाज और देश या राष्ट्र किसी के विकास की रीढ़ या आधार शिक्षा ही होता है । स्वाभाविक रूप से मुझे प्रसन्नता हुई कि शिक्षा विभाग की मांग पर लगभग 19 या अधिक सदस्यों ने रूचि दिखाई और उन सभी सदस्यों के प्रति मैं विभाग की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने विचार विभाग के लिए जो हमने द्वितीय अनूपूरक के माध्यम से शिक्षा विभाग के लिए मांग की, जो राशि पेश की थी उस पर अपने अपने विचार रखे हैं इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ । महोदय, दोनों तरह के विचार आये हैं, सरकार के काम के बारे में भी और विभाग के क्रियाकलाप के बारे में भी और तरह तरह के विचार भी आये हैं । हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने जहां सरकार की उपलब्धियां भी गिनायीं हैं, वहीं हमारे विपक्ष के साथियों ने भी बहुत सारे सुझाव भी दिये हैं और बहुत सारी कमियां भी गिनायीं है तो सबसे पहले तो हम चाहे सत्ता पक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने या विपक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं, सरकार के कार्यशैली में कुछ ..

श्री ललित कुमार यादव: सुझाव दिये गये हैं तो उस पर बोलिये, केवल भूमिका से काम नहीं चलेगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: जल्दी जाना नहीं न है ?

(व्यवधान)

हमारी चिंता दूसरी है कि अगर आपको जल्दी बाहर जाना होगा तो अध्यक्ष महोदय, हमारी चिंता है कि हमें दोनों तरह की बात बतानी है, सरकार की उपलब्धियां भी बतानी है और जो आपने बातें कहीं हैं उसकी भी हकीकत सच्चाई खोलकर रखनी है, वह भी बतायेंगे ।

अगर आपको जाने की जल्दी है तो कहिये हम आपकी ही वाली बात पहले कर लेंगे लेकिन हमको डर है कि कहीं ..

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप इनको बताने दीजिये, बैठ जाईए न ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, ये चले जायेंगे तब फिर इनकी वाली बात कहने का असर और उसकी रूचि खत्म हो जाती है । चूंकि आपने जो बातें कहीं है उसके संबंध में तो हकीकत बतानी होगी, आपने जो कहा है और जो सच्चाई है महोदय, शिक्षा की अहमियत जैसा कि हमने कहा कि सब लोग मानते हैं इसको और जो हमारी पिछली सरकार के समय में जो उपलब्धियां हैं उसको भी हम समझते हैं गिनाने की अब आवश्यकता नहीं है और सब लोग उसको महसूस करते हैं । महोदय, 2005 के बाद से जो हमने काम शुरू किया है और देखिये हम बोल रहे हैं तो ललित जी बात कर रहे हैं और महोदय आपने जो कहा है, हम समझते हैं कि यह आपकी राजनीतिक विवशता है जिसे हम समझते हैं इसलिए आपने कुछ अगर सरकार के खिलाफ बोल दिया है तो हम उसको उसी भाव से ग्रहण करते हैं । ऐसा थोड़े हम मानते हैं कि आप सरकार के खिलाफ हैं। महोदय अब हमको लगता है कि कहीं इनको हड़बड़ी होगी, कुछ बात की चर्चा इन्होंने की है इसलिए हम आप ही की बात शुरू करते हैं, आपने कहा था कि हम कहां से शुरू करें, आप हमारी बात सुनिये आपको लगेगा कि हम आपकी बात कितने ध्यान से सुन रहे थे । आपने शुरू में ही कहा कि आपको मुश्किल हो रही है कि आप कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें, याद होगा आपका यह पहला लाईन था।

(व्यवधान)

महोदय, अब हम इनकी बात छोड़ देंगे और हम अपनी बात करनी शुरू कर देंगे । महोदय, वर्ष 2005 के बाद से हमलोगों ने जो इस सूबे में रोशनी जगाने का काम किया है उस रोशनी से आज आपका इलाका भी जगमगा रहा है और उस रोशनी में आपके बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने जो समावेशी शिक्षा है, भूदेव चौधरी जी बात कर रहे थे गरीबों के बच्चों के संबंध में, आपको पता होगा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता जो है, कुछ लोग गुणवत्ता की बात कर रहे थे हमारी सरकार की प्राथमिकता उन दोनों में है । पहले चरण में शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्राथमिकता थी (क्रमशः)

टर्न–27/मधुप/02.12.2021

...क्रमशः...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं, जिसमें भूदेव चौधरी जी जो बात कह रहे थे कि गरीबों के बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, हमलोगों ने उसकी व्यवस्था की और यह हमलोगों की नीतियों, हमलोगों के कार्यक्रमों और उसकी सफलता का ही परिणाम है कि जो 2005 में इनके समय में स्कूल से बाहर छूटे बच्चों का प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, आज 0.5 से भी नीचे प्रतिशत हो गया है । यह हमारी उपलब्धि है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । शांति से सुनिये । अभी बहुत टाइम है, अभी सुनिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उस रिपोर्ट पर भी आ रहे हैं । हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद ही हमलोगों ने शिक्षा के अधिकार का कानून बनाया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी इस तरह से आपकी कोई बात नहीं जायेगी । अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उसके तहत हमने फैसला किया कि प्रत्येक कि0मी0 में एक प्राथमिक विद्यालय, 3 कि0मी0 में मध्य विद्यालय और 5 कि0मी0 से अधिक दूरी रहने पर 5 कि0मी0 के अंदर एक माध्यमिक विद्यालय और बात यहीं नहीं रूकी । महोदय, बात इससे भी आगे गई और आज यह हम बड़े फख्र से कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि आज नीतीश सरकार ने यह एलान करके लागू कर दिया कि हर पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हो चुकी है । महोदय, हम तो कहते हैं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : धैर्य से सुनिये महबूब जी, बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : जो माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है, मैं आपकी चिन्ता से इत्तेफाक रखता हूँ इस मायने में और हम स्वीकार करते हैं कि अभी हमारे सारे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भवन और शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था हम नहीं कर पाये हैं । यह स्वाभाविक है । एक साथ 5 हजार, आप अपने समय में पता है कि कितना माध्यमिक विद्यालय खुला ? हमलोगों ने 5300 उच्च माध्यमिक विद्यालय एक साथ पंचायतों में खोल दिया । यह हमारी उपलब्धि है और आप पूछ रहे थे कि क्या किये हैं। अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी ललित जी पूछ रहे थे कि आपके समय में क्या हुआ है तो हम इनको बता देते हैं, खाली धीरज से सुनियेगा कि आपके समय में क्या था और हमारे समय में क्या हो गया ।

(व्यवधान)

नीति आयोग पर भी बोलेंगे । आप धैर्य रखिये, बोलकर उधर मत घूमिये । आप इधर देखिये, धैर्य से रहिये । उसपर भी बोलेंगे ।

प्राईमरी विद्यालयों की संख्या ललित जी, आपके समय में मात्र 37 हजार थी जो हमारे समय में बढ़कर 40 हजार से भी अधिक हो गई, यह हम आपको बताना चाहते हैं । महोदय, अब मध्य विद्यालय का सुनिये कि आपके समय में मात्र 13.5 हजार मध्य विद्यालय थे और आज की तिथि में 29 हजार से अधिक मध्य विद्यालय हैं । ये विद्यालय हमने खोला है । आप बार-बार पूछ रहे थे । महोदय, अब हम बताना चाहते हैं टीचर के बारे में ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर राजद, कांग्रेस, भा0क0पा0(मा0ले0), मा0क0पा0, भा0क0पा0 सहित विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से वाक-आऊट किया गया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शिक्षा के प्रति गम्भीर होना चाहिए । गम्भीरता से सुननी चाहिये । माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, एक चीज इनको जाते-जाते हम सुना देना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि इनके समय में स्कूलों में शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा की गई थी, अभी ललित जी बोल रहे थे । बात वे सही कह रहे हैं लेकिन किस परिस्थिति में बहाली हुई थी, कैसे लोगों के द्वारा बहाली हुई थी और उस समय कैसे बिहार लोक सेवा आयोग चलता था, यह सिर्फ एक बात से स्पष्ट हो जायेगा कि इनके समय में चार बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाये गये थे और चार में से एक जिनकी सबसे बेहतर स्थिति रही वे निलम्बित हुये, नहीं तो बाकी तीन जेल चले गये भ्रष्टाचार के आरोप में । यह इनके समय में बिहार लोक सेवा आयोग की स्थिति थी कि चार बनाये, तीन जेल गये उसमें से, एक जिनकी सबसे अच्छी स्थिति रही, वे निलम्बित रहे और उसी आयोग के द्वारा शिक्षकों की बहाली करके ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे । हमलोगों ने तो शिक्षकों की बहाली इतनी पारदर्शिता से की है और मुझे सरकार की तरफ

से बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि इसी सदन को हमने पिछले दिनों विश्वास दिलाया था कि शिक्षकों की नियुक्तियां जो न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण बाधित थी, हमने विभाग की तरफ से सदन को आश्वस्त किया था कि हमलोग विभाग की तरफ से पूरी सक्रियता से न्यायालय से अनुमति/इजाजत की माँग करेंगे और जैसे ही इजाजत मिलेगी हम उनमें नियुक्तियाँ तुरंत करेंगे । आज महोदय, मुझे खुशी है कि हमलोगों ने सक्रिय होकर, बार-बार उल्लेख करके माननीय उच्च न्यायालय से नियुक्तियों की इजाजत पा ली है और हम नियुक्ति प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं । 90 हजार और 30 हजार, लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है जिसमें से लगभग 40 हजार की पूरी हो चुकी है । महोदय, पंचायत चुनाव के कारण हम फिर थोड़ा अटक से गये हैं । हालांकि इस चुनाव में भी हमने राज्य चुनाव आयोग से इजाजत माँगी थी कि आप हमें इजाजत दीजिये, हम इस हालत में भी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि हमलोगों ने ऐसी त्रुटि-रहित नियुक्ति की प्रक्रिया बनायी है कि कोई चाहकर भी उसमें हेराफेरी नहीं कर सकता है, इसलिये हमको इजाजत दीजिये, हमलोग आगे बढ़ेंगे, हमारे विद्यालय शिक्षकों के बिना सफर कर रहे हैं, पढ़ाई बाधित हो रही है लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि महीने दो महीने की बात है, रूक जाइये और हमें भी लगा कि जो हमारी नई नियमावली है, उसके हिसाब से जो चाहे पंचायत स्तर का हो, प्रखंड स्तर का हो या जिला स्तर का हो, जो हमारे नियुक्ति प्राधिकार हैं, उनके ही पदाधिकारियों से संबंधित चुनाव कार्य चल रहा है ।

...क्रमशः...

टर्न-28/आजाद/02.12.2021

..... क्रमशः .....

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : और इसी चुनाव से वो पदाधिकारी निर्वाचित हो कर आते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह प्रक्रिया बीच में रूक गई है और जैसे ही वह खत्म होगी, हमलोगों ने पूरे अपने अभ्यर्थियों को भी आश्वस्त किया है कि आप अकारण परेशान न हो क्योंकि हमने देखा है, कभी-कभी हो सकता है कि इन्हीं लोगों के बहकावे में, कुछ अभ्यर्थियों के ब्यान देखे हैं कि अब नियुक्ति पत्र के लिए धरना देंगे, शायद कुछ लोग बैठे भी हैं । हमें समझ में नहीं आता है कि हम जब ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से और पूरी मुस्तैदी से हम नियुक्ति की प्रक्रिया कर रहे हैं तो आखिर इस तरह की बात करने का क्या औचित्य है ? महोदय, आप भी जानते हैं कि पूरे प्रदेश में नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है । कुछ पंचायतों में प्रक्रिया पूरी हो गई है, कुछ पंचायतों में जॉच की

कार्रवाई चल रही है, कुछ पंचायतों में अभी पूरी नहीं हो पायी है । कई स्तर पर कई पंचायतों में यह मामला अलग-अलग स्तर पर रूका हुआ है और अगर अभी हम जहां नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई है, वहां उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे देते हैं तो जहां महीने-दो महीने बाद होगा, वो तीन महीना अकारण फिर पिछड़ जायेंगे, वे जूनियर हो जायेंगे, कनीय हो जायेंगे । फिर एक न्यायालय में मामला अटकेगा । जब एक साथ विज्ञापन निकला था, एक साथ नियुक्तियां होनी थी तो आपने ऐसी प्रक्रिया अपनायी कि किसी के साथ भेद-भाव हो गया । महोदय, इस कारण से इस स्थिति को टालने के लिए हमलोगों ने सब लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र देने का फैसला लिया है और आज हम सदन के माध्यम से और आसन के माध्यम से पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वे किसी बहकावे में नहीं आयें, किसी के उकसावे में नहीं आयें, क्योंकि सरकार नियुक्ति के प्रति पूरी गंभीरता से काम कर रही है और जैसे ही हमें इजाजत मिलेगी, जैसे ही समय आयेगा, हम नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे क्योंकि हमें भी चिन्ता है कि बिना शिक्षक के हमारे विद्यालय में पढ़ाई बाधित हो रही है। इसलिए हमने अपनी चिन्ता से ही इतना आगे बढ़कर के काम किया है और अभी दूसरा भी हमारे एक साथी बोल रहे थे कि आप अपने यहां शिक्षकों को चपरासी से कम तनख्वाह देते हैं । बिना किसी जानकारी के कैसे-कैसे आरोप लगाते हैं । अकारण शिक्षकों को उकसाते हैं, अकारण उन्हें हतोत्साहित करते हैं । आज आपके माध्यम से हम सारे सदस्यों को और पूरे बिहार के लोगों को बताना चाहते हैं कि जो हम शिक्षकों को वेतन दे रहे हैं, हमलोग जो अपने शिक्षकों को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, वो इस देश के कई दूसरे प्रदेशों से काफी अधिक है, यह हम इस सदन के माध्यम से अपने सभी शिक्षकों को और इस प्रदेश के लोगों को बताना चाहते हैं ।

महोदय, हम उदाहरण भी देना चाहते हैं कि इस तरह के शिक्षकों को आसाम में दिया जाता है मात्र 31 हजार, झारखंड में दिया जाता है 34 हजार और हम देते हैं दोनों जगह से अधिक 36 हजार, यह हम बिहार में देते हैं अपने शिक्षकों को । अपर प्राईमरी शिक्षक को आसाम में तो 33 हजार ही देते हैं, झारखंड में 35 हजार देते हैं और हम देते हैं 38 हजार । यह हम कई प्रदेशों से अधिक हमलोग अपने शिक्षकों को सम्मान भी देते हैं और शिक्षकों को तनख्वाह भी देते हैं और उनकी सेवा, शर्त्तों में हमलोगों ने जो समय-समय पर मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन और अनुशंसा पर जो परिवर्तन किये हैं । अब उनकी सेवा, शर्त्ते भी किसी दूसरे प्रदेशों से कमतर नहीं है बल्कि हर माने में दूसरे प्रदेशों से हमारे यहां के शिक्षकों की स्थिति बेहतर है, यह हम अपने सदन को बताना चाहते हैं।

अभी बात महोदय हो रही थी हमारे प्लस-2 स्कूल जो हमने किया है, अभी सारे माननीय सदस्य बता रहे थे और हमने खुद माना है कि एक साथ हम जब साढ़े पांच हजार करीब पंचायतों में उच्च विद्यालयों की स्थापना की है तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए शिक्षकों की या उसके लिए पर्याप्त भवन की आवश्यकता को पूरा करने में महोदय थोड़ा वक्त लगता है लेकिन वो भी हमलोगों ने उसकी व्यवस्था कर ली है और आप सबको मालूम है कि जैसा हमने कहा कि सवा लाख शिक्षक बहाल कर रहे हैं, उसमें 30 हजार से अधिक इन्हीं विद्यालयों के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है और हम समझते हैं कि शीघ्र ही उसका भी हमें वो मिल जायेगा, चुनाव खत्म हो रहा है, वो सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे । अभी महोदय, हमारे शारीरिक शिक्षा अनुदेशक जो थे, पता नहीं वे वर्षो-वर्ष से परेशान थे, उनके लिए पात्रता परीक्षा भी हो चुकी थी । लेकिन मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से उस दिशा में पहल करने की इजाजत दी और हमलोगों ने 8300 से अधिक पद जिसको फिजिकल टीचर्स कहते हैं, आपलोग भी दिन-रात कई माननीय सदस्य भी उस सिलसिले में बराबर आकर कहते थे कि उनके लिए भी कुछ करिए, वो पद सृजित हो गये हैं, उनकी पात्रता परीक्षा पहले ली जा चुकी है । वो उत्तीर्ण होकर के पहले से प्रतीक्षा में है महोदय । जैसे ही आचार संहिता और पंचायत के चुनाव का कार्य खत्म होता है वो भी रिक्तियां निकलेगी और वे आवेदन देंगे और सब नियुक्तियां उसमें भी महोदय हम कर पायेंगे । हमलोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में या नामांकन के क्षेत्र में अभी नामांकन की बात कर रहे थे । स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की बात कर रहे थे, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जो सात निश्चय-2 का स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, इस योजना की सफलता किसी दूसरे योजना से कहीं अधिक है, यह आप किसी ब्लॉक में सर्वे करके देख सकते हैं । हमलोगों के यहां अपने यहां भी है .....

श्री अख्तरूल ईमान : माननीय मंत्री जी, उर्दू शिक्षक के बारे में .....

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उर्दू की भी बात कर लेते हैं । उसके बारे में सिर्फ स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में बता दें कि आज आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि 1 लाख 35 हजार के करीब छात्र-छात्रायें स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ ले चुके हैं इस बिहार के लोग। लगभग 2 हजार करोड़ रू0 से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है । आप अख्तरूल ईमान जी बोल रहे थे उर्दू टीचर्स के बारे में और उर्दू प्रेम के बारे में । यह बात ठीक है कि आप उर्दू जानते हैं, उर्दू बोलते हैं, अच्छा करते भी हैं लेकिन हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों और उर्दू से जो प्रेम दिखाया है, वह बेमिसाल है, बिहार के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, यह इसकी गवाही आपका दिल देगा, आपका जमीर

देगा, आपका ईमान देगा । ये आप सोचकर रखिए । आप बताइए कि आज तक बहुत सरकारें आयी और गयी और उर्दू प्रेम में ....

(व्यवधान)

अगर हम आपके बात पर आ जायेंगे तो बात ही खतम हो जायेगी । अपनी बात कहकर ही न आपकी बात पर आयेंगे । महोदय, आज तक इतनी सरकारें आयी और गयी, आज तक अलीगढ़ विश्वविद्यालय का कहीं पर शाखा खुली बिहार छोड़कर के । पूरे देश में नहीं है जो बिहार में खुली है । (व्यवधान)

केरल में जाता है तो केरल में आप भी ज्यादा जाते हैं । केरल में जाने की बात नहीं है महोदय । जहां तक उर्दू की बात है, आप बताइए, जितना मदरसा को हमलोगों की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार में जितने मदरसों को मान्यता मिली है, जितना उनके तनख्वाह की सहुलियत दी गई है, आप बताइए चुनौती के साथ कहता हूँ किसी सरकार ने दिया हो या किसी सरकार ने ऐसा किया हो । चाहे मदरसा की बात है, इनके मदरसा में चाहे शिक्षकों को सुविधा देने की बात है ।

..... क्रमशः .....

टर्न–29/शंभु/02.12.21

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : क्रमशः महोदय, जो ये टी0इ0टी0 की बात कह रहे हैं उर्दू शिक्षकों की हमने उनके कागजात देखे हैं व्यक्तिगत रूप से लेकिन जो वे बोलते हैं उसकी बात नहीं कह पाये हैं । आप कागज लेकर आइयेगा, लेकिन आप आश्वस्त रहिये कि चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत को बढ़ावा देने की बात हो सरकार उर्दू और संस्कृत दोनों भाषाओं को बिहार में आगे बढ़ाने के लिए हर काम करेगी और देश में सबसे अच्छी पढ़ाई संस्कृत और उर्दू की व्यवस्था करेगी प्रदेश में यह हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं । आपको याद है न कि जो चले गये बहुत हमदर्द बनते हैं और सियासी गफलत का फायदा उठाकर आपलोग भी कातिलों को रहनुमा बना लेते हैं । महोदय, हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि ये वही हैं जो आप जिस टी0इ0टी0 और शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कह रहे हैं वे अपनी बात रखने के लिए सड़क पर निकले थे तो वो पिटाई की थी इनलोगों ने, वो पिटाई की थी कि आज तक वे लोग सड़क पर निकलना भूल गये, ये समझिये और ये लोग वही लोग हैं । इसलिए महोदय, हम पूरे सदन से अनुरोध करते हैं कि हमने जो मांग रखी है शिक्षा विभाग की तरफ से वह मांग सदन सर्वसम्मति से पारित करे क्योंकि हमें शिक्षा में और भी काम करने हैं । बिहार जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है अपने शिक्षण संस्थाओं से पूरे देश और दुनिया को रौशनी दिखायी है बिहार ने हम उस मुकाम

पर पहुंचना चाहते हैं । इसलिए हम सदन से अनुरोध करते हैं कि आप हमें अनुपूरक मांग की स्वीकृति दीजिए ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''इस शीर्षक की मांग 10/–रू0 से घटायी जाय।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं :

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या–2) अनिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या–3) अधिनियम, 2021 के उपखंडों के अतिरिक्त 7 हजार 7 सौ 44 करोड़ 1 लाख 72 हजार रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांग गिलोटिन के माध्यम से लिये जायेंगे ।

प्रश्न यह है कि :

''द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या–3) अधिनियम, 2021 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :–

माँग संख्या–01 कृषि विभाग के संबंध में **57,55,72,000**/–
(सत्तावन करोड़ पचपन लाख बहत्तर हजार) रूपये

माँग संख्या–02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में **81,000**/–
(इक्यासी हजार) रूपये

माँग संख्या–03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में **82,40,85,000**/–
(बयासी करोड़ चालीस लाख पचासी हजार) रूपये

माँग संख्या–04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में **1,31,95,000**/–
(एक करोड़ इकतीस लाख पंचानवे हजार) रूपये

माँग संख्या–09 सहकारिता विभाग के संबंध में **31,79,88,000**/–
(इकतीस करोड़ उनासी लाख अठ्ठासी हजार) रूपये

माँग संख्या–10 उर्जा विभाग के संबंध में **14,24,19,000**/–
(चौदह करोड़ चौबीस लाख उन्नीस हजार) रूपये

माँग संख्या–11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में **4,40,20,000**/–(चार करोड़ चालीस लाख बीस हजार) रूपये

माँग संख्या–15 पेंशन के संबंध में **2,19,14,000**/–
(दो करोड़ उन्नीस लाख चौदह हजार) रूपये

माँग संख्या–16 पंचायती राज विभाग के संबंध में **3174,71,95,000**/–
(तीन हजार एक सौ चौहत्तर करोड़ इकहत्तर लाख पंचानवे हजार) रूपये

माँग संख्या–17 वाणिज्य–कर विभाग के संबंध में **1,60,00,000**/–
(एक करोड़ साठ लाख) रूपये

माँग संख्या–18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में **45,34,00,000**/–
(पैंतालीस करोड़ चौंतीस लाख) रूपये

माँग संख्या–19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में **4,30,60,000**/–(चार करोड़ तीस लाख साठ हजार) रूपये

माँग संख्या–20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में **858,90,53,000**/–
(आठ सौ अठ्ठावन करोड़ नब्बे लाख तिरपन हजार) रूपये

माँग संख्या–22 गृह विभाग के संबंध में **464,68,74,000**/–
(चार सौ चौंसठ करोड़ अड़सठ लाख चौहत्तर हजार) रूपये

माँग संख्या–23 उद्योग विभाग के संबंध में **298,14,40,000**/–
(दो सौ अठानवे करोड़ चौदह लाख चालीस हजार) रूपये

माँग संख्या–26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में **3,17,62,000**/–
(तीन करोड़ सत्रह लाख बासठ हजार) रूपये

माँग संख्या–27 विधि विभाग के संबंध में **25,53,75,000**/–
(पचीस करोड़ तिरपन लाख पचहत्तर हजार) रूपये

माँग संख्या–29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में **21,84,000**/–
(इक्कीस लाख चौरासी हजार) रूपये

माँग संख्या–31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में **2,57,70,000**/–
(दो करोड़ सत्तावन लाख सत्तर हजार) रूपये

माँग संख्या–33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में **8,00,41,000**/–
(आठ करोड़ इकतालीस हजार) रूपये

माँग संख्या–35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में **65,12,000**/–
(पैंसठ लाख बारह हजार) रूपये

माँग संख्या–36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में **500,00,00,000**/– (पाँच सौ करोड़) रूपये

माँग संख्या–37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में **887,78,00,000**/– (आठ सौ सत्तासी करोड़ अठहत्तर लाख) रूपये

माँग संख्या–39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में **1182,34,01,000**/– (एक हजार एक सौ बयासी करोड़ चौतीस लाख एक हजार) रूपये

माँग संख्या–40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में **37,47,27,000**/– (सैंतीस करोड़ सैंतालीस लाख सत्ताईस हजार) रूपये

माँग संख्या–41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में **400,00,01,000**/– (चार सौ करोड़ एक हजार) रूपये

माँग संख्या–42 ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में **54,54,00,000**/– (चौवन करोड़ चौवन लाख) रूपये

माँग संख्या–43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में **14,02,12,000**/– (चौदह करोड़ दो लाख बारह हजार) रूपये

माँग संख्या–44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में **59,32,00,000**/–(उनसठ करोड़ बत्तीस लाख) रूपये

माँग संख्या–45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में **1,14,33,000**/– (एक करोड़ चौदह लाख तैंतीस हजार) रूपये

माँग संख्या–47 परिवहन विभाग के संबंध में **3,35,01,000**/– (तीन करोड़ पैंतीस लाख एक हजार) रूपये

माँग संख्या–48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में **2853,17,21,000**/–(दो हजार आठ सौ तिरपन करोड़ सत्रह लाख इक्कीस हजार) रूपये

माँग संख्या–49 जल संसाधन विभाग के संबंध में **1535,00,00,000**/– (एक हजार पाँच सौ पैंतीस करोड़) रूपये

माँग संख्या–51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में **165,23,99,000**/– (एक सौं पैंसठ करोड़ तेईस लाख निन्यानवे हजार) रूपये

से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
सभी माँगे स्वीकृत हुई ।

टर्न–30/पुलकित/02.12.2021

अध्यक्ष : अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

''बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2021''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक 29.11.2021 को उपस्थापित किया गया है। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में 20531,82,72,000/- (बीस हजार पांच सौ इकतीस करोड़ बयासी लाख बहत्तर हजार) रुपये की राशि प्रस्तावित की गयी है । इसमें वार्षिक स्कीम मद में 12120,83,41,000/- (बाहर हजार एक सौ बीस करोड़ तिरासी लाख इकतालीस हजार) रुपये स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में प्रवृत्त सहित 8373,52,04,000/- (आठ हजार तीन सौ तिहत्तर करोड़ बावन लाख चार हजार) रुपये एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 37,47,27,000/- (सैंतीस करोड़ सैंतालिस लाख सताईस हजार) रुपये प्रस्तावित है । अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 के संकट से बाहर आने एवं टीकाकरण की बेमिसाल उपब्धियों के कारण देश सहित राज्य में आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ है । इसके परिणामस्वरूप राज्य में योजनाओं का क्रियान्वयन तीव्र गति से हो रहा है । केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं एवं केन्द्रीय प्रक्षेत्र योजनाओं के लिए भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के विरूद्ध समानुपातिक राज्यांश राशि के लिए भी द्वितीय अनुपूरक में बजट का उपबन्ध किया जाना आवश्यक है । महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं यथा समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि में 5348 करोड़ (पांच हजार तीन सौ अड़तालिस करोड़) रुपये के अनुपूरक उपबन्ध का प्रस्ताव है । राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं यथा पेयजल हेतु गंगा जल उद्भव योजना एवं पटना मेट्रो रेल परियोजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, सात निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सृजन परियोजना आदि के लिए 6773 करोड़ (छह हजार सात सौ तिहत्तर करोड़) रुपये के अनुपूरक उपबन्ध का

प्रस्ताव है । महोदय, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के सहायतार्थ राज्य सरकार कृत संकल्प है । षष्ठम् राज्य वित्त राज्य के आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायतों को 2130 करोड़ (दो हजार एक सौ तीस करोड़) रुपये तथा नगर निकायों को 1445 करोड़ (एक हजार चार सौ पैंतालीस करोड़) रुपये के अनुपूरक का प्रस्ताव है । अध्यक्ष महोदय, राज्य में स्थानीय स्तर पर आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर-निकायों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए कुल 1170 करोड़ (एक हजार एक सौ सत्तर करोड़) रुपये का अनुपूरक प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार की अवधारणा है कि राज्य के संसाधनों पर आपदा पीड़ितों का हक पहले है इसलिए द्वितीय अनुपूरक बजट में इस हेतु 1182 करोड़ (एक हजार एक सौ बयासी करोड़) रुपये का अनुपूरक उपबन्ध प्रस्तावित है । अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद- 205 के अंतर्गत 20,05,31,82,72,000/- (बीस हजार पांच सौ इक्तीस करोड़, बयासी लाख बहत्तर लाख) रुपये द्वितीय अनुपूरक में राशि उपबन्धित करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । सदन से अनुरोध है कि द्वितीय अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए ध्वनिमत से पारित किया जाय ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनयोग (संख्या-4) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या- 113 है अगर सदन की सहमति हो तो उन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।